लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 25 फरवरी, 1969/6 फाल्गुन, 1890 (शक)

No. 7, Tuesday, February 25, 1969/Phalguna 6, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
151. डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई	Distiller's Trading Corporation Bombay ..	1—2
152. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on National Coal Development Corporation ..	2—7
153. राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन	Reports of National Development Council Working Groups ..	7—13
154. तम्बाकू बोर्ड	Tobacco Board ..	13—17
155. कच्चे पटसन का मूल्य	Prices of Raw Jute ..	17—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
156. ट्रैक्टर बनाने वाले नये कार-खाने	New Tractor Factories ..	21
157. मैसूर सीमेंट लिमिटेड	Mysore Cement Ltd.	21—22
158. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर	British India Corporation, Kanpur ..	22—23
159. पूर्वोत्तर रेलवे की रेलगाड़ियों में डकैती	Dacoities in Trains on N. E. Rly. ..	24
160. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को घाटा	Loss to Heavy Engineering Corporation Ranchi ..	25
161. लोहे और इस्पात के लिये पुंज मूल्य	Pool price for Iron and Steel ..	25—26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
162. नागपत्तनम् इस्पात बेलन मिलें	Nagapatnam Steel Rolling Mills ..	26
163. कम्पाला (उगांडा) में चाय उत्पादक देशों का सम्मेलन	Conference of Tea Producing Countries at Kampala (Uganda) ..	27
164. काफी उद्योग का विकास	Development of Coffee Industry ..	28
165. राज्य व्यापार निगम द्वारा रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of Silk Fabrics by State Trading Corporation ..	28—29
166. भारत का निर्यात तथा आयात व्यापार	India's Exports and Imports ..	29—30
167. व्यापार गृहों की आस्तियां	Assets of Business Houses	30—31
168. मलयेशिया में उद्योग	Industries in Malayasia ..	31
169. मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन	Conversion of Metre-Gauge lines into Broad Gauge ..	31—32
170. मिश्र की रूई का आयात	Import of Egyptian Cotton ..	32
171. कालीकट में लौह अयस्क के निक्षेप	Deposits of Iron Ore in Calicut ..	33
172. कच्ची ऊन की कमी	Shortage of Raw Wool	33
173. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production in Durgapur Steel Plant ..	34
174. मोटर गाड़ियों की कीमतों के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें	Tariff Commission's Recommendations on prices of Automobiles ..	34
175. डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों का अपने गन्तव्य स्थानों पर विलम्ब से पहुंचना	Late Running of Mail/Express Trains ..	34—35
176. उत्तर बंगाल में चाय उद्योग पर बाढ़ का प्रभाव	Impact of Floods on Tea Industry in North Bengal ..	35
177. रूसी ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जे	Spare Parts for Russian Tractors ..	35—36
178. काहिरा में औद्योगिक मेला	Industrial Fair at Cairo ..	36
179. औद्योगिक संयंत्रों का निर्यात	Export of Industrial Plants ..	36—37
180. छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car ..	37

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

960.	पठानकोट स्टेशन पर छोटी लाइन सैक्शन के प्लेटफार्म का विस्तार	Extension of Narrow Gauge Section Platform at Pathankot Station ..	37—38
961.	ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर नलका	Hand pump at Jwalamukhi Road Station ..	38
962.	ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क	Booking Clerk at Jwalamukhi Road Railway Station ..	38
963.	ज्वालामुखी रोड और गुलेर स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt Station between Jwalamukhi Road and Guler Stations ..	38—39
964.	विमान द्वारा गुजरात का सर्वेक्षण	Aerial Survey of Gujarat ..	39
965.	जापान से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation from Japan ..	39—40
966.	इस्पात की पटरियों का निर्यात	Export of Steel Rails ..	40
967.	श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के रेलवे अधिकारियों को वार्षिक लाभ	Annual Benefit to Class I and Class II Railway Officers ..	40—41
968.	महाराष्ट्र में उद्योग	Industries in Maharashtra ..	41—42
969.	नेपाल के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Nepal ..	42
970.	उत्पादक उद्योग का सर्वेक्षण	Survey of Manufacturing Industries ..	43
971.	चाय और पटसन का निर्यात	Exports of Tea and Jute ..	43
972.	विस्फोटक का निर्माण	Manufacture of Detonators ..	43—44
973.	प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन	Production of Natural Rubber ..	44—45
974.	समितियां पंजीयन अधिनियम	Societies Registration Act ..	45
975.	हरियाना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	More Public Sector Projects in Haryana ..	46
976.	पंजाब में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Punjab ..	46
977.	भारतीय उद्योगपतियों की इथोपिया की यात्रा	Indian Industrialists Visit to Ethiopia ..	47
978.	भारत रूस संधि	Indo-Russian Agreement ..	47—48
979.	यूगोस्लाविया को भारत का निर्यात	Indian Exports to Yugoslavia ..	48

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

980.	इस्पात संयंत्रों से कच्चे माल तथा तैयार माल की चोरी	Thefts of Raw Materials and Finished Goods from Steel Plants ..	48—49
981.	भारती मिल्स, पांडीचेरी	Bharathi Mills, Pondicherry ..	49
982.	सत्यमंगलम तथा चामराज-नगर के मध्य नई रेलवे लाईन (दक्षिण रेलवे)	New Railway Line between Satyamangalam and Chamrajnagar ..	49
983.	भिलाई इस्पात कारखाने को सुव्यवस्थित करना	Stream Running of Bhilai Steel Plant ..	50
984.	आंध्र प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Andhra Pradesh ..	50—51
985.	मद्रास में सूती कपड़ा मिलें	Textile Mills in Madras ..	51
986.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production ..	51—52
987.	अर्थ सम्बन्धी मंत्रालयों की समिति	Committee of Economic Ministries ..	52
988.	अमृतसर में कृत्रिम रेशम उद्योग	Art Silk Industry in Amritsar ..	53
989.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की जांच	Enquiry into the Affairs of British India Corporation	53—54
990.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोयले की खरीद	Purchase of Coal from National Coal Development Corporation ..	54
991.	संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills ..	54—56
993.	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंन्स	Industrial Licences in U. P.	56—57
994.	राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलान धागे का आयात	Import of Nylon Yarn by State Trading Corporation ..	57
995.	मरियानी में रेलवे यातायात अधिकारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Regional Traffic Officers in Mariani ..	57—58
996.	राज्यों में लघु उद्योगों के लिए नये लाइसेंस	New Licences for Small Scale Industries in States ..	58
998.	संयुक्त अरब गणराज्य लघु उद्योग दल का दौरा	Visit by a UAR Small Industries Team ..	58
999.	शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge line from Shahdara to Saharanpur ..	59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1000. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार	Improvement in the working of Hindustan Steel Limited ..	59—60
1001. राष्ट्रीय कपड़ा निगम	National Textile Corporation ..	60
1002. निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का कार्यकरण	Working of Neyveli Lignite Corporation Ltd.	60
1003. उत्तर रेलवे (दिल्ली डिवीजन) में टेलीफोन आपरेटर	Telephone Operators in Northern Railway (Delhi Division) ..	61
1004. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स परियोजना, पिंजोर	Hindustan Machine Tools Project, Pinjore ..	61—62
1005. आयात सम्बन्धी नीति	Import Policy	62—63
1006. बड़ौदा डिवीजन में झंडी स्टेशन	Flag Stations in Baroda Division ..	63
1007. कपड़ा उद्योग	Textile Industry ..	63
1008. केरल में नई रेलवे लाइन	New Railway Lines in Kerala	63—64
1009. स्टैण्डर्ड ड्रम कम्पनी	Standard Drum Company	64—65
1010. इस्पात कारखानों के कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप	Political Interference in the Affairs of Steel Plants ..	65
1011. तिरुनेलवेलि और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Tirunelveli and Kanyakumari ..	65—66
1012. सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in the Public Sector	66—67
1014. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स	Bharat Heavy Electricals Ltd.	67
1015. सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट	Central Electrical Engineering Research Institute ..	68
1016. डीजल तथा बिजली के इंजन	Diesel and Electric Engine	68
1017. रेलवे द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned by Railways ..	68—69
1018. प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अधिक बर्थों की व्यवस्था	Provision of more Berths in First Class Compartments ..	69
1019. इनटिगरल कोच फैक्टरी, मद्रास में तीसरी पारी	Third Shift in Integral Coach Factory, Perambur ..	69

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1020.	उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनाएं	Central Projects in Uttar Pradesh ..	69—70
1021.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Workers of Heavy Engineering Corporation ..	70—72
1022.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	Indian Iron and Steel Co. Ltd. ..	72
1023.	अफ्रीकी तथा दक्षिणी अमरीकी देशों को निर्यात	Exports to Africa and South America ..	72—73
1024.	इस्पात कारखानों का प्रशासनिक नियंत्रण	Administrative Control of Steel Plants ..	73
1025.	राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in State Trading Corporation ..	73—74
1026.	भारतीय आर्थिक तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडल का लातीनी अमरीकी देशों का दौरा	Visit of Indian Economic and Trade Delegation to Latin American Countries..	74—75
1027.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में लाभ का बढ़ना	Improvement in the Profitability of the Public Sector Steel Plants	75
1028.	लघु उद्योग	Small Scale Industries ..	75—76
1029.	भारत नेपाल व्यापार	Indo-Nepal Trade ..	76
1031.	एल्युमीनियम का निर्यात	Export of Aluminium ..	76—77
1032.	ग्रैफाइट अयस्क का आयात	Import of Graphite Ore ..	77
1033.	भरतपुर जिले में खस तेल आसवन उद्योग	Khus Oil Distillation Induustry in Bharatpur District ..	77—78
1034.	लक्कदीव का सर्वेक्षण	Survey of Laccadives ..	78
1036.	टेलीविजन सेटों का आयात	Import of Television sets	78—79
1037.	तंजौर तथा रामनाथंपुरम में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Tanjore and Ramanathampuram ..	79—80
1038.	यूरोप में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित माल जोड़ने का कारखाना	HMT goods Assembly ..	80—81

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1039.	केरल में बीड़ी उद्योग का पुनर्गठन	Reorganisation of Beedi Industry in Kerala ..	81
1040.	प्रताप नगर से छोटा नागपुर तथा राजपिपला से अंक्लेश्वर स्टेशनों तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Railway line from Pratapnagar to Chhotta Nagpur and Rajpipla to Anklesvar Stations	82
1041.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को ऋण	Loan to Public Sector Steel Plants	82
1042.	केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर	Central Small Industries Corporation Indore ..	83
1043.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के एकक	British India Corporation Units ..	83
1044.	उपक्रमों में कर्मचारी	Employees in the undertakings ..	84
1045.	तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत कारखाने	Factories registered with Directorate General of Technical Development ..	84
1046.	वाराणसी के निकट ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory near Varanasi	85
1047.	अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन	General Motors Corporation of US ..	85—86
1048.	स्कूटर टायरों का आयात	Import of Scooter Tyres ..	86
1049.	तमिलनाडु के विद्यार्थियों द्वारा गाड़ियां रोकना	Detention of Trains by Tamil Nadu Students ..	86—87
1050.	कुदुरेमुख में लौह अयस्क निकालना	Exploitation of Iron Ore at Kudremukh ..	87
1051.	रेलवे डिब्बों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Passenger Facilities in Railway Bogies ..	87
1052.	मैंगनीज अयस्क खनन उद्योग	Managanese Ore Mining Industry ..	88
1053.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन कानपुर की कूपर एलन तथा नार्थ वैस्ट टैनरी शाखाएं	Cooper Allen and North West Tannery Branches of British India Corporation Kanpur ..	88—89
1054.	आल इण्डिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाईजेशन	All India Manufacturing Organisation ..	89—90
1055.	पूर्वोत्तर रेलवे यातायात प्रशिक्षणार्थियों का त्यागपत्र	Resignation of Traffic Apprentices on North Eastern Railway ..	90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
1056. पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति के यातायात प्रशिक्ष	Scheduled Caste Traffic Trainees on North Eastern Railway ..	90—91
1957. रेलवे गार्ड	Railway Guards	91
1958. विदेशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी का समर्थन	Pooling of Imported know how ..	91—92
1059. उत्तरी बंगाल में बाढ़ के कारण रेलवे पटरियों की क्षति	Damage to Railway Lines in North Bengal due to Floods ..	92—93
1060. बड़ी लाइन का गोहाटी तक विस्तार	Extension of Broad Gauge Line upto Gauhati ..	93
1061. सीमेण्ट आवंटन तथा समन्वय संगठन निधियों के बारे में जांच	Enquiry into Cement Allocation and Co-ordination Organisation Funds ..	93—94
1062. औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में जांच करने के लिये समिति	Committee to go into Industrial Licencing Policy ..	94—95
1063. बाढ़ों के कारण उड़ीसा में रेल की पटरी तथा सम्पत्ति को हानि	Damage to Railway Track and property in Orissa due to Floods ..	95
1064. विदेशी सहयोग प्राप्त परियोजनाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात	Exports of Goods manufactured by Foreign Collaboration Projects ..	95—96
1065. भारत रूस व्यापार	Indo Soviet Trade ..	96—97
1066. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	97—98
1067. मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Dodsal (P) Ltd. ..	98
1068. मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी, बम्बई	M/s Kila Chand Devi Chand and Co. Bombay ..	98—99
1069. अखरोट और अखरोट की लकड़ी का निर्यात	Export of Walnuts and Walnut Wood ..	99
1070. व्यापारिक गतिविधियों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Trading Activities ..	100

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1071. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore by National Mineral Development Corporation	..	100—101
1072. देश में लोहा और इस्पात कारखाने	Iron and Steel Plants in the country	..	101—102
1073. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, रायपुर	Wagon Repair Shop Raipur	..	102
1074. लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सरलीकरण	Simplification of licensing procedure	..	102—103
1075. रूसी सहायता प्राप्त कारखानों के लिये रूसी कर्मचारी	Russians for Soviet Aided Plants	..	103
1076. संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills	..	104
1077. बोकारो इस्पात कारखाने के लिये निर्माण सामग्री की पूर्ति	Supply of structural materials to Bokaro Steel Project	..	104—105
1078. दक्षिण पूर्व रेलवे के बोडामुंडा स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान किराया	House Rent for Railway Staff of Bondamunda (South Eastern Railway)	..	105
1079. रामनाथपुर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर आक्रमण	Raid on Ramnathpur Station (N.E. Rly.)	..	105
1080. अमरीका को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to USA	..	106
1081. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	..	106—108
1082. विदेशों में भारतीय गुलाब के फूलों की मांग	Demand for Indian Roses in Foreign countries	..	108
1083. मुजफ्फरपुर के निकट गाड़ी की दुर्घटना होते-होते बचना	Aversion of Train Mishap near Muzaffarpur	..	109
1084. सरकारी उपक्रमों में अधिकारी	Officers in Public Undertakings	..	109
1085. रेलवे स्लीपर्स	Railway sleepers	..	109—110
1086. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्यक्रम	Working of Hindustan Steel Limited	..	110—111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1087. मनमाड और ढोंड के बीच मेल/एक्सप्रेस गाड़ी	Mail/Express Train between Manmad and Dhond ..	111
1088. बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Chairman, Bokaro Steel Plant ..	111—112
1089. वोल्टास लिमिटेड	Voltas Ltd. ..	112
1090. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड	Union Carbide India Ltd. ..	113
1091. नेशनल इण्डिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	National India Traders Private Ltd. Bombay ..	113
1092. ग्लास कारवायज एण्ड प्रैस्ड वेयर्स	Glass Carboys and pressed wares Ltd. Bombay ..	113—114
1093. सेन्ट्रल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, बम्बई	Central Distributors Ltd. Bombay ..	114
1094. पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग	Ticketless Travel on North Eastern Railway ..	114—115
1095. पूर्वोत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों का अपने प्रस्थान से गन्तव्य स्थान पर विलम्ब से पहुंचना	Late Running of Trains on North Eastern-Railway ..	115
1096. पूर्वोत्तर रेलवे जोन की उपेक्षा	Neglect of North-Eastern Railway Zone ..	115—116
1097. गैर-सरकारी रेलवे व्यवस्था	Privately Owned Railway System ..	116
1098. सीमेंट का मूल्य	Cement Price ..	116—117
1099. हिन्दुस्तान स्टील के मजदूर संघ की मान्यता समाप्त करना	De-Recognition of Hindustan Steel Workers' Union ..	117
1100. द्रुतगामी डीजल इंजिनों की खरीद	Purchase of High Speed Diesel Engines ..	117
1101. चाय निगम	Tea Corporation ..	118
1102. औद्योगिक लाइसेंस देने के नियमों में संशोधन	Revision of Industrial Licensing Rules ..	118—119
1103. भारतीय इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Items ..	119
1104. पश्चिम बंगाल में कृषि उद्योग	Agro-Industries in West Bengal ..	119—120

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1105.	दोहद खंडवा रेलवे लाइन	Dohad Khandwa Railway Line ..	120
1106.	दोहद और खंडवा के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Dohad and Khandwa ..	120—121
1107.	खंडवा दोहद रेलवे लाइन	Khandwa Dohad Railway Line ..	121
1108.	खंडवा दोहद रेलवे लाइन	Khandwa Dohad Railway Line ..	121—122
1109.	इलाहाबाद यात्री रेल गाड़ी से एक महिला यात्री को बाहर फेंकना	Throwing out a Lady Passenger from Allahabad Passenger Train ..	122
1110.	आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों की बिक्री के बारे में शिकायतें	Complaints against sale of imported Raw materials and components ..	123
1111.	शिवरावपेट स्टेशन पर यात्रियों से आय	Income from Passengers at Sivaraopeta Station	123
1112.	उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण	Mineral Survey of Orissa ..	124
1113.	सूरत और भड़ोच के बीच शटल गाड़ी चलाने की मांग	Demand for shuttle Train between Surat and Broach ..	124—125
1114.	स्टेशनों का वर्गीकरण	Categorisation of Stations ..	125
1115.	रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षक	Commercial inspectors on Railways ..	125—126
1116.	यूगोस्लाविया से व्यापार संतुलन	Balance of Trade with Yugoslavia ..	126—127
1117.	देश में निर्मित मशीनों का प्रयोग करने वालों को प्रोत्साहन	Incentive to Users of Indigenous Machinery ..	127
1118.	अलौह धातु की मांग	Demand of Non-Ferrous Metals ..	127—130
1119.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ..	130—131
1120.	आमों का निर्यात	Export of Mangoes	131
1121.	राजस्थान में फास्फेट मिट्टी के निक्षेप	Deposits of Rock phosphate in Rajasthan ..	131—132
1122.	रेमिंगटन रैंड टाइपराइटरों का निर्माण	Manufacture of Remington Rand ..	132
1123.	पश्चिमी रेलवे की यात्री रेलगाड़ी संख्या 161	Western Railway Passenger Train No. 161	132—133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1124.	अलवर में रेलवे फाटक पर रेलवे पुल	Railway Bridge at Level Crossing in Alwar	133
1125.	राजस्थान में जिप्सम के निक्षेपों का उपयोग	Uilization of Deposits of Gypsum in Rajasthan	133
1126.	तेलंगाना के आन्दोलनकर्ताओं द्वारा रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Damage to Railway Property by Telengana Agitators ..	134
1127.	मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी	M/s Cooper Allen and Co.	134
1128.	खेत्री तांबा उद्योग समूह	Khetri Copper Complex ..	134—135
1129.	मैसूर में लाइसेंस जारी किये जाने के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र	Applications Pending for Issue of Licences in Mysore ..	135
1130.	भूमिगत रेलवे	Underground Tube Railways ..	135—136
1131.	आगरा तथा ढोलपुर के बीच रेलवे की तारें काटी जाना	Cutting of Rail Wire between Agra and Dholpur ..	136
1132.	रेलवे सम्पति को क्षति	Damage to Railway Property ..	136—137
1133.	झांसी तथा वाराणसी के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Express Train between Jhansi and Varanasi	137
1134.	बम्बई-इलाहाबाद रेल मार्ग पर डीजल इंजन चलाना	Introduction of Diesel Engines on Bombay-Allahabad Route ..	137
1135.	जबलपुर से इटारसी सेक्शन की यात्री रेलगाड़ियों के संचलन समय में वृद्धि	Increase in Running Time of Passenger Trains in Jabalpur-Itarsi Section ..	137—138
1136.	फास्फेट के रिजर्व	Phosphate Reserves	138
1137.	सरकारी उद्यमों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निदेश	Investment by Private Sector in State Enterprises ..	138—139
1138.	लन्दन में मैसूर सरकार का व्यापार अभिकर्ता	Mysore Government's Trade Agent in London	139
1139.	मणिपुर में उद्योग	Industries in Manipur	139
1140.	अल्पविकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Undeveloped and Backward Areas ..	140
1141.	बल्गारिया के साथ व्यापार	Trade with Bulgaria ..	140

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

1142. सीमेंट का निर्यात	Export of Cement ..	140—141
1143. सरकारी क्षेत्र में कागज की स्थापना	Setting up of a Paper Corporation in Public Sector ..	141—142
1144. अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा	Ashoka Paper Mills, Darbhanga ..	142
1145. दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्क	Commercial Clerks on Southern Railway ..	142—143
1146. उत्तर रेलवे के मुख्यालय में आशुलिपिक	Stenographers in Northern Railway Headquarters Office ..	143
1147. रेलवे में आशुलिपिकों के लिये प्रोत्साहन परीक्षा	Incentive Test for Stenographers on Railways	144
1148. न्यूजीलैण्ड के साथ व्यापार	Trade with New Zealand ..	144—145
1149. रेल के माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Rail Wagons ..	145
1150. दक्षिण कोरिया को उसके रेलवे के विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये सहायता	Assistance to South Korea for Electrification of Their Railways ..	145—146
1151. इंडोनेशिया के साथ व्यापार	Trade with Indonesia ..	146
1152. मैंगनीज अयस्क का निर्यात व्यापार	Export trade of Manganese Ore ..	147
1153. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Faizabad, Uttar Pradesh	148
1154. हाइड्रोसल्फाइट सोडे का आयात	Import of Hydro-sulphite Soda ..	148—149
1155. रेलगाड़ियों में कंडक्टर और अटेंडेंट	Conductors and Attendants in Trains	149
1156. केन्द्रीय कुटीर उद्योग वस्तु भण्डार (एम्पोरियम), नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the Employees of Central Cottage Industries Emporium, New Delhi	149—150
1157. रूस को रेल के माल डिब्बों का संभरण	Supply of Rail Wagons to USSR ..	150—151
1158. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd. ..	151
1159. मंगलौर रेलवे स्टेशन	Mangalore Railway Station ..	151—152

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
श्रीनगर में पवित्र स्थानों को आग लगाने की योजना बनाने के कारण श्रीनगर में और काश्मीर के अन्य भागों में पाकिस्तान समर्थक तत्वों के पकड़े जाने का समाचार	Reported apprehension of pro-Pakistani Elements in Srinagar and other Parts of Kashmir for Planning to set Fire to Holy Shrines in Srinagar	.. 152—155
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	.. 155—156
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 155—158
पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा का वापिस लिया जाना	Revocation of Proclamation in Relation to West Bengal	.. 158
सभा का कार्य	Business of the House	.. 158—159
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक—	Lok Pal and Lok Ayuktas Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय बढ़ाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee	.. 159
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	159—186
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	.. 160
डा० सुशीला नैयर	Dr. Shushila Nayar	.. 160—161
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Ghulam Mohammed Bakshi	.. 161—162
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	.. 162—164
श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	.. 164—165
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	.. 165—166
श्री जी० कुचेलर	Shri G. Kuchelar	.. 166
श्री स० कुन्डू	Shri S. Kundu	.. 166—168
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 168
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	.. 168—169
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	.. 169—170
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale	.. 171
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	.. 171—172
श्री राजा राम	Shri Rajaram	.. 172—174

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 174—175
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao	.. 175—181
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	.. 181—183
श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Sheopujan Shastri	.. 183—184
श्री वि० ना० शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	.. 184—186
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	.. 186
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
29वां प्रतिवेदन	Twenty-ninth Report	.. 184

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 फरवरी, 1969/ 6 फाल्गुन, 1890 (शक)
Tuesday, February 25, 1969/Phalguna 6, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Distiller's Trading Corporation, Bombay

*151. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the quantity of each of the chemicals exported by the Distiller's Trading Corporation, Bombay to foreign countries every year ;

(b) the amount of foreign exchange earned by the Corporation by way of exports ;

(c) whether any licence for import of chemicals was given to the Company after devaluation ; and

(d) the additional exports for which the licence was issued to the Company in the year 1967 over their previous year's export performance ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) तथा (ख). निर्यात के आंकड़े महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा मात्रा एवं मूल्य में रखे और प्रकाशित किये जाते हैं। वे उन आंकड़ों को पार्टियों के नाम से नहीं रखते।

(ग) तथा (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Deven Sen : Will the Hon. Minister be pleased to state as to whether it is a fact that the Distiller's Trading Corporation is one of many firms of Seth Jiwanlal, Kilachand Devchand of Bombay ? What was the Principal asset of this firm during 1967 General Elections, and what is that now ? Whether it is a fact that an amount of Rupees Seven lakhs was given by Shri Tiwari, Secretary of Seth Jiwan Lal, during Elections as fund to Kalakankar College, whose Chairman is External Affairs Minister, Shri Dinesh Singh ?

Shri B. R. Bhagat ; This information requires details. If the Hon'ble Member gives notice for that, I will be able to say something. I have no such information at present. And Hon. Member knows this fact fully.

Shri Deven Sen : This is a strange way of side tracking the reply of a question. In the first instance to say that the information is being collected and secondly, that no answer could be given, it is stated that the answer would be given if a notice of a separate question is given. When the questions are admitted, it ought be presupposed that the members will ask supplementaries.

Shri B. R. Bhagat : Supplementaries would be definitely answered, but they should be connected with the main question. When Hon. Members ask new questions, and no information is readily available with me, what can be done. By whom, where and how much donation was given are such things information regarding this can only be collected after receipt of questions of this type.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम संबंधी समिति का प्रतिवेदन

+

*152. **श्री दे० अमात :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री गु० चं० नायक : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
कुमारी कमला कुमारी : **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने सरकार को अब अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके निष्कर्षों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है। ज्योंही यह जांच पूरी होगी समिति की मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णय दिखाने वाला एक विवरण, रिपोर्ट के साथ संसद् के समक्ष रख दिया जायेगा ।

श्री दे० अमात : कई एक विकास योजनाओं में बहुत सी चीजें आवश्यकता से अधिक थीं, जैसे सयंत्र, कोयला, ट्रक, जीपें इत्यादि । इसके अतिरिक्त कुछ उपकरण ऐसे ही थे जो बिना

अनुमति लिए किसी अन्य परियोजना के लिए दे दिये गये। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या इसी प्रकार की बातें ही आज के वित्तीय संकट के लिए उत्तरदायी नहीं, जिसका सामना आज निगम को करना पड़ रहा है।

श्री जगन्नाथ राव : इस समिति ने अनेक प्रश्नों पर विचार किया है और यह उनमें से एक है। इससे पूर्व समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में प्रतिवेदन दिया था। अपने दसवें प्रतिवेदन में इसने कुछ दोष बताये थे। ये सब बातें मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन हैं और इसका निश्चय शीघ्र ही हो जायेगा।

श्री दे० अमात : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह गम्भीर स्थिति की बात नहीं है कि लेखा कार्य, जिसमें भण्डार का लेखा भी सम्मिलित है, के बहुत पीछे रह जाने से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थिति और भी बिगड़ गई है ? इसके अतिरिक्त, निगम के दस वर्षों तक अस्तित्व में रहने से उसके मासिक लेखा-जोखा रखने में भी सामर्थ्य नहीं है। कानूनी बंधनों के कारण इन हिसाब लेखों को वार्षिक बनाया जाता है। मासिक लेखा और विनियोजना लेखा परीक्षा के अभाव में बजट प्रावधान में इसके व्यय पर नियन्त्रण करना असम्भव है। लेखा-जोखा और भण्डार के हिसाब की कमी के कारण आय-व्ययक की यथार्थता अपने में गम्भीर दोषपूर्ण हो गई है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस दयनीय अवस्था के शोचनीय कारणों के विश्लेषण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री जगन्नाथ राव : इस निगम के प्रबन्ध में से दोषों को दूर करने के लिए समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। ये सब बातें विचाराधीन हैं और इन पर विचार होगा।

Shri Om Prakash Tyagi : Whether the National Coal Development Corporation has tried to enquire into the ratio of efficiency and economy between Private Big Collieries and National Coal Corporation, which is profitable and which is running its business smoothly? What is the reaction of the National Coal Development Corporation so far as the recommendations of the Coal Wage Board are concerned? To what extent the National Coal Development Corporation have followed the safety rules and what is its reaction in this connection?

श्री जगन्नाथ राव : यह तो बहुत जटिल प्रश्न है। इसका सम्बन्ध तो समिति की राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के यथार्थ संचालन से सम्बद्ध सिफारिशों से है। मैं यह कहता हूं कि इसने पिछले दो वर्षों में कोई लाभ नहीं किया। वर्ष 1965-66 में इससे 61 लाख रुपये का लाभ हुआ। इसकी उपक्रय क्षमता बहुत छोटी होने के कारण उत्पादन अधिक नहीं हो सका। इसकी उत्पादन क्षमता 160 लाख टन प्रतिवर्ष है। जब तक इसका यह उपक्रय है जो बहुत गिर गया है, यह अधिक उत्पादन नहीं कर सकती। अत: यह असन्तुलन तो है ही। इसके दूसरे प्रश्न जैसे वेतन-आयोग आदि का मैं ध्यान दूंगा।

Shri N. S. Sharma : I want to know as to how long the report of the Committee will take to be published.

श्री जगन्नाथ राव : मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यह दो महीने में इस सत्र के अन्त तक प्रकाशित हो जायेगी ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : In the first instance a contract was signed with Railways to supply the coal after getting it washed by Giridih Colliery. Now it is known that the Railways have refused to purchase this Coal. I want to know whether the Railways have refused to take coal because of any mistake of the Corporation or has any defect been found in the quality of coal ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं यह एक दम तो नहीं कह सकता परन्तु यह अवश्य है कि रेलवे की मांग बहुत कम हो गई है । किसी एक विशेष विषय को लेकर प्रत्येक प्रश्न के अनुपूरकों को यदि पूछा जायेगा तो उनके उत्तर देना कठिन हो जायगा । समिति की विशेष सिफारिशों के सम्बन्ध में मैं अब बताता हूं । जैसा मैंने कहा कि रेलवे की मांग में कमी हो गई है क्योंकि इंजनों को डीजलीकृत और विद्युतीकृत कर दिया है । मैं निश्चय से नहीं बता सकता कि कोयला खान के इस विशिष्ट कोयले को लेने से रेलवे ने क्यों इन्कार किया ।

श्री रा० बरुआ : ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले दस वर्षों में कोयले का उत्पादन लक्ष्य का स्थिरीकरण वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हुआ है। वस्तुतः ऊर्जा के नये स्रोतों के उत्पन्न होने से, उसे उपयोग में लाने के लिए कोयले पर की निर्भरता कम होती जा रही है। इसके साथ-साथ हम एक ऐसी वस्तु स्थिति से गुजर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय कोयला विकास निगम सहित बहुत से और भी कोयले की खानें घाटा उठा रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की वर्तमान नीति, इस समग्र विषय, अर्थात इसके भावी उत्पादन और प्रबन्ध के तदनुरूप नया रूप देने और इसका मूल्यांकन करने की है ?

श्री जगन्नाथ राव : देश की आवश्यकता के अनुसार भावी उत्पादन की योजना करनी है । यह ठीक है कि मांग गिर गई है । जैसा मैंने पहले बताया कि रेलों ने भी डीजलीकरण और विद्युतीकरण के कारण अपनी मांग में कमी कर दी है । यह एक महत्वपूर्ण मासला है जिसको हमने भावी उत्पादन के प्रतिमान के सम्बन्ध में केवल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में ही नहीं अपितु निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में भी विचार करना है ।

Shri Shiv Charan Lal : I want to know whether National Coal Development Corporation can supply coal to Bangle Industry in Ferozabad ?

If so, how much ? There is Bangle Industry in Ferozabad for which coal is essential.

श्री जगन्नाथ राव : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम मुख्यतया सरकारी, क्षेत्र उपक्रमों और राज्य विद्युत मण्डलों को कोयला भेजती है । परिसीमत हद तक ही यह निजी उद्योगों को भेजती है । मैं तुरन्त तो इसका उत्तर नहीं दे सकता कि यह कितनी मात्रा में कांच उद्योग को देती है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का कार्य संचालन डांवाडोल है। इसका कार्य सन्तोषजनक नहीं है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सम्बन्ध में बहुत से प्रतिवेदन आए हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रतिवेदनों में बताई गई कमियों पर विचार किया गया है और इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : जब सरकारी उपक्रम समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उस समय माननीय सदस्य उसके सभापति थे। उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं और अवश्य ही उनको कार्यान्वित किया जायगा।

डा० रानेन सेन : लगभग एक या दो वर्ष पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कुछ कर्मचारियों और उनके संगठनों ने कुछ शिकायतें की थीं कि बहुत सी मशीनें उपयोग में नहीं लायी गईं तथा बहुत अपव्यय हुआ है। इस पर सदन में निर्णय भी हुआ था। क्या मैं जान सकता हूं कि सदन में जो विशिष्ट अभियोग लगाए गए थे उनका अन्वेषण हो चुका है और यदि हो चुका है तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सत्य है कि राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संस्था ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बहुत सी अनियमितताओं का उल्लेख किया था। माननीय सदस्य श्री प्र० कु० घोष ने भी कुछ आरोप लगाए थे। इस समिति ने विविध प्रकार के केवल 25 आरोपों की जांच की थी तथा वह भी इसी परिणाम पर पहुंची कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं। उनपर कार्यवाही की जा रही है। सतर्कता अधिकारी से भी उनकी जांच करने को कहा गया है।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that during the last two years the prices of coal have gone much high ? If so, then how much, and the reasons thereof ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री नन्द कुमार सोमानी : विक्रय की स्थिति बहुत ही दोषपूर्ण है, और साथ ही कोयला भी निम्न कोटि का रहता है, इन्हीं दो दोषों के कारण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पीछे रह जाता है दूसरे एक यह कमी है कि खनन किया हुआ कोयला निम्नकोटि का है। उसमें तापजनक तत्वों की कमी है तथा राख और नमी की मात्रा अधिक होती है। जिसके कारण वह उन बॉयलरों के लिए नितान्त अनुपयोगी होता है जो कि सशक्त दाह्य तकनीक पर चलते हैं। क्या यह सही है कि डी० जी० टी० डी० के साथ दुर्गम सन्धि करके राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उन ग्राहकों पर इसी कोयले का प्रयत्न कर रही है जो कि इस कोयले का उपयोग नहीं करना चाहते ? और यदि ऐसा है तो, इस तथ्य के होते हुए भी कि उद्योग से नियंत्रण एवं लाइसेंस हटा लिया गया है, सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उपभोक्ताओं को निम्नकोटि का कोयला दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उच्चकोटि के कोयले का भी उत्पादन करता है। मैं माननीय सदस्य के इस कथन से भी सहमत नहीं हूं कि तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच कोई सांठ-गांठ है। यदि मुझे किसी विशिष्ट मामले की सूचना दी जाय तो मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं आपके समक्ष विशिष्ट मामला ला सकता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : In spite of investing a sum of Rs. 170 crores in 11 years on N. C. D. C. it is found that, due to wastage, there has been a loss of Rs. 2 crores in it. As Shri Somani has correctly stated and as it is described in the Report also, the position is that even the public undertakings are not willing to take this coal. Added to that an amount of Rs. 1 crore has been written off by them in the back date during three years. This deplorable condition of the management is quite clear from the report. The members of the top management are responsible for that. I want to know from the Hon. Minister that since the report was submitted to him one year ago, why he is sitting idle for such a long time. An interim report on the matter was also submitted to him, and he gave certain directives to the N.C. D.C. after this submission. One of the directives was as follows:

"It is stated that for an investment outlay of Rs. 168 crores, the N.C. D. C. has build up inventories of the order of 32 crores. The suggestion is to reduce to one-half so that the Corporation's profitability will improve."

The other directive was:

"Another important decision taken by the Government is to advise the N.C.D.C. to close down the Giridih coal mines and one or two others, phasing this process over a three-year period....."

Thus, I want to know from the Hon. Minister, whether the directives given by him have been implemented by N.C.D.C., if so, then how far and how much time is required by the Government to take their decision finally in the matter?

श्री जगन्नाथ राव : यह कथन सत्य नहीं है कि समिति ने अपना प्रतिवेदन एक वर्ष पहले प्रस्तुत कर दिया था। फरवरी 1968 में प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें 34 सिफारिशें और सुझाव थे।...

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या यह एक वर्ष नहीं है ?

श्री जगन्नाथ राव : उनको निगम ने स्वीकार नहीं किया था। वे सिफारिशें महत्वपूर्ण नहीं थीं। अन्तिम प्रतिवेदन 19 अगस्त, 1968 को प्रस्तुत किया गया था...

श्री कंवर लाल गुप्त : यह मई, 1968 को प्रस्तुत किया गया था।

श्री जगन्नाथ राव : अन्तिम प्रतिवेदन 19 अगस्त, 1968 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें सिफारिशों और सुझावों की संख्या 164 थी। उन पर कार्यवाही हो रही है। जैसा कि मैं कह चुका हूं अप्रैल के अन्त से पहले-पहले प्रतिवेदन तथा सिफारिशों और उन पर सरकारी कार्यकलापों का विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र ने सदन का ध्यान उन दो निदेशों की ओर दिलाया है जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को दिये गये थे। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, उन निदेशों का कहां तक पालन तथा कार्यान्वित किया है ?

श्री जगन्नाथ राव : निदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री रंगा : निदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं, इस विषय में अवश्य ही उनको सूचना मिली होगी। यह कोई सिफारिशें तो नहीं हैं जिनपर विचार करना हो। भारत सरकार ने उनपर विचार किया था और उसके बाद ही सरकार ने उन्हें निदेश देना उचित समझा है। निदेश प्राधिकारियों को कुचेष्टा करने का अवसर नहीं मिलने देते किन्तु लगता है कि वे कुचेष्टाएं कर रहे हैं अन्यथा ऐसा क्यों होता कि मंत्री महोदय को यह सूचना ही नहीं मिली है कि निदेशों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रकार की किसी सूचना का मुझे ज्ञान नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार द्वारा दिए गए निदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा था।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the Hon. Minister whether he has taken any notice of the statement made by the Minister of Labour in which he has refused to take coal until the recommendations made by the Coal Wage Board are not accepted by the Coal Industry or the National Coal Development Corporation, if so, then what is the consideration of this corporation in this matter ?

My second question is that several disputes are existing in the Coal Industry, and no solution is being sought. The reason for that is that the Coal Industrialists close down their mines thereby decreasing the production of coal. What have you thought in this matter ?

श्री जगन्नाथ राव : मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच मजदूरी के विषय में कोई विशिष्ट शिकायत या विवाद सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है, यदि कोई ऐसी विशिष्ट शिकायत आई, तो मैं अवश्य ही उस पर विचार करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : You have not replied to my first question.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न···श्री हेम राज।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Minister of Labour had made a statement that until Coal Industry will accept the recommendations of the Wage Board.....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर पहुंच गया हूं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन

+

*153. **श्री हेमराज :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री ओंकर लाल बेरवा : **श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव के लिए उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई कसौटी

निर्धारित करने तथा औद्योगिक रूप से पहले से ही विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि के जमाव को निरुत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या इन प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : No, Sir, my question should be answered. The statement given by the Minister of Labour.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगले प्रश्न पर पहुंच गया हूं । अगला प्रश्न पूछा जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है । अब मैं पीछे नहीं जा सकता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Do you want to evade my question. Sir, is there any reason of not answering it.....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं असमर्थ हूं । अगला प्रश्न रखा जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है । अब श्री हेमराज को उस पर अपना अनुपूरक प्रश्न रखना है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I was on my legs before you called for a next question. Either we should not be allowed to put questions or our questions should be answered:?

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय चाहें भी तो मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा । श्री हेमराज अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री हेमराज : क्या यह सच है कि रास्ट्रीय विकास परिषद् ने पिछड़े क्षेत्रों की कसौटी निश्चित करने के लिए तथा यह जानने के लिए कि उन क्षेत्रों को उनका भाग मिलता है दो कार्यकारी दल बनाए हैं ? चौथी पंच-वर्षीय योजना को अप्रैल तक अन्तिम रूप मिलने वाला है । क्या मैं जान सकता हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव के सम्बन्ध में मंत्रालय ने राष्ट्रीय विकास परिषद् या कार्यकारी दलों को क्या राय दी है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं ही कहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के फलस्वरूप दो कार्यकारी दल नियुक्त किये गये थे । उनमें से एक इसलिए कि वह ऐसी सिफारिशें करे जिसके आधार पर पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास किया जाये तथा यह भी कि पिछड़े क्षेत्रों को भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा सके । दोनों दलों से प्रतिवेदन मिलने की आशा है और जैसे ही उनसे प्रतिवेदन मिलेंगे सरकार उन पर निर्णय देगी ।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वयं मंत्रालय ने भी ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया है जिनमें तीन पंच-वर्षीय योजनाओं के दौरान कोई भी उद्योग नहीं खोला गया, और यदि किया है तो वह राज्य और भू-भाग कौन-कौन से हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मंत्रालय भी इसका पता लगाने में व्यस्त था। उसी समय यह दोनों दल नियुक्त किये गए थे। मंत्रालय को जो भी सूचना उपलब्ध हो पायी थी उसे मंत्रालय ने इस दल को ही अपनी सिफारिशें देने के लिए सौंप दिया है।

श्री चेंगलराया नायडू : एक ओर तो सरकार कुछ क्षेत्रों में उद्योगों के एकत्रीकरण को रोकने के मामले पर विचार करने के लिए समितियां नियुक्त कर रही है तथा जो क्षेत्र कम विकसित हैं वहां उद्योगों की स्थापना करके वह उनकी सहायता करना चाहती है। तथा दूसरी ओर हम देखते हैं कि सरकार उन परियोजनाओं को स्थगित कर रही है जिन्हें उद्योगहीन क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए स्वयं सरकार ने मंजूरी दे दी हुई है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। सरकार ने विशाखापटनम में एक जस्ता पिघलाने का संयंत्र लगाने का निर्णय किया था। श्री पी० सी० सैन, जो कि उस समय कार्यकारी मंत्री थे, ने दिसम्बर में सलाहकार समिति में कहा था कि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिए जनवरी में पोलैंड के विशेषज्ञ आ रहे हैं। किन्तु हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस का विरोध किया है तथा कहा है कि संयंत्र विशाखापटनम में नहीं लगना चाहिए। उन्होंने फिर कुछ दिन बाद इस बात की घोषणा की कि केन्द्र सरकार विशाखापटनम में लगने वाले जस्ता पिघलाने के संयंत्र का स्थगन कर रही है। जब ऐसी स्थिति चल रही है तो जिन क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं हैं उनके साथ न्याय की जाने की क्या सम्भावना हो सकती है ? कल सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मैंने जाना कि विदेशी विनिमय की कमी के कारण विशाखापटनम में जस्ता पिघलाने वाले संयंत्र की स्थापना को स्थगित कर दिया गया है। यह मेरी समझ में नहीं आया। विदेशी विनिमय को बचाने के लिए ही हम विशाखापटनम में जस्ता पिघलाने वाले संयंत्र को लगाने जा रहे हैं। हम अरबों का जस्ता खरीदते हैं। यदि विशाखापटनम में यह संयंत्र लग जाय तो जस्ता अयस्क का आयात करने के लिए हमें केवल 50 प्रतिशत राशि ही व्यय करनी पड़ेगी और इससे हमारी 50 प्रतिशत विदेशी विनिमय की बचत होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसे क्यों स्थगित करना चाहती है ? जो परियोजना पहले ही स्वीकृत हो चुकी है उसे सरकार किस के बिना पर तथा किस मजबूरी के कारण स्थगित करना चाहती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : परियोजना को स्थगित नहीं किया गया है। जहां तक इन दोनों दलों का सम्बन्ध है इन्हें योजना आयोग ने असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए नियुक्त किया है। जो भी निर्णय किया गया है उसे चौथी योजना में सम्मिलित कर दिया जायगा। जिस योजना की माननीय सदस्य ने चर्चा की है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि

निर्णय से पहले विभिन्न पहलुओं से विचार किया जाता है। परियोजना को स्थगित नहीं किया गया।

श्री मंगलाथुमाडोम : दो समितियां, वांचू समिति तथा पांडे समिति, नियुक्त की गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में देरी होने का क्या कारण है? क्या इस विषय में योजना आयोग से कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : देर नहीं हुई है। नवम्बर महीने में इस समिति का गठन हुआ था। उन्हें अपना प्रतिवेदन दो या तीन महीने में प्रस्तुत करना था तथा मुझे बताया गया है कि प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने वाला है।

श्री वीरभद्र सिंह : क्या यह सच है कि तीन पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई भी प्रमुख उद्योग नहीं खोला गया, और यदि नहीं खोला गया तो असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ये अध्ययन दल अपनी सिफारिशें देते समय इन सभी तत्वों को ध्यान में रक्खेंगे।

श्री स० कुन्दू : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस विषय पर सितम्बर, 1968 में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा। प्रश्न विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में था। उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् का विचार है कि आवश्यकता इस बात की है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन दिए जायें तथा नए औद्योगिक एककों की महानगरों या भारी औद्योगीकृत क्षेत्रों में स्थापना के विरुद्ध निरुत्साह पैदा किया जाय। इसी दिशा में कुछ और सुझाव भी दिए गए थे। इस समय मैं उन सुझावों में नहीं उलझना चाहता। मंत्री महोदय ने अभी दो दलों की नियुक्ति के बारे में कहा है कि एक दल पिछड़े राज्यों को पहचानने की कसौटी निश्चित करेगा। इसके बाद दूसरा दल यह जानने के लिए नियुक्त किया जाएगा कि कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं। जब वह दल अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा तब एक अन्य समिति यह छानबीन करने के लिए नियुक्त की जाएगी कि किस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जाय। सम्पूर्ण अभिवृत्ति यही है कि जब सरकार कोई काम करना नहीं चाहती तो वह समितियां नियुक्त करके हर कार्य को स्थगित कर देती है।

लगभग एक वर्ष से समिति ने अपना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। यहां निरूपित हुए सिद्धांत के अनुसार जब तक समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार तब तक स्वयं क्या कर रही है। समस्या इतनी सरल है कि मंत्रालय का कोई भी छोटा दल इसे सुलझा सकता है? कसौटी निर्धारण करने के लिए पहले ही पर्याप्त आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं तथा यह बताया जा सकता है कि कौन-कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं।

समिति के प्रतिवेदन तक, नगर क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भेजने के लिये वे नियम जिसकी, रूप रेखा यहां पर बनाई गई है और जिसे मैंने पढ़ा है, का पालन करने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मेरे विचार से इन दलों के बारे में गलत फहमी हो गई है। मेरा निवेदन है कि इन दलों को सरकार ने नहीं बनाया प्रत्युत इनको योजना आयोग ने नियुक्त किया है। इन्होंने दो दल बनाए हैं, पहला पिछड़े हुए क्षेत्रों की पहचान के मानदण्ड की सिफारिशें करने के लिये, क्योंकि यह बहुत ही जटिल समस्या है। साथ ही इसका विचार एक राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में रखते हुये ही नहीं अपितु इस मामले में राज्य के भीतर की स्थिति का ध्यान रखना होता है अतएव योजना आयोग ने विचार किया कि वे इस मानदण्ड की सिफारिश इस आधार पर करें जिससे कि पिछड़े हुये क्षेत्रों की समस्याओं को समझा जा सके। पहले दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा से पहले ही, इन पिछड़े वर्गों में असंतुलन को दूर करने की दिशा में कुछ करने के लिये उनको आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहन देने की सिफारिशें करने के लिये दूसरे दल का गठन किया गया। इन दोनों दलों की सिफारिशों के मिलने के पश्चात् अवश्य ही हम कार्यवाही करेंगे कि क्षेत्रीय असन्तुलनों को किस सीमा तक दूर किया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि सिफारिशों के आधार पर ही इन क्षेत्रीय असन्तुलनों को एक ही दिन में दूर किया जा सकता है तो मैं समझता हूं यह उनकी गलत धारणा है। यह निश्चित है कि हम इस प्रादेशिक असुन्तुलन को दूर करने के लिये कार्यवाही करेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, because of this regional imbalance there is unrest in Telangana, this paradox is seen not only in Telangana, but also all over the country. We have taken keen interest in the Industrial Development of some regions of the country, i.e. Maharashtra, W. Bengal and other areas. I am not dissatisfied with this development, but I want to draw your attention to the State of Rajasthan also. After the States were taken out from the clutches of Rajas and Maharajas, the State of Rajasthan has been recently formed. I want to know from the Hon. Minister as to why in these twenty years we have not been able to develop this area in the field of industrial development ?

I have put this question many a time and everytime in was said that the answer to the question would be placed on the Table of the House. Crores of Rupees we have spent today for the Industrial Development of that region but it is all the more necessary due to the rising new generation, who want gainful employment. For the sake of industrial development, it is essential to develop the means of transport and electricity in the State. I want to know from Industries Minister whether any planning has been done for Rajasthan in the coming years. It is also requested that the figures of the past years may kindly be made available, which must show investment made by the Government for the development of the various States and how much you want to spend to balance this development ?

Shri F. A. Ahmad : The Hon. Member has asked so many things, how much would be invested in Rajasthan in comparison to other States ? I think the Hon. Member is aware of the decision taken by the Planning Commission this time after meeting all the States together

to authorise each state to spend the funds already allotted or to be allotted to them on the priority, to be decided by them. Except that agricultural sector will not be ignored various items of industrial development and the investments to be made in various projects will be decided by the States themselves.

I agree that there is regional imbalance but this is not due to the Government alone, but the fact is that people have not tried to remove the imbalance; as the people of Punjab and Madras have tried. They got incentives for Small Scale Industries, and for this reason there was progress in these two States. Therefore, besides the efforts of the Government, if the people there also try and invest for their development the regional imbalance can be removed.

श्री एन० शिवप्पा : माननीय मंत्री बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और अपनी कमियों को कई ढंगों से ढांपने में सिद्धहस्त हैं। जो तर्क वह प्रस्तुत कर रहे हैं, वे वही कर सकते हैं। अपनी नीतियों की असफलता के संदर्भ में कभी वह राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम लेते हैं और कभी योजना आयोग का उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि ये ही उद्योगों को चलाने के लिये धन देने की व्यवस्था के लिये नियम बनाते हैं। पिछड़े क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिये वहां उद्योगों को खोलने की दिशा में सीधी कार्यवाई करने के बजाए लोगों की आखों में धूल क्यों झोंकी जाती है। इसके लिये खाम्खवाह क्यों बहाने बनाये जाते हैं? क्या मैं उनका ध्यान मैसूर के साथ हुए अत्याचार की ओर आकृष्ट कर सकता हूं। मैसूर में औद्योगिक विकास के लिये 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था में से केवल 40 करोड़ रुपये दिये गये। क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि भारत इलैक्ट्रौनिक्स और इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के, जो मैसूर में बड़ी सफलता से चल रही हैं, प्रसार के बजाए उनमें और अधिक असन्तुलन क्यों पैदा किया जा रहा है? धन के बराबर बटवारे से पिछड़े वर्गों को क्यों नहीं ऊपर उठाया जाता? क्या ये सब समितियां आवश्यक हैं।

श्री फ० अ० अहमद : प्रत्येक राज्य को शिकायत हो सकती है कि अमुक चीज नहीं की गई। हमारे पास सीमित साधन हैं और इन साधनों को कच्चे माल की उपलब्धि तथा अन्य साधनों पर निर्भर रहते हुये अनेक स्थानों और अनेक परियोजनाओं में लगाया हुआ है। मुझे इससे प्रसन्नता होगी यदि आदरणीय सदस्य इन क्षेत्रों में बिना भेदभाव की भावना से लगाने के लिये मुझे धन दें.....(**विरोध....**)

Shri Shiv Narain : Mr. Speaker, the Hon. Minister for Industry has expressed lame excuse that it is beyond his responsibility. I come from a poor area of Uttar Pradesh and Hon. Minister also represents same type of poor area i. e. Assam. We have brass and cloth Industry. As the Hon. Minister has said that those who ask they would be given. So we ask you to help us in the development of these Industries. I may ask whether the Central Government is ready to help us in this matter.

श्री फ० अ० अहमद : इन सब समस्याओं पर विचार हो रहा है।

Shri Ramavatar Shastri : Before the report of the Council is received, I want to know from the Government, whether the attention has been paid to the backward Industries of Bihar state particularly Northern backward area of Bihar. I also want to know whether any enquiry

has been conducted in this connection? Secondly, the whole of the area between Patna and Benaras is lying bare, no industry, no factory is there. In this connection I put up a question before the Government in this house but no satisfactory reply have been given by the Government. I want to know, whether Government has any proposal to set up any Industry in the area of Bihar lying bare betwen Patna and Benaras? Besides, as I said the area of North Bihar is the most backward area, people living there, worker and Industrialist alike, asking for help but Government is not ready for that. What are the reasons for all this? Is it a fact that there is any plan proposal in this direction?

Shri F. A. Ahmed : The Hon. Member has mentioned about the part that comes within these two States. As regards Bihar, enough investment has been made during the last three Five Year Plans. Many big industries have been established there .....(**interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा देश के प्रत्येक भाग से सम्बन्धित है। प्राय: 50 सदस्य और प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा अगले बीस मिनट में भी हम इस प्रश्न को पूरा नहीं कर पायेंगे। दलों के नेता भी इस बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। व्यवस्था रखिये। सभी सदस्य बैठ जायें। आप केवल सामान्य प्रश्न पूछिये और उसका सामान्य उत्तर ही दिया जायेगा। बाद में बजट और अनुदान के लिये मांगें भी पेश की जायेंगी। आप हर अनुपूरक प्रश्न करके मंत्री महोदय से 30 या चालीस करोड़ रुपये नियत नहीं करा सकते। उनके लिये शायद यह सम्भव न हो सकेगा। अब अगला प्रश्न लीजिये।

तम्बाकू बोर्ड

+

*154. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री नम्बियार :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू की खेती तथा उसके निर्यात व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये तम्बाकू बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन कब तक किया जायेगा; और

(ग) बोर्ड के कृत्य क्या होंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री ई० के० नायनार : जहां तक मुझे ज्ञात है, पिछले दिसम्बर में भारत सरकार ने पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत अमरीका से 200 टन तम्बाकू का आयात करने का निश्चय किया था। तम्बाकू के उत्पादन के बारे में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहां की

कुल पैदावार का 68 प्रतिशत आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न होता है। अब केरल के उत्तरी भागों ने तम्बाकू पैदा करना आरम्भ कर दिया है। मैसूर भी तम्बाकू उत्पन्न करता है।

एक माननीय सदस्य : असम में भी उत्पन्न होता है।

श्री ई० के० नायनार : तम्बाकू उद्योग में पूंजीपतियों का बोलबाला है क्योंकि इस उद्योग में लगी अधिकतम पूंजी विदेशी पूंजीपतियों तथा अन्य लोगों की है। तम्बाकू उत्पादकों को केवल राज्य सरकारें ही सहायता देती हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से तम्बाकू उत्पादकों को सीधे ही सहायता देने अथवा इस उद्योग में प्रगति करने हेतु कोई संस्थान नहीं स्थापित किया गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार देश के तम्बाकू उत्पादकों को सीधे ही सहायता देने हेतु केन्द्र में कोई तम्बाकू-बोर्ड-अर्थात् एक केन्द्रीय बोर्ड—स्थापित करेगी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस बोर्ड से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन है। अभी हाल ही में एक उप-समिति ने इस बारे में विचार किया था तथा उसने भी इसकी सिफारिश की है। हम खाद्य और कृषि मंत्रालय से सम्पर्क बनाये हुए हैं। इस बोर्ड के गठित होने तक खाद्य और कृषि मंत्रालय ने विकास, बिक्री तथा अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान सभी प्रबन्ध जुटा लिये हैं, और इस एक-मात्र एजेन्सी को सुदृढ़ कर लिया है जिसके माध्यम से यह मंत्रालय तम्बाकू की खेती, बिक्री तथा अनुसन्धान में सहायता देना चाहता है।

श्री ई० के० नायनार : पिछले वर्ष सरकार ने तम्बाकू का निर्यात सम्बन्धी उपदान 20 से 25 प्रतिशत बढ़ा दिया तथा इसके मूल्य 88% बढ़ गये। परन्तु इसका लाभ उत्पादकों को सीधे नहीं पहुंचा। बीच के लोग ही इस लाभ का अधिकतम भाग पा रहे हैं। इसीलिये तो मैंने सरकार से कहा है कि बीच के लोगों तथा बड़े-बड़े एकाधिकार-प्राप्त व्यापारियों के लिये नहीं बल्कि तम्बाकू उत्पादकों को सहायता देने के लिये सरकार इस बोर्ड का गठन करे। मैं इस बारे में विशिष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार तम्बाकू उत्पादकों को शामिल करके एक बोर्ड का गठन करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसके लाभ बीच के व्यक्तियों तथा एकाधिकार-प्राप्त लोगों को नहीं प्राप्त होने चाहिये बल्कि उत्पादकों को ही प्राप्त होने चाहिये। इन कार्यों को करने के लिये बनी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की यह एजेन्सी एक सरकारी एजेन्सी है, और एकाधिकार-प्राप्त व्यक्तियों की नहीं। यह एजेन्सी सीधे उत्पादकों के लिये ही कार्य करेगी।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि उचित बाजार के अभाव में भारी मात्रा में तम्बाकू अभी तक रुका पड़ा है। तथा विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों व व्यापारियों के लिये एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ? इस तम्बाकू को उठवाने तथा उत्पादक को उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि तम्बाकू का उत्पादन बढ़ रहा है। इसके निर्यात करने तथा देश में ही इसकी खपत बढ़ाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि वे भण्डार उठवाये जा सकें। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी हाल ही में वर्ष 1968-69 में तम्बाकू का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि इस देश में अनेक विदेशी एजेन्सियां कार्य कर रही हैं तथा वे उत्पादकों को दृढ़ता से जकड़े हुए हैं ? उत्पादक-गण बड़े त्रस्त हैं क्योंकि यह सम्भव नहीं कि विदेशी एजेन्सियों के पंजे में आये बिना उनके भण्डारों का निर्यात हो सके। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड को गठित करने में सरकार इतना लम्बा समय क्यों ले रही है ? क्या मैं जान सकता हूं कि यह बोर्ड कितनी जल्दी गठित कर दिया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा है, खाद्य व कृषि मंत्रालय ऐसे बोर्ड के गठन को आवश्यक या सुविधाजनक नहीं समझता। तम्बाकू सम्बन्धी उत्पादन से लेकर निर्यात तक के बिक्री सहित सभी कार्य-कलापों को उस मंत्रालय ने अपनी ही एजेन्सी के अधीन समन्वित कर दिया है ताकि एक सामूहिक तथा समन्वित ढंग से कार्य किया जा सके। उन्होंने उत्पादकों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर रखा है। इसलिये, कृषि मंत्रालय समझता है कि ऐसे किसी बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उप-समिति ने इसकी सिफारिश की है। हम भी ऐसे बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय को राजी करने हेतु उससे सम्पर्क बनाये हुए हैं परन्तु अभी तक उस मंत्रालय ने यह स्वीकार नहीं किया है।

श्री रंगा : यह समस्या काफी समय से चली आ रही है तथा अकेले कृषि मंत्रालय से इसके समाधान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में तो वाणिज्य मंत्रालय को इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि देशी बाजार की तुलना में यह उद्योग निर्यात पर कहीं अधिक निर्भर करता है।

जहां तक देश की मण्डियों का सम्बन्ध है किसान, व्यापारी तथा अन्य व्यक्तियों में अपने हितों की देख-भाल करने की क्षमता है तथा राज्य सरकारें भी उनकी कुछ सहायता करती हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय अधिक उत्तरदायी है। मैं गत कई वर्षों से इस दिशा में आन्दोलन कर रहा हूं। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय पर प्राथमिक उत्तरदायित्व को छोड़कर अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लेता है जिसके परिणामस्वरूप विक्रय, माल का संचय और व्यापार में दिक्कत जैसी स्थानिक समस्याएं पैदा हुई हैं। क्या वह समय नहीं आया है जबकि कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर वाणिज्य मंत्रालय अपने उत्तरदायित्व को निभाने पर बल दे जिससे कि यह बोर्ड स्थापित हो सके तथा वह इन दोनों मंत्रालयों का प्रति-निधित्व कर सके। साथ ही सम्बद्ध राज्य सरकारों के इसी प्रकार के विभागों के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होकर उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। तब इस बोर्ड को कृषि-सम्बन्धी-सुधार और

उत्पादन आदि का उत्तरदायित्व ही न देकर प्रमुखतः निर्यात को बढ़ावा देने का विशिष्ट उत्तर-दायित्व भी सौंप सकते हैं। दूसरे, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय भाण्डागार अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कुछ किया जा रहा है या किया जायेगा ? इस तरह जैसे ही संचित माल की मात्रा एक खास सीमा से ऊपर बढ़े तो वे उन्हें अपने अधिकार में कर लें तथा भारत सरकार, रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक उसे ऋण दे दें। ऐसा करने से माल के संचित होने पर भी उत्पादकों तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा हो जायेगी।

श्री ब० रा० भगत : सुझाव के अन्तिम भाग की मैं जांच करूंगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इस पण्य के निर्यात के हित में यह आवश्यक है कि किसानों को बीज बोने के स्तर से लेकर विकास, विपणन, अनुसंधान तथा निर्यात तक सहायता दी जानी चाहिए। यह सभी कार्य करने हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार का बोर्ड लाभकर रहेगा। लेकिन हमें कृषि-मंत्रालय को समझाना है क्योंकि वही इससे मुख्य रूप से सम्बन्धित है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस बारे में प्रयत्न करेंगे। इसी बीच में ऐसे सभी प्रश्नों को संघटित रूप से हल करने तथा प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए कृषि-मंत्रालय ने कदम उठाये हैं। इस समय की यही स्थिति है।

श्री म० सुदर्शनम् : क्या मैं जान सकता हूं कि किसानों और व्यापारियों के पास तम्बाकू के भारी संचय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का अन्य देशों के साथ वस्तु-विनिमय करने का प्रस्ताव है ?

श्री ब० रा० भगत : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : जैसा कि श्री रंगा ने कहा है, यह तम्बाकू समस्या बहुत दिनों से चल रही है। तम्बाकू से भारी विदेशी विनिमय अर्जित होती है। अतः पहले तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जब इसकी कीमत एक विशिष्ट स्तर से नीचे गिरे तो स्वयं सरकार या राज्य व्यापार निगम उसके स्टाक को ले लें तथा दूसरे यह ध्यान रखेगी कि देश में उत्पादित हुए तम्बाकू के प्रत्येक पत्ते का निर्यात हो जाय। तथा निर्यात में वृद्धि करने के ख्याल से क्या सरकार विशेषकर महिलाओं और संसद् सदस्यों के लिए धूम्रपान का निषेध करना भी चाहेगी ?

श्री मनुभाई पटेल : विभिन्न मंत्रालयों में उचित समन्वय की कमी के कारण तम्बाकू उगाने वाले किसान घाटा उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए बीड़ी में घटिया किस्म के तम्बाकू की पत्तियों को उपयोग करने की इजाजत नहीं है किन्तु उनमें डण्ठल आदि का उपयोग किया जा सकता है। पत्तियों पर उत्पाद शुल्क उगाहा जाता है जबकि डण्ठल और नाल और भी घटिया होते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह मंत्रालय सम्बद्ध मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलायेगा ? देश में तम्बाकू विकास परिषद् बनी हुई है। क्या ऐसी समस्याएं उसके समक्ष रखी जायेंगी ? उत्तरीय गुजरात में घटिया किस्म का तम्बाकू उगाया जा रहा है और उनके पास भारी मात्रा में माल

संचित है जिसे कोई भी नहीं उठा रहा है। यह गम्भीर समस्या है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन समस्याओं को तम्बाकू विकास परिषद् के समक्ष रखेगी ?

श्री ब० रा० भगत : समन्वय-समस्या को बहुत सशक्त किया जा चुका है। उत्पाद-शुल्क लगाने का कार्य वित्त मंत्रालय का है। इस समस्या पर कभी भी विचार करते समय हमारा वित्त मंत्रालय तथा कृषि-मंत्रालय के साथ सदा ही समन्वय रहता है।

श्री तिरुमल राव : खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय के अन्तर्गत एक केन्द्रीय तम्बाकू समिति थी। सम्भवतः जब श्री सुब्रामानियम मंत्री थे तब यह वस्तु समितियों के सम्पूर्ण उन्मूलन के अन्तर्गत आ चुकी है। मैं नहीं जानता कि यह अब भी कार्य कर रही है अथवा नहीं। मद्रास में भी एक अन्य संघटन है जिसका नाम है तम्बाकू निर्यात वर्धन परिषद् (Tobacco Export Promotion Council) बढ़िया किस्म के तम्बाकू की खेती में उन्नति के लिए राजमुन्द्री स्थित केन्द्र के समान ही अन्य बहुत से अनुसंधान केन्द्र हैं। चूंकि तम्बाकू की पैदावार से अधिक मूल्य की प्राप्ति होती है इसीलिए देश भर में बिना विचारे उसे उगाया जा रहा है तथा खाद्यान्न की अवहेलना की जा रही है। तम्बाकू की इसी विवेक शून्य पैदावार के कारण उत्पादकों के पास विभिन्न किस्म का तम्बाकू बड़ी मात्रा में संचित पड़ा है। संघटन ने तम्बाकू के क्रम में कुछ राजनीति का भी समावेश कर दिया है। क्या मंत्री महोदय इन सभी मामलों की जांच करेंगे तथा उद्योग को उचित मार्ग पर गठित करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक निर्यात वर्धन परिषद् का सम्बन्ध है वह पूरी तरह से विद्यमान है तथा निर्यात और अन्य मामलों पर वह हमें सलाह दे रही है। किन्तु जहां तक प्रश्न तम्बाक के सम्बन्ध में केन्द्रीय समिति का है, वह कृषि-मंत्रालय के अन्तर्गत आती है।

कच्चे पटसन के मूल्य

*155. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे पटसन के मूल्य स्थिर करने की किसी योजना के न होने के कारण पटसन के मूल्यों में प्रतिवर्ष उतार-चढ़ाव होता रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कच्चे पटसन के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते हैं जो आपूर्ति तथा मांग की स्थिति पर तथा तैयार माल की सामान्य बाजार दशाओं पर निर्भर होते हैं।

(ख) प्रत्येक वर्ष पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के अतिरिक्त प्रत्येक मास में कच्चे पटसन की अनुमानित प्राप्यता को ध्यान में रखते हुये मिलों द्वारा खरीद तथा

भंडारण के लिये संविधिक कोटे निर्धारित किये जाते हैं। मूल्य-समर्थन देने के लिये समीकरण भंडार भी खोले जाते हैं। कच्चे पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : 12 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3926, जिसका एक अंश इस प्रकार था कि "क्या यह समझा जाता है कि जूट की अलाभकारी कीमत के कारण अगले वर्ष इसकी काश्त घट जायेगी", के उत्तर में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि "किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये जिससे कि वह जूट का उत्पादन बढ़ाएं उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को गत मौसम की तुलना में इस मौसम में 93 रुपया 75 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 107 रुपया 14 पैसा कर दिया गया है।" क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या वह योजना अब भी लागू है, और यदि हां तो, चालू मौसम के लिये समर्थन मूल्य क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : 35 रुपया से बढ़ाकर 40 रुपया कर दिया गया है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : किसी विशेष वर्ष में जूट के उत्पादन में कमी होने के कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है जिससे अगले वर्ष किसान जूट की काश्त बढ़ा देते हैं और फिर उसकी कीमत गिर जाती है। इस प्रकार काश्तकारों को हानि उठानी पड़ती है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार संचित भण्डार बनाने जा रही है तथा क्या कुछ जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है जिससे कि भारतीय जूट मिल एसोसिएशन की नीति तानाशाही न हो सके ? इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने 15 दिसम्बर, 1967 के प्रश्न के उत्तर की ओर दिला सकता हूं जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जूट मिल संस्था ने भारत सरकार से पाकिस्तान से जूट का आयात करने का निवेदन किया है। यद्यपि भारत में जूट का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है तथापि उन्होंने अपने हितों के लिये सरकार के ऊपर दबाव डाला है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या सरकार भविष्य में ऐसे दबावों का प्रतिरोध करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : हमने इस प्रकार के दबावों का प्रतिरोध किया है। यह सच है कि एकान्तर वर्षों में जूट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने से उसके मूल्यों में गिरावट आ जाती है। इसीलिए रक्षित भण्डार बनाकर हमने बाजार को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया है। यह आवश्यक है कि जिस वर्ष उत्पादन अच्छा हो उस वर्ष रक्षित भण्डारों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाय जिससे कि स्थिरता बनी रहे। यह सच है कि जूट का सामान पूर्णतः निर्यात की वस्तु है। पिछले वर्ष जूट के सामान का उत्पादन बहुत अच्छा था किन्तु उसके निर्यात की मांग कम होने के कारण मिलें पूरा लाभ नहीं उठा सकीं तथा रक्षित भण्डारों के बावजूद भी कच्चे जूट का बाजार गिर गया। किन्तु इस वर्ष कम उत्पादन के कारण जूट का मूल्य ऊंचा है। इस परिस्थिति को स्थिरता लाने के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। अर्थात् जब पूर्ति की मात्रा अधिक हो तो रक्षित भण्डारों को बढ़ा दिया जाय तथा जिस वर्ष उत्पादन कम हो तो उस वर्ष भण्डारों से माल का

मोचन कर दिया जाय । हम इसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं । मेरे विचार से इस विधा में राष्ट्रीयकरण करना उपयोगी नहीं रहेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की सूचना मिल गई है कि भारतीय जूट मिल संस्था ने पश्चिमी बंगाल में 40,000 जूट कर्मचारियों की छटनी करने का या उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय किया है ? मुझे ज्ञात हुआ है कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है । उस समय वहां राष्ट्रपति शासन था तथा राज्यपाल भारतीय जूट मिल संस्था से मिल गये थे । इस कुचेष्टा को रोकने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ।

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न श्रम मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय : माननीय मंत्री महोदय को इस प्रश्न की प्रत्याशा की जानी चाहिए थी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी सम्भावना नहीं थी ।

श्री बेदब्रत बरुआ : मेरा विचार है कि इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा कि पिछले वर्ष कुछ प्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम हुआ । कारण यह है कि गत वर्ष जो मूल्य प्रस्तावित किया गया था वह कम था । जहां तक जूट पैदा करने वालों का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि मूल्य की स्थिति पूर्णरूप से अस्त व्यस्त है । एक वर्ष कम उत्पादन के कारण मूल्य ऊंचे हो जाते हैं और दूसरे वर्ष ऊंचे मूल्यों के कारण लोग दूनी मात्रा में उत्पादन करना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे पुनः कीमतें गिर जाती हैं और किसानों को घाटा उठना पड़ता है । इस प्रकार की परिस्थिति को नहीं रहने दिया जाना चाहिये तथा इस विषय में अनेक सुझाव दिए जा चुके हैं कलकत्ता के किसानों से भाड़े आदि के कारण असम के किसानों को जूट का मूल्य लगभग 8 रुपया अधिक मिलता है । जहां तक रक्षित भण्डार बनाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि गत कई वर्षों में उनसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली । मैं जानना चाहूंगा तथ्यतः सरकार ने क्या करने की सोची है । क्या वह कुछ मिलों के राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी तथा चीनी की तरह ही जूट भी किसी निश्चित मूल्य पर प्राप्त करेगी और कुछ अन्य उपाय भी करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : उदाहरण के लिए गत वर्ष 75 लाख गांठों (बण्डलों) का उत्पादन हुआ था । समर्थन मूल्य 40 रुपया दिया गया था जोकि सब वर्षों से ऊंचा था । संस्था ने लगभग 6 लाख गांठों का रक्षित भण्डार बनाया था तथा राज्य व्यापार निगम ने समर्थन मूल्य पर 3,44000 गांठें खरीदी थीं । यदि इसकी सुव्यवस्था हो जाय तथा संस्था या राज्य व्यापार निगम समर्थन मूल्य पर और अधिक संचित भण्डार बनायें तो समस्या का समाधान हो जाएगा । राष्ट्रीयकरण या अन्य उपाय इस स्थिति को सम्भालने में उपयुक्त नहीं हो सकते ।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या यह सच है कि विशेषकर अच्छे किस्म के जूट की संसार व्यापी कमी है तथा भारतीय मिलें अच्छे जूट की कमी के कारण उत्पादन में भारी घाटा उठा रही हैं ? यदि यह सच है तो राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस को भारत का बढ़िया जूट निर्यात करना कहां तक न्यायसंगत है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि इस वर्ष जूट की देशव्यापी कमी रही । केवल हमारा ही नहीं पाकिस्तान और थाईलैंड का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है । जहां तक जूट के निर्यात का सवाल है, सम्भव है वह पहले वायदों के परिणामस्वरूप किया गया हो ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : नहीं । यह कोई नई घटना नहीं है । उत्तम कोटि के जूट की कमी गत पांच वर्षों से चली आ रही है । इस घटना को ध्यान में रखते हुए यह कहां तक न्यायोचित है कि सरकार अच्छे जूट का निर्यात करे जिसकी देश में बहुत आवश्यकता है ।

श्री एम० नारायण रेड्डी : अगला प्रश्न ट्रैक्टरों के बारे में है जो बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने दिया जाय ।

श्री ब० रा० भगत : रूस को कितना जूट निर्यात किया गया इस विषय में मुझे पूरी सूचना नहीं है । मैंने केवल यही कहा है कि हो सकता है पूर्व वायदों के कारण निर्यात किया गया हो ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह उत्तर तो कल्पना पर आधारित है ।

श्री बलराज मधोक : हमारा देश संसार के सर्वाधिक जूट उत्पादक देशों में से है । इसके बावजूद भी हमारे जूट के निर्यात में कमी आने के प्रतिवेदन मिल रहे हैं । भारतीय जूट मिल संस्था ने कहा है कि उसे प्रतिदिन 2 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है । यदि यही स्थिति रही तो उद्योग को भारी हानि उठानी पड़ेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जूट के उत्पादन, समर्थन मूल्य और निर्यात में कमी आने में कोई पारस्परिक सम्बन्ध है और यदि है तो इन कठिनाइयों को दूर करने तथा निर्यात को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक मूल्य उत्पादन लागत पर आधारित रहता है और समर्थन मूल्य निर्यात बाजार पर, इनमें पारस्परिक सम्बन्ध है । यह सत्य है कि हमारे जूट के निर्यात में कमी आई है । किन्तु इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान से प्रतियोगिता, और अनेक कारणों से पाकिस्तान इसमें हमसे ज्यादा फायदे में रहा है । एक मुख्य कारण संश्लिष्ट (सिन्थैटिक्स) से प्रतियोगिता भी है । अतः इसका उत्तर यही है कि उत्पादन में विविधता लाने का प्रयत्न किया जाय तथा कारपैट पैकिंग और अन्य ऐसी चीजों का विकास किया जाय जिनसे निर्यात बाजार में हमें अब भी लाभ प्राप्त है । इसी का हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

New Tractor Factories

*156. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of new tractor manufacturing factories set up since the abolition of the licensing system for tractor industry ;

(b) the production capacity and the location of each such factory ; and

(c) when the production is likely to be started in each factory ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). A statement is attached.

Statement

Ten proposals have been received for setting up factories for the manufacture of tractors since the industry was delicensed in February, 1968. These proposals are at various stages of approval, processing or consideration. The capacity and location envisaged in respect of each of these proposals is as follows :

Serial Number	Annual capacity envisaged	Location
(1)	(2)	(3)
1.	12,000 Nos.	Ludhiana
2.	10,000 Nos.	Loni (U. P.)
3.	10,000 Nos.	Moradabad (U. P.)
4.	10,000 Nos.	Hyderabad
5.	10,000 Nos.	Hyderabad
6.	5,000 Nos.	Hyderabad
7.	6,000 Nos.	Faridabad
8.	10,000 Nos.	Poona
9.	5,000 Nos.	Patiala
10.	10,000 Nos.	Hyderabad

None of the schemes has yet reached the stage at which the actual construction can be taken on hand or production established. It is, therefore, difficult to state at this stage when each of the schemes will go into production.

मैसूर सीमेंट लिमिटेड

*157. **श्री क० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्या थी ;

(ख) इस कम्पनी ने 31 मार्च, 1968 तक केन्द्रीय सरकार, बैंकों या अन्य संस्थाओं से पृथक-पृथक कितना ऋण लिया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इसने कितना कार्य किया और इसमें क्या अनियमिततायें पाई गयीं और यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स मैसूर सीमेंट लिमिटेड, 3 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी सहित, 13 मई, 1956 को, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के नाम से पंजीकृत की गई थी। 30 जून, 1959 की वर्ष समाप्ति के इसके प्रथम तुलन-पत्र के अनुसार इसकी प्रदत्त पूंजी 3,800 रुपयों की हुई, जबकि इसकी अधिकृत पूंजी 3 करोड़ की अपरिवर्तनीय ही रही। 30 जून, 1968 को इसकी प्रदत्त पूंजी, 249.9 लाख रुपयों की राशि की थी।

(ख) 30 जून, 1968 तक कम्पनी पर 2.82 करोड़ रुपयों का ऋण शेष था। यह ऋण, स्टेट बैंक आफ मैसूर का 10 लाख रुपयों, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का 48 लाख रुपयों, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक वाशिंगटन का 39 लाख रुपयों, तथा एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट, वाशिंगटन का 1.85 करोड़ रुपयों, की राशि के थे।

(ग) कम्पनी ने करों से पहले, 1965-66 में 16.7 लाख रुपयों, 1966-67 में 52.3 लाख रुपयों, तथा 1967-68 में 27.9 लाख रुपयों का लाभ उठाया। सरकार के नोटिस में अभी तक कोई अनियमिततायें नहीं आई हैं।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर

*158. **श्री ए० श्री धरन :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ली जाने वाली शाखाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस समय उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है और इसे अपने नियंत्रण में लेने में सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख). जैसाकि तारांकित प्रश्न संख्या 3 (दिनांक 18 फरवरी, 1969) के उत्तर में कहा गया था, सरकार ने, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कूपर एलन तथा नार्थ-वेस्ट टैनरी एककों को, अपने अधिकार में लेने का निर्णय कर लिया है।

(ग) कम्पनी का, 1968 के वर्ष का लेखा-परिक्षित लेखा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु वर्तमान में विभाग के पास उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कम्पनी ने, जून 1968 तक की अर्ध वर्ष समाप्ति की अवधि में, कूपर एलन, तथा नार्थ-वेस्ट टैनरी शाखाओं पर लगभग 48 लाख रुपयों की हानि उठाई।

14 फरवरी, 1969 को की गई, निगम की असामान्य-साधारण बैठक में, हिस्सेधारियों ने, निम्नलिखित शर्तों पर, उपरोक्त दोनों एककों को सरकार को हस्तांतरित करने का अनुमोदन कर दिया है।

(1) इन दोनों एककों की स्थिर परिसम्पत्ति, जिसमें, भूमि, भवन, यंत्र व मशीनरी तथा अन्य परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के प्रबन्धकों द्वारा, एक रुपये के नाम मात्र के मूल्य पर नई कम्पनी को सौंप दी जायेगी।

(2) कच्चे माल का संग्रहण, भंडार, फालतू पुज तथा चालू कार्य, जो प्रयोज्य समझा जाय, उस मूल्य पर, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये तकनीकी समूह के साथ, संयुत, शासप्राप्त लेखाकारों की एक फर्म, मैसर्स एस० आर० बाटलीवाय एण्ड कम्पनी द्वारा निर्धारित किया जाय, नई कम्पनी द्वारा ले लिया जायेगा।

(3) नई कम्पनी ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के बिक्री से पूर्व की तिथि के, ऋण, अग्रिम के रूप में कर्ज, तथा खर्च की गई देयता, चाहे वह वास्तविक, संभाव्य अथवा अन्य प्रकार की हो, किसी के लिये उत्तरदायी नहीं होगी। ये सभी प्रकार के उत्तरदायित्व, कारपोरेशन द्वारा इस ढंग से व्यवहारित किये जायेंगे, जो वह इस उद्देश्य के लिये उचित समझें। उसी प्रकार नई कम्पनी, बिक्री से प्रथम की तिथि के निगम की उपरोक्त शाखाओं द्वारा लिये गये जमा तथा अग्रिमों को भी ग्रहण नहीं करेगी।

(4) बिक्री की तिथि पर वर्तमान तैयार भंडार को भी नई कम्पनी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) नई कम्पनी द्वारा ग्रहण किये गये कर्मचारियों की बाबत नई कम्पनी, उनके उत्पादन के बारे में, पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी, तथा इस प्रकार ग्रहण किये गये कर्मचारी, पहले की उपार्जित छुटिट्यों के लाभ के हकदार होंगे। जो लोग नई कम्पनी द्वारा ग्रहण नहीं किये गये हैं, उनके लिये, कारपोरेशन, उनके उपदान सहित, देयता तथा यदि कोई छटनी भत्ता हो तो, चुकाने के लिये उत्तरदायी होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे की रेलगाड़ियों में डकैती

*159. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 के उत्तरार्ध में पूर्वोत्तर रेलवे में बरौनी और तेघरा स्टेशनों के बीच चलती हुई 311-अप हावड़ा जाने वाली समस्तीपुर यात्री गाड़ी में सशस्त्र व्यक्तियों ने डाके डाले और अन्तिम डकैती 30 दिसम्बर, 1968 को द्वितीय श्रेणी के एक डिब्बे में पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो इन डकैतियों का पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पहली दो डकैतियों को देखते हुए पिछली डकैती के समय रेलगाड़ी में पुलिस नियुक्त की गई थी ;

(घ) हताहतों की यदि कोई क्षतिपूर्ति की गई है, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) ऐसी डकैतियां पुनः न होने देने के लिए और यात्रियों की जान व माल की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिसम्बर, 1968 के दूसरे पखवाड़े में इस गाड़ी में डकैती की दो घटनाएं घटीं। पहली घटना पूर्व रेलवे में बरौनी जंक्शन और मोकामा के बीच 21-12-1968 को और दूसरी घटना पूर्वोत्तर रेलवे में बरौनी जं० और टेघरा के बीच 30-12-1968 को घटी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें दोनों घटनाओं का ब्योरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 120/69]

(ग) जी हां। सरकारी रेलवे पुलिस, बरौनी का एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल इस गाड़ी में चल रहे थे।

(घ) कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गयी है।

(ङ) सरकारी रेलवे पुलिस और बिहार मिलिटरी पुलिस के सशस्त्र अनुभाग के अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय स्थलों पर कैम्प करते हैं ताकि आकस्मिक छापे मारकर अपराधियों को पकड़ा जा सके। अब रात की सभी सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारी चलते हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में, गाड़ियों में बिहार मिलिटरी पुलिस के सशस्त्र दस्ते भी तैनात किये जाते हैं।

Loss to Heavy Engineering Corporation, Ranchi

*160. **Shri Suraj Bhan:**
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Sitaram Kesri:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the total amount of capital invested in the Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi so far;

(b) the total amount of loss suffered so far and the amount of loss suffered in 1967-68;

(c) the causes of the loss;

(d) the steps taken by Government in this regard and the result thereof; and

(e) whether it is a fact that there has been delay in supplying material for defence purposes and if so, the reasons therefor?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha): (a) The total investment as on the Ist December, 1968 amounts to Rs. 213.69 crores of which Rs. 100 crores is in the form of equity Capital and Rs. 113.69 crores is in the form of loans.

(b) The total accumulated loss upto the 31st March, 1968 is Rs. 25.57 crores. Of this, the loss during the year 1967-68 came to Rs. 15.9681 crores.

(c) The period during which these losses were incurred constituted the construction period and the early gestation years during which production commenced and was gradually being built up. Projects of this nature and size inevitably have a long gestation period during which skills and productivity can only gradually be improved.

(d) Government have taken a number of steps, from time to time, to increase production and productivity in the HEC. These include, inter-alia, steps to complete the Foundry Forge Plant as early as possible in order to ensure a regular flow of castings and forgings, close co-ordination between the Foundry Forge Plant and the other two units of the HEC, including the appointment of a Director of Co-ordination for the purpose, strengthening of the production planning unit, more intensified training courses together with a number of other measures.

(e) Certain orders from Defence establishments were received by the H. E. C. and are under implementation. In some of these cases, it has been found necessary to revise the delivery period for some of the supplies as the manufacturing time-cycle was found to be much longer than had been anticipated earlier.

लोहे और इस्पात के लिये पुंज मूल्य

*161. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से लोहे तथा इस्पात का पुंज मूल्य, जो सारे देश में लागू हो, निर्धारित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) बहुत समय से प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादित लोहा और इस्पात रेल पर्यन्त सभी स्थानों पर समान दरों पर बेचा जाता है।

नागपत्तनम् इस्पात बेलन मिलें

*162. **श्री के० रमानी :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि नागपत्तनम् इस्पात बेलन मिल्स, मद्रास के प्रबन्धकों ने इस मिल को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसे बन्द करने का एक कारण इस्पात का न मिलना है और

(घ) यदि हां, तो इस्पात की सप्लाई बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स, नागपत्तनम् के प्रबन्धकों का बेलन मिलों को बन्द करने का विचार था। उन्होंने इसके निम्नलिखित कारण बताये थे।

(i) कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति ;

(ii) अधिक परिचालन-व्यय ; और

(iii) उपक्रम के अभाव में तैयार माल के विक्रय में असमर्थता।

(घ) फर्म के 1967-68 में लगभग 2000 टन बिलेट प्रतिमास के अपक्रय की तुलना में अक्तूबर से दिसम्बर 1968 की अवधि में फर्म को 6,936 टन बिलेट प्रेषित किये गये हैं और यह भी प्रबन्ध किया गया है कि जनवरी, 1969 से इनको प्रतिमास 2670 टन के हिसाब से बिलेट दिये जायें।

कम्पाला (उगांडा) में चाय उत्पादक देशों का सम्मेलन

*163. **श्री म० सुदर्शनम् :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पाला (उगांडा) में चाय-उत्पादक देशों के हाल में हुए सम्मेलन में लन्दन के बाजार में चाय की नीलामी की प्रणाली के बारे में विचार-विमार्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में और किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा उसने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ वे निम्नलिखित हैं :—

(1) चाय की वर्तमान स्थिति तथा उसकी अल्पकालिक सम्भावना ।

(2) उत्पादन तथा उपभोग के लिए दीर्घकालीन सम्भावना ।

(3) चाय उपभोग में प्रवृत्तियां ।

(4) विश्व चाय बाजार की सम्भावना और विपणन की समस्याएं ।

(5) चाय पर प्रभाव डालने वाले शुल्क, कर तथा अन्य सरकारी कार्य ।

(6) चाय के सम्बन्ध में आंकड़ों की समस्याएं ।

(7) चाय उपभोग को बढ़ाना ।

(8) चाय उद्योग की समस्याओं के प्रति संभावित अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ।

सम्मेलन ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की सिफारिश की है जो निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन करके संयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करेगा : अर्थात् चाय का संवर्द्धन, विपणन व्यवस्थाओं में उन कारणों को दूर करने के लिए सुधार जिनसे मूल्य में मन्दी आती है, और ऐसे मूल्य प्राप्त करने के लिये जोकि उपभोक्ताओं के लिए उचित व उत्पादकों के लिए लाभकारी होंगे और निर्यातिक देशों के लिए निर्यात उपार्जनों का उपयुक्त स्तर तैयार करेंगे, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भाव्यता तथा उसके लिये एक योजना के मसौदे के व्यावहारिक ब्योरे ।

(ग) भारत कार्यकारी दल का एक सदस्य है जिसमें 7 अन्य उत्पादक देश तथा 8 आयातक देश हैं और वह कार्यकारी दल की स्थापना हो जाने पर उसके कार्य-कलापों में भाग लेगा ।

काफी उद्योग का विकास

*164. **श्री अबिचन :**

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काफी उद्योग के विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य क्या हैं तथा प्रत्येक काफी उत्पादक राज्य में इस कार्यक्रम के अन्य ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) उक्त काफी विकास कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं का वित्तीय परिव्यय क्या है तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का क्या अंशदान है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हाँ ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1973-74 के लिये काफी के उत्पादन तथा निर्यात के प्रस्तावित लक्ष्य क्रमश: 1,00,000 मे० टन तथा 41,500 मे० टन हैं । जहां तक काफी उद्योग के विकास के लिये कार्यक्रम के ब्योरों का सम्बन्ध है, एक विवरण संलग्न है । इन कार्यक्रमों को राज्यवार न बनाया जाकर कुल काफी उद्योग के लिये बनाया गया है ।

(ग) योजना को अन्तिम रूप देते समय वर्तमान काफी विकास योजना तथा काफी पुनर्रोपण योजनाओं के लिये वित्तीय परिव्यय निर्धारित किये जायेंगे । काफी उत्पादक राज्यों से कोई अंशदान लेने का विचार नहीं है ।

काफी उद्योग के विकास के लिये कार्यक्रम का ब्योरा निम्नलिखित है :—

विवरण

काफी विकास योजना

(1) गहन खेती के लिये छोटे उत्पादकों को दीर्घावधि ऋण ।

(2) किराया-खरीद की शर्तों पर मशीनें तथा उपकरण प्राप्त करने के लिये बागानों को माध्यमिक अवधि के ऋण ।

(3) कार्यकारी पूंजी के लिये बागानों को अल्पावधि ऋण ।

काफी पुनर्रोपण योजना

पुराने तथा कम उपज देने वाले काफी के पौधों का पुनर्रोपण करने के लिये बागानों को दीर्घावधि ऋण ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रेशमी कपड़े का निर्यात

*165. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग के विद्युत चालित

करघों के मालिकों ने राज्य व्यापार निगम द्वारा कृत्रिम रेशम के कपड़े के निर्यात करने की प्रणाली की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी आलोचना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस उद्योग को पुनः गति प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). अमृतसर के कृत्रिम रेशम बुनाई संघों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मुख्यतः विस्कोस रेयन धागे के ऊंचे मूल्यों तथा सैलूलोसिक कृत्रिम रेशम के कपड़े तथा नायलोन कपड़े के लिये वर्तमान निर्यात संवर्धन योजनाओं के कार्यचालन के विरोध में शिकायत की गई है ।

(ग) टैरिफ आयोग को विस्कोस रेयन मूल्यों के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये पहले ही कहा जा चुका है, जिसके मार्च 1969 के मध्य तक मिल जाने की आशा है । इस प्रतिवेदन के मिल जाने पर यथावश्यक सुधारोपायों पर विचार किया जायेगा । इस समय चालू निर्यात संवर्धन उपायों की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा निर्यात आगे बढ़ाने के लिये सरकार उद्योग तथा व्यापार, जिसमें अमृतसर में कृत्रिम रेशम बुनाई हित शामिल हैं, द्वारा दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखेगी । हाल ही में सरकार ने अफगानिस्तान को रेयन कपड़ा निर्यात करने वाले बुनकरों को रियायती मूल्यों पर विस्कोस फिलामेंट धागा देने का निर्णय किया है ।

भारत का निर्यात तथा आयात व्यापार

*166. **श्री रा० वें० नायक :**
श्री नंजा गौडर :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1968-69 में भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या वर्ष 1968-69 में ऐसा प्रयास किया गया था जिससे भारतीय माल की मांग अन्य मंडियों में बढ़े ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन प्रयत्नों में कुछ सफलता मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किये गये इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार देश के निर्यात-निष्पादन पर निरन्तर ध्यान देती रहती है और नये बाजारों में भारतीय माल भेजने तथा परम्परागत बाजारों में नयी मदों का निर्यात शुरू करने के लिये भारी प्रयत्न करती रहती है। चालू वर्ष में इन प्रयत्नों के लाभप्रद परिणाम निकले हैं। अप्रैल-दिसम्बर 1968 की अवधि में 1,019 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ तथा इतना निर्यात पहले कभी नहीं हुआ था। यह, अप्रैल-दिसम्बर 1967 के निर्यात की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक था तथा अप्रैल-दिसम्बर 1964 में पहुंचे 964.2 करोड़ रुपये (वर्तमान रु० में) के पहले के रिकार्ड से भी 5.7 प्रतिशत अधिक था।

अप्रैल-नवम्बर 1967 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 1968 के निर्यात में (जिसके लिये देशवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध हैं) 112 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। निर्यात में 60 प्रतिशत वृद्धि एशिया तथा समुद्री देशों, जिनमें इकाफे के देश भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में हुई, लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि पूर्वी यूरोप के देशों, 10 प्रतिशत वृद्धि अमरीका और 9 प्रतिशत वृद्धि पश्चिमी यूरोप आदि के सम्बन्ध में हुई।

अप्रैल-दिसम्बर 1968 में भारत का आयात 1376.5 करोड़ रु० का था जो अप्रैल-नवम्बर 1967 से 107.7 करोड़ रु० कम था। भारत का व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर 1967 में 581.8 करोड़ रु० था, जो अप्रैल-दिसम्बर 1968 में 357.5 करोड़ रु० रह गया अर्थात् लगभग 224 करोड़ रु० कम हो गया। व्यापार-अन्तर में उपर्युक्त कमी मुख्यतः अनाज तथा लौह एवं अलौह दोनों प्रकार की धातुओं के आयात में कमी करने से तथा निर्यात में वृद्धि करने से हुई।

व्यापार गृहों की आस्तियां

*167. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने व्यापार गृहों की आस्तियां, उनकी कम्पनियों और उद्योगों तथा उनके द्वारा नियंत्रित अथवा जिन कम्पनियों तथा उद्योगों का उनके द्वारा प्रबंध किया जाता है उन सबकी आस्तियों सहित, 20 करोड़ रुपये से अधिक हैं तथा कितने व्यापार गृहों की आस्तियां 50 करोड़ तथा 100 करोड़ रुपये से अधिक हैं ; और

(ख) कितनी फर्मों अथवा कम्पनियों की आस्तियां, यदि एक कम्पनी एक से अधिक उपक्रम चलाती है तो प्रत्येक उपक्रम की आस्तियों को देखते हुए एक करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपयों तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1964 में, अनेक व्यापार गृहों की कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों की बाबत एकाधिकार जांच आयोग द्वारा संग्रह की गई सूचना के अनुसार, 38 व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियां, 20 करोड़ रुपयों से अधिक थी ; 12 व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियां, 50 करोड़ रुपयों से अधिक तथा 3 व्यापार गृहों की परिसम्पतियां 100 करोड़ रुपयों से अधिक थीं।

(ख) एकाधिकार जांच आयोग द्वारा कम्पनियों (सरकारी, बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियों के अतिरिक्त) की बाबत, संग्रह की गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1964 तक, 838 कम्पनियों की परिसम्पत्तियां, एक करोड़ रुपयों से ऊपर थीं ; 474 कम्पनियों की परिसम्पत्तियां, 2 करोड़ रुपयों से ऊपर तथा 169 कम्पनियों में से प्रत्येक की परिसम्पत्तियां, 5 करोड़ रुपयों से अधिक थीं। फर्मों तथा उपक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मलयेशिया में उद्योग

*168. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को मलयेशिया में संयुक्त उपक्रमों के रूप में उद्योग आरम्भ करने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना करने में काफी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) मलयेशिया के संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के लिए विभिन्न भारतीय पक्षों से प्राप्त अभी तक सात प्रस्तावों का भारत सरकार ने अनुमोदन किया है। उनमें से एक प्रायोजना में उत्पादन जुलाई, 1968 में प्रारंभ हो गया। अन्य छः क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन

*169. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री जनार्दनन :
श्री न० कु० सांघी :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री रा० रा० सिंह देव :
डा० रानेन सेन :
श्री प० मु० सईद :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री देवराव पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दस वर्षों में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये

रेल ने कोई वृहद योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) क्या 1969-70 में योजना के एक भाग को क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो 1969 में किन लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). लगभग 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से करीब 3000 किलोमीटर लम्बी मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए एक संदर्श योजना बनाई गयी है ।

(घ) और (ङ). इनमें से कुछ लाइनों का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने और यातायात सम्बन्धी औचित्य और आर्थिक क्षमता के आधार पर लाइनों के बदलाव की उपयुक्तता सिद्ध होने के बाद ही बदलाव का वास्तविक काम शुरू किया जा सकता है । यह काम धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा ।

मिश्र की रुई का आयात

*170. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1966 में रुपये के अवमूल्यन के बाद मिश्र के रुई निर्यातकर्ता ठेके में इस आशय का विशेष भुगतान खण्ड जोड़ते रहे हैं कि भुगतान रुपये में किया जायेगा और सोने के रूप में भारतीय रुपये के मूल्य में परिवर्तन होने पर ठेके की राशि में तदनुसार फेरबदल किया जाना चाहिये ।

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस खण्ड के जोड़ने से भारतीय आयातकर्ताओं को बड़ी असुविधा हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय आयातकर्ताओं को इस कारण हुई असुविधा से बचाने के लिये सरकार का विचार यह मामला सरकारी स्तर पर उठाने का है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) तथा (घ). 'विशेष भुगतान खण्ड' में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कालीकट में लौह अयस्क के निक्षेप

*171. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों के संबंध में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का छिद्रण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच पड़ताल के क्या परिणाम रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी, नहीं। चेरुप्पा पहाड़ी क्षेत्र में समन्वेषी व्यधन मार्च, 1968 में शुरू हुआ था और दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 6 छिद्रों में 826 मीटरों का व्यधन किया गया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा अब तक किये गये व्यधन कार्य से चेरुप्पा पहाड़ी क्षेत्र में 675 मीटरों की कुल लम्बाई में 25 मीटर से 70 मीटर तक की मोटाई की 30-35 प्रतिशत लोहे वाली मैग्नेटाइट-युक्त लौह-अयस्क काम के होने के संकेत मिले हैं। व्यधन कार्यवाहियां अभी जारी हैं।

कच्चे ऊन की कमी

*172. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे ऊन की कमी के कारण ऊनी उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण ऊन के आयात के लाइसेंस देने में विलम्ब करना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ऊनी उद्योग में ऊनी वर्स्टेड तथा शाडी क्षेत्र शामिल हैं। ऊनी क्षेत्र स्वदेशी कच्ची ऊन का उपयोग करता है और ऐसी ऊन की कोई कमी नहीं है। वर्स्टेड तथा शाडी क्षेत्र प्रधानतः आयातित ऊन पर आश्रित हैं। इन क्षेत्रों की आयातित ऊन की आपूर्ति स्थापित क्षमता से कम है। अतः ये क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) ऊन का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है। पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाने का प्रधान कारण कोई कार्यविधिगत विलम्ब नहीं है अपितु आयातों के परिमाण का अपर्याप्त होना है।

Production in Durgapur Steel Plant

*173. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Durgapur Steel Plant has started production at its rated capacity ;

(b) whether the detailed information regarding the reasons and the persons responsible for the loss suffered by the Steel Plant due to sabotage in the past has since been collected ; and

(c) if so, whether any action has been taken against the guilty persons ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) : (a) Production at the Durgapur Steel Plant is currently at the level of about 1 million tonnes of ingot steel per year.

(b) and (c). Yes, Sir. Disciplinary action is being taken against those involved in the sabotage of the 3rd-4th September, 1968, night.

मोटर गाड़ियों की कीमतों के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

*174. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटरगाड़ियों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). मोटरगाड़ियों के उचित विक्रय मूल्य मिश्रित करने के विषय में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1968) अभी सरकार के विचाराधीन है ।

Late Running of Mail/Express Trains

*175. **Shri Yashpal Singh** :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any enquiry has been made to find out the reasons as to why the passenger, Mail and Express trains do not reach their destinations within the scheduled time, although the time for their arrival from the place of their departure to the place of destinations has been extended considerably during post-independence period ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken to ensure the arrival of trains in scheduled time and to lessen the time for their arrival from the place of departure to the place of destinations ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The running of mail, express and passenger trains is scrutinised daily by each zonal Railway and the reasons for every case of late running are gone into fully. One of the major factors that has militated against a high punctuality performance is anti-social activity such as indiscriminate alarm-chain pulling; theft of tele-communication fittings and public demonstrations.

It is not correct that the running time of trains has been generaly increased. While the numerous developmental works being carried out have necessitated an increased running time in some cases, several trains have been speeded up during the post-independence period.

(c) Corrective measures are taken in respect of all causes of late running within the control of Railways. As far as anti-social activity is concerned, close liaison is maintained with the State Governments at a high level.

The running time of all passenger carrying trains is periodically reviewed and reduced wherever possible. From 1-4-67 to 1-10-68, the running time of 370 trains including 73 mails and expresses has been reduced.

उत्तर बंगाल में चाय उद्योग पर बाढ़ का प्रभाव

*176. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1968 में उत्तर बंगाल में आई बाढ़ का कुप्रभाव उत्तर बंगाल की चाय की बिक्री तथा उसके उत्पादन पर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) उत्तर बंगाल के चाय व्यापार की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ सीमा तक ।

(ग) चाय पुनर्रोपण उपदान योजना में खोये हुये प्रतिस्थापन क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है । प्रभावित जनवर्ग को फैक्टरी भवनों, क्षति ग्रस्त संयंत्र तथा मशीन की मरम्मत/पुनर्निर्माण की लागत के सम्बन्ध में ऋण देना अवेक्षित है । क्षेत्र में श्रम गृहों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण तथा उपदान के रूप में वित्तीय सहायता देना भी विचाराधीन है ।

रूसी ट्रैक्टरों के लिये फालतू पुर्जे

*177. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की 1967-68 में होने वाली सप्लाई अभी तक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) फालतू पुर्जों के सम्भरण में विलम्ब के कारण देश में ट्रैक्टरों के कार्य करने पर कितना प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). मूल्यों पर असहमति के कारण फालतू पुर्जों के आयात का प्रबन्ध करने में विलम्ब हुआ । किन्तु, इससे ट्रैक्टरों के कार्य पर कोई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि किसानों की फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं को विगत में आयातित स्टाक से पूरा किया गया । तब से सोवियत संघ से फालतू पुर्जों का आयात करके स्टाक की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये गये हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

काहिरा में औद्योगिक मेला

*178. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काहिरा में 20 अक्तूबर, 1968 को आरम्भ हुये औद्योगिक मेले में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो मेले में प्रदर्शित हमारे उत्पादों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया रही; और

(ग) मेले में भाग लेने के फलस्वरूप प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर सरकार की भावी नीति का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) भाग लेने से संयुक्त अरब गणराज्य के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा । सरकार को मिली जानकारी के अनुसार जो व्यापार हो चुका है और जिसकी बातचीत चल रही है उसका मूल्य 3.45 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस प्रदर्शनी के परिणामस्वरूप संयुक्त अरब गणराज्य में हमारी अपरम्परागत मदों विशेषतया इंजीनियरी सामान, हल्का तथा भारी, दोनों के प्रदर्शन पर जो सोत्साह प्रतिक्रिया हुई उससे सरकार सन्तुष्ट है तथा वह संयुक्त अरब गणराज्य को भारत से इन मदों के निर्यात का विस्तार सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

औद्योगिक संयंत्रों का निर्यात

*179. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस अन्य देशों को पूरे औद्योगिक संयंत्र निर्यात करने में भारत

की सहायता करने की सम्भावना पर विचार करने के लिये सहमत हो गया है ताकि इस देश में रूसी सहायता के साथ बनी परियोजनाएं, जिनकी क्षमता का पूरा प्रयोग न करने के कारण हानि हो रही है, अधिक लाभप्रद बनाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). करार सिद्धान्तरूप में हाल ही में सम्पन्न हुआ है । किये जाने वाले प्रस्तावित उपाय विचाराधीन हैं ।

Manufacture of Small Car

*180. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of firms and the names of persons from whom applications for the manufacture of small car were received by Government ;

(b) whether these applications have been examined by now ;

(c) if so, the name of the person and the firm whose proposal has since been approved by Government for the implementation of this scheme ;

(d) whether his Ministry has since referred the matter to a sub-Committee for finalisation ; and

(e) the names of the persons under the consideration of the sub-committee ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed). (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-121/69].**

(b) and (c). The proposals have been examined in a broad way but no final decision in the matter has yet been taken.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

पठानकोट स्टेशन पर छोटी लाइन सैक्शन के प्लेटफार्म का विस्तार

960. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट स्टेशन पर छोटी लाइन सेक्शन के प्लेटफार्म के विस्तार के लिए प्राक्कलन तैयार किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के आयव्ययक में इस व्यय को शामिल कर लिया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर नलका

961. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन में लगा हुआ नलका कठिनाई से चलता है और वहां दो अश्वशक्ति वाला बिजली से चलने वाला पम्प लगाने के लिये प्रार्थना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर जो हथ-पम्प लगा है, वह पहिया किस्म का है और इसे चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती । फिर भी, वहां दो अश्व-शक्ति वाला बिजली पम्प लगाने का एक सुझाव मिला था ।

(ख) चूंकि ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर पानी की सामान्य आवश्यकता कम है, इसलिये अभी वहां बिजली पम्प लगाना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क

962. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन में कांगड़ा जिला के सैनिक भारी संख्या में चढ़ते-उतरते हैं और वहां के वर्तमान कर्मचारी इस बढ़े हुये काम को पूरा करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बढ़े हुये काम को पूरा करने के लिये वहां एक बुकिंग क्लर्क नियुक्त करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

ज्वालामुखी रोड और गुलेर स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

963. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में ज्वालामुखी रोड स्टेशन और गुलेर स्टेशन के बीच लेमसु नाम का खनिज नमक का सोता है जहां लोग दवाई के लिये खनिज जल पीने जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोग वहां से रेलगाड़ी में चढ़ने और वहां पर गाड़ी से उतरने के लिये वहां हाल्ट बनाये जाने के लिये अनुरोध कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस स्थान पर हाल्ट स्टेशन बनाने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस प्रस्ताव की अब जांच की जायेगी ।

विमान द्वारा गुजरात का सर्वेक्षण

964. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के खनिज संसाधनों का विमान द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या निकले हैं; और

(ग) अब तक किन-किन खनिजों की खोज की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) गुजरात के खनिज साधनों के हवाई सर्वेक्षण का कार्य अभी हाथ में नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

जापान से व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल

965. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे उन मुख्य उत्पादों के नाम क्या हैं; जिनकी कीमतें जापान के व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल के नेता श्री तकेशी ओ का मुरा ने ऊंची बताई थीं और इसके कारण क्या हैं;

(ख) उस प्रतिनिधि-मण्डल के साथ हुई अन्य बातचीत का ब्योरा क्या है और यदि कोई समझौते हुये हैं तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) जापानी प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा प्रस्तुत सहयोग प्रस्तावों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है और हमारी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिये उनके द्वारा सुझाये गये उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). हाल ही में एक जापानी व्यापार मिशन छर्रों, नमक, पत्ता तम्बाकू, झींगों, भेड़ के सिंग, खली, रत्नों, सब्जियों तथा फलों के भारत से जापान को निर्यात और भी बढ़ाने की सम्भावना का विशेष अध्ययन करने के लिये भारत आया था। किसी करार पर बातचीत अथवा हस्ताक्षर नहीं हुये। मिशन का उद्देश्य केवल तथ्यों का पता लगाना था और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट वह जापान सरकार को देगा। मिशन की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा जांच करने के उपरान्त मिशन के निष्कर्षों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्य होगी।

इस्पात की पटरियों का निर्यात

966. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अफ्रीकी देशों को भिलाई कारखाने में बनी जो इस्पात की पटरियों का निर्यात किया गया था वे उसी जहाज में 'अस्वीकृत' रूप में वापिस लौटा दी गई हैं और यदि हां, तो उनको अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं और वापिस आये माल की मात्रा तथा उसका मूल्य क्या है और इसके जाने-आने पर कितना भाड़ा व्यय हुआ है;

(ख) अफ्रीकियों द्वारा माल को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण बताये गये हैं और त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार इन त्रुटियों के बारे में जांच करवायेगी और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कितनी हानि हुई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

श्रेणी 1 और 2 के रेलवे अधिकारियों को वार्षिक लाभ

967. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 जनवरी, 1969 को उन्होंने 'नए वर्ष का उपहार' के रूप में जिस पर प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिस लाभ की घोषणा की है उनसे श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के कितने अधिकारियों को लाभ पहुंचा है और उनको कितना-कितना अतिरिक्त वार्षिक लाभ हुआ है ;

(ख) उपरोक्त उपहार से श्रेणी 3 के कितने क्लर्कों को अतिरिक्त लाभ पहुंचा है और कितना ;

(ग) क्या निकट भविष्य में श्रेणी 4 के कर्मचारियों को छोटा या बड़ा उपहार देने का सरकार का विचार है जो कि बढ़ते हुए मूल्यों से निरन्तर बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पदों का ग्रेड बढ़ाये जाने के फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के 254 अधिकारियों को लाभ होगा और उन पर 8 करोड़ रुपये नहीं बल्कि प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये खर्च आयेगा :

निर्माण संवर्ग के संकुचित हो जाने के कारण वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से काम करने वाले बहुत से द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और अस्थायी अधिकारियों के परावर्तन की स्थिति पैदा हो गयी थी । यह विनिश्चय किया गया है कि जिन अधिकारियों ने वरिष्ठ वेतन-मान में तीन वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली है; उन्हें परावर्तन से बचाया जाये ।

(ख) से (घ). रनिंग कर्मचारी वर्ग को, जिसमें ड्राइवर, गार्ड, फायरमैन आदि शामिल हैं, 1-12-68 से बढ़ी हुई दरों पर रनिंग भत्ते का लाभ दिया जा चुका है। इस संशोधन से रनिंग कर्मचारियों की, जिनकी संख्या लगभग 93,000 है, परिलब्धियां काफी बढ़ जायेंगी और इस पर प्रति वर्ष लगभग 4.4 करोड़ रुपये खर्च आयेगा । तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ मामले न्यायाधीश एन० एम० मियाभाय के रेल श्रम अधिकरण को सौंपे जा चुके हैं । आशा है कि यह अधिकरण इस महीने के अन्त में अपना काम शुरू कर देगा । इन मामलों के अलावा जो कर्मचारी कुछ समय से अपने ग्रेड के अधिकतम पर पहुंच गये हों, उनके सम्बन्ध में कुछ सुधार करने के उद्देश्य से कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । इस जांच के पूरा होने में कुछ समय लगेगा ।

Industries in Maharashtra

968: **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4871 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether the Fourth Five Year Plan has since been finalised ;

(b) the new industries proposed to be established in Maharashtra ;

(c) whether the working groups appointed for making the comparative study of the regional imbalances have submitted their recommendations ; and

(d) if so, the details of the recommendations and the steps taken by Government to remove the backwardness of the Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Since the Fourth Five Year Plan has not yet been finalised it is not possible at this stage to furnish details of new industries to be set up in Maharashtra during this Plan.

(c) and (d). The recommendations of the two Working Groups on Regional Imbalances have not yet been finalised. The steps that will be taken to remove the deficiencies of industrially backward areas will be decided after the recommendations have been received and examined.

नेपाल के साथ व्यापार समझौता

969. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेपाल के साथ व्यापार के बारे में वर्तमान आलोचना को ध्यान में रखते हुए नेपाल के साथ व्यापार करार पर पुनः विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में एक संसद् सदस्य द्वारा प्रधान मंत्री को तथा उनको दिये गये सुझावों पर भी विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारत-नेपाल व्यापार 1960 की व्यापार तथा पारगमन संधि के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है जो कि 31 अक्तूबर, 1970 तक वैध है। उपर्युक्त संधि के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की समीक्षा दोनों देशों की आवधिक वार्ताओं में की जाती है ।

(ख) तथा (ग). आयातित कच्चे माल पर आधारित कुछ माल, अर्थात् संश्लिष्ट वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात के बर्तनों, का भारत में नेपाल से मुक्त आयात होने से भारत में उसी प्रकार के उत्पादों के निर्माताओं को कुछ कठिनाइयां हो रही थीं । कतिपय संसद् सदस्यों से इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए थे कि अन्य देश से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित माल के नेपाल से आयात पर रोक लगायी जानी चाहिए । नवम्बर, 1968 में काठमांडू में दोनों देशों के प्रतिनिधि के बीच हुई वार्ताओं के दौरान इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार हुआ था । इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप, नेपाल सरकार संश्लिष्ट धागे के वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात उत्पादों के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिए और इन मदों के उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन को भी 1967-68 के ही स्तर पर सीमित करने के लिए सहमत हो गई है । नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए उपायों की कारगरता की अन्तर-सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक में समीक्षा की जायेगी । भारत सरकार इस सम्बन्ध में नेपाल की महामहिम सरकार के साथ पत्र-व्यवहार कर रही है ।

उत्पादक उद्योग का सवक्षण

970. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950-51 से 1967-68 तक की अवधि में वर्ष वार भारत में तथा पश्चिम बंगाल में (उत्पादन उद्योगों की गणना और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार) उत्पादन द्वारा कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) वर्ष 1950-51 से 1967-68 की अवधि में वर्ष-वार उत्पादन द्वारा हुई कुल आय में भारत और पश्चिम बंगाल में (1) श्रमिकों और (2) श्रमिकों से भिन्न-भिन्न अन्य व्यक्तियों का अंशदान क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). 29 उद्योगों के बारे में 1965 तक की आवश्यक जानकारी जो कि कैलेन्डर वर्षों के अनुसार उपलब्ध हैं, के दिखाने वाले विवरण (अनुबन्ध 1 तथा 2 अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 122/69]**

चाय और पटसन का निर्यात

971. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1950-51 से 1968-69 तक वर्षवार चाय और पटसन की बनी वस्तुओं का अलग-अलग कितनी मात्रा में निर्यात हुआ और उसका मूल्य कितना था ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : एक विवरण (अंग्रेजी) में सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 123/69]**

विस्फोटक का निर्माण

972. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विस्फोटक लिमिटेड को सब प्रकार के 400 लाख मीट्रिक टन विस्फोटक प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया जो कि देश के प्रतिवर्ष 2100 लाख मीट्रिक टन की कुल आवश्यकता के गलत अनुमान पर आधारित था ;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि जो 400 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए जो उपकरण आयात किया गया, वह इगलैंड में प्रति पारी 1200 लाख मीट्रिक टन

का उत्पादन करती थी और यह मशीनरी पुरानी है तथा भारत में इसको भेजने से पूर्व इंगलैंड में इसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा था ;

(ग) आयातित मशीनरी की जांच न किए जाने के क्या कारण थे जबकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता स्पष्ट ही लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक है ; और

(घ) सरकार का ऐसे कौन से कदम उठाने का विचार है कि कम्पनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन न करे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

973. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ;

(ख) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के उत्पादन आकड़ों के साथ इसकी क्या तुलना की जा सकती है ;

(ग) देश में उद्योगों विशेषकर टायर उद्योग के लिए प्राकृतिक रबड़ की कितनी आवश्यकता है और इनमें से प्रत्येक वर्ष में प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता और उत्पादन में कितना अन्तर रहा है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह अन्तर कितना हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक वर्षों में कितने प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया और वर्ष 1968-69 और 1969-70 में कितना आयात करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :

	लक्ष्य	अनुमानित उत्पादन
(क)	64,000 मे० टन	69,000 मे० टन

	वर्ष	उत्पादन (मे० टन)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
(ख)	1966-67	(वास्तविक) 54818	8.5 प्र० श०
	1967-68	(वास्तविक) 64468	17.6 प्र० श०
	1968-69	(अनुमानित) 69000	7.0 प्र० श०

(ग)

वर्ष	उत्पादन (मे० टन)	उपभोग	अन्तर (मे० टन)
1966-67	54,818	68,685	13,867
1967-68	64,468	74,518	10,050
1968-69 (अनुमानित)	69,000	88,000	19,000

चौथी योजना के अन्त तक सम्भावित अन्तर 37,000 मे० टन होने का अनुमान है।

कुल रबड़ के लगभग 60 प्रतिशत की खपत टायर उद्योग में होती है।

(घ) 1966-67 तथा 1967-68 में आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

वर्ष	आयातित मात्रा (मे० टन)
1966-67	23,544
1967-68	9,551

1968-69 में 19,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ आयात किये जाने का विचार है। 1969-70 में प्राकृतिक रबड़ के आयात के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

समितियां पंजीयन अधिनियम

974. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समितियां पंजीयन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत अधिकतर समितियां अपना वार्षिक प्रतिवेदन रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम में उपर्युक्त दोषी समितियों के लिए दण्ड का कोई उपबन्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के लिये कार्यवाही की गई है कि उपर्युक्त समितियां अधिनियम के उपबन्ध का पालन करें ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 1860 के अधिनियम में, इसके अन्तर्गत पंजीकृत किसी समिति के लिये, रजिस्ट्रारों को वार्षिक विवरणी, भेजने की अपेक्षा युक्त कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इस विशिष्ट अधिनियम से सम्बंधित, भाग (ख) तथा (ग) के बारे में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पुनः, संविधान की अनुसूची 7, सूची 2, की प्रविष्टि 32 के अनुसार, इस अधिनियम का विषय केवल राज्य सूची के अन्तर्गत आता है।

हरियाना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

975. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरयाना सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र में कुछ और परियोजनाएं स्थापित करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में हरियाणा में उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव हरियाणा सरकार से प्राप्त हुए हैं। यह अभी विचाराधीन हैं और इन पर अन्तिम निर्णय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के विवरण को अन्तिम रूप दिये जाने पर किया जायेगा ।

पंजाब में ट्रैक्टर कारखाना

976. **श्री श्रीचन्द गोयल** :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या इस मांग पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि भारत सरकार द्वारा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किये जाने वाला ट्रैक्टर कारखाना पंजाब में लगाया जाना चाहिये ।

(ख) तथा (ग). अब विचार यह है कि प्रस्तावित परियोजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित एकक एवं खनन तथा सहायक मशीनरी निगम, दुर्गापुर में उपलब्ध फालतू क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिये । राष्ट्रीय औद्योगिक निकास निगम से मामले की जांच करने तथा विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कहा गया है । पंजाब सरकार के अनुरोध पर रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उसकी जांच कर लेने के पश्चात् विचार किया जायगा ।

भारतीय उद्योगपतियों की इथोपिया की यात्रा

977. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री दिनकर देसाई :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968/जनवरी, 1969 के दौरान भारत के कुछ उद्योगपतियों ने इथोपिया की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इथोपिया सरकार से उन्होंने किस प्रकार की बातचीत की;

(ग) वे किन निर्णयों पर पहुंचे; और

(घ) क्या उन्होंने सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सरकार को सूचना मिली है कि भारत के उद्योगों के एक सुविख्यात समूह (ग्रुप) के कुछ उद्योगपतियों ने दिसम्बर, 1968 से जनवरी, 1969 तक की अवधि में इथोपिया की अल्पकालीन यात्रा की । यह ग्रुप पहले ही उस देश में एक संयुक्त औद्योगिक उद्यम चला रहा है । ऐसा ज्ञात हुआ है कि शाही इथोपिया सरकार के साथ इस पार्टी की बातचीत उद्योग खनन, कपास की खेती के क्षेत्रों में और भी सहयोग की सम्भावना के बारे में थी और सहयोग की कुछ सम्भावनाओं का पता लगाया गया ।

(घ) यह यात्रा उन उद्योगपतियों ने शाही इथोपिया सरकार के निमंत्रण पर अपने खर्चे पर की थी । यह ज्ञात हुआ है कि पार्टी के सदस्यों ने व्यवसाय यात्रा के प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी ले ली थी ।

Indo-Russian Agreement

978. **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of agreements between India and Russia concluded so far setting up of industries in the country ;

(b) the names of the industries set up under the said agreements, the dates on which they were set up along with the names of the places where they have been established ; and

(c) the total as well as the industry-wise amount invested in the said industries ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (**Shri F. A. Ahmed**) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

यूगोस्लाविया को भारत का निर्यात

979. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 के आरम्भ से ही यूगोस्लाविया को होने वाला भारत का निर्यात घटता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1963 से यूगोस्लाविया को भारतीय निर्यात की स्थिति निम्नोक्त प्रकार रही है :

	(दस लाख रु० में)
1963-64	146.0
1964-65	181.1
1965-66	178.0
1966-67	189.5
1967-68	116.5
1968-69 (नवम्बर, 1968 तक)	126.4

इससे प्रकट है कि निर्यातों के स्तर में उतार-चढ़ाव आता रहा है। 1967-68 में निर्यात काफी गिर गया था, वह हाल ही में किये गये उपायों से 1968-69 में फिर से बढ़ गया है और नवम्बर, 1968 के अन्त तक ही गत वर्ष के आंकड़ों से बढ़ चुका है।

Thefts of Raw Materials and Finished Goods from Steel Plants

980. **Shri Balraj Madhok** :
Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of raw materials and finished goods is stolen from all the three Steel Plants and the people residing near the plants have full knowledge of these thefts ;

(b) if so, whether Government propose to keep a strict watch on the private ancillary industries set up near these three steel plants as to wherefrom they get raw materials and when the engineers working in the public sector steel plants visit the proprietors of these industries ;

(c) if so, when the said arrangements are proposed to be made ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). It is not a fact that there are large scale thefts in the Steel Plants. Suitable security arrangements exist in these Plants to keep a watch on such activities.

भारती मिल्स, पांडीचेरी

981. **श्री के० रमानी :** **श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री नम्बियार :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री दिनांक 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये भारती मिल्स, पांडिचेरी में अतिरिक्त तकुए और करघे चालू कर दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने तकुए और करघे चालू किए गए हैं; और

(ग) कुल कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक चालू हुए तकुओं तथा करघों की कुल संख्या क्रमश: 16,440 तथा 156 है।

(ग) 951.

सत्यमंगलम् तथा चामराजनगर के मध्य नई रेलवे लाइन (दक्षिण रेलवे)

982. **श्री के० रमानी :** **श्री नम्बियार :**
श्री राममूर्ति : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री दिनांक 17 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने सत्यमंगलम् तथा चामराजनगर के मध्य निर्मित की जाने वाली नई रेलवे लाइन के लिये किये गये सर्वे पर पुन: विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह पुनर्विचार कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). इस प्रायोजना पर पुनर्विचार का काम शुरू किया जायेगा और यथासंभव शीघ्र पूरा किया जायेगा।

भिलाई इस्पात कारखाने को सुव्यवस्थित करना

983. **श्री अदिचन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री जागेश्वर यादव :**
डा० रानेन सेन : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री एम० नारायण रेड्डी **श्री समर गुह :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों के सोवियत मंत्री श्री एस० स्केचकोव के नेतृत्व में, अभी हाल में भारत का दौरा करने वाले एक सोवियत दल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्य को सुव्यवस्थित करने तथा इसकी उत्पादकता और लाभ को बढ़ाने के लिये एक कार्य-योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत दल द्वारा सुझायी गई इस योजना का मुख्य ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में सोवियत दल द्वारा दिये गये सुझावों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उन सुझावों पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (घ). भिलाई इस्पात कारखाने के कार्यकरण का भारत सरकार और श्री स्केचकोव के नेतृत्व में आये सोवियत शिष्ट-मण्डल ने संयुक्तरूप से पुनरीक्षण किया था। इस पुनरीक्षण के दौरान कुछ निर्णय किये गये थे जिन पर दोनों पक्ष सहमत थे। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उन निर्णयों को यथासम्भव क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्न कर रही है।

आन्ध्र प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

984. **श्री अदिचन :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिये उस राज्य में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). जी, हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, बहुत से खनिज निक्षेपों का पता लगाया गया है। इनमें से, अधिक महत्व के

निक्षेप ऐस्बेस्टास, बेराइटस, कोयला, सोना, लोहा-अयस्क, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक, चूना-पत्थर, चीनी-मिट्टी और सीसा तांबा सल्फाईड के हैं । अन्य खनिज निक्षेपों में ऐपेटाइट, हीरे और मोलिब्डिनाइट सम्मिलित हैं ।

मद्रास में सूती कपड़ा मिलें

985. **श्री अदिचन :** **श्री जागेश्वर यादव :**
श्री रामावतार शास्त्री : **डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति द्वारा मद्रास की शेष चार सूती कपड़ा मिलों के मामलों की जांच अब पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने जिन छः मिलों की जांच की उनमें प्रत्येक के बारे में समिति की क्या उपपत्तियां तथा सिफारिशें हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) छः सूती कपड़ा मिलों में से तीन के बारे में जांच समिति ने प्रतिवेदन दे दिये हैं । समिति अब चौथी मिल की जांच में व्यस्त है और इसका प्रतिवेदन शीघ्र ही तैयार हो जायेगा । जांच समिति से शेष मिलों की जांच में शीघ्रता करने के लिये कहा गया है ।

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों वाले ये प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज हैं ।

(ग) समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

औद्योगिक उत्पादन

986. **श्री हिम्मतसिंहका :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : **श्री हेमराज :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के पहले 9 महीनों में और दिसम्बर, 1968 में वर्ष 1967-68 की समकक्ष अवधि की कुल तुलना में प्रत्येक उद्योग में उत्पादन में वस्तुतः कितनी-कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उद्योग में किस दर पर वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) वर्ष 1968-69 में देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर का लक्ष्य क्या है; और

(घ) पिछली उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के लिये औद्योगिक प्रगति की दर कितनी निश्चित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 124/69]**

(ख) वृद्धि की दर बनी रहने की आशा है।

(ग) 5 से 6 प्रतिशत।

(घ) 8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

अर्थ सम्बन्धी मंत्रालयों की समिति

987. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री अदिचन : **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिसम्बर में, वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों के लिये सोवियत मंत्री परिषद् की राज्य साक्ष्य समिति के अध्यक्ष श्री एस० ए० स्केचकोव से हुई बातचीत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी परियोजनाओं को क्रयादेशों से भरपूर करने तथा उन्हें पूरी क्षमता से चलाने के लिये विशिष्ट उद्देश्य के लिये आर्थिक मंत्रालयों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का वास्तविक गठन और काम क्या होगा; और

(ग) उपरोक्त बातचीत के सन्दर्भ में, विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने हेतु कौन से अन्य उपाय किये गये अथवा किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की मूल-भूत समस्याओं और उनसे संबंधित मामलों के समन्वय के लिये एक समिति स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा कुछ समय से अलग से विचार किया जा रहा है। इसमें से कुछ समस्याओं पर श्री स्काचोव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधि-मंडल के साथ बात-चीत की गई थी। इस समिति के गठन तथा उसकी रचना और कार्यों के ब्योरे आदि के बारे में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

अमृतसर में कृत्रिम रेशम उद्योग

988. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री गु० सि० ढिल्लों :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह अभी हाल में कृत्रिम रेशम के धागे के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कृत्रिम बुनाई उद्योग में पैदा हुई समस्याओं का अध्ययन करने के लिये अमृतसर गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं और उनकी अमृतसर यात्रा के दौरान इस उद्योग ने उनके समक्ष क्या मांगें रखीं; और

(ग) इन मांगों तथा समस्या का व्यक्तिगत रूप से किए गए अध्ययन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां । मुझसे पूर्व के मंत्री महोदय गत मास अमृतसर गये थे और उन्होंने कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था । यह मांग की गई कि विस्कोस रेयन धागे की समुचित मूल्यों पर आपूर्ति की जाये तथा निर्यात में परिवर्तन किया जाये ।

(ग) टैरिफ आयोग से विस्कोस रेयन धागे के मूल्यों के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और इस प्रतिवेदन के मार्च, 1969 के मध्य तक प्राप्त होने की सम्भावना है । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यदि आवश्यकता हुई तो, उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जायेगा । इस समय लागू निर्यात संवर्धन उपायों की सतत समीक्षा की जाती है और निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार उद्योग तथा व्यापार, जिसमें अमृतसर स्थित कृत्रिम रेशम बुनाई हित भी शामिल है, से प्राप्त सुझावों पर ध्यान देगी ।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के मामलों की जांच

989. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री दिनांक 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन के मामलों की जांच करने हेतु कोई नया अधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा उस व्यक्ति का नाम क्या है; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) पटना उच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश श्री सरजू प्रसाद सिंह को ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है । जांच प्रगति पर है ।

(ग) जी, प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से कोयले की खरीद

990. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बिहार बिजली बोर्ड से, उससे एकाधिकारिता के आधार पर कोयले की खरीद आरम्भ करने का अनुरोध नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बिहार राज्य विद्युत मंडल को पतरातु तापीय बिजली घर के लिये 1969-70 वर्षों में आवश्यक सारा कोयला उन (निगम) से ही प्राप्त करने की प्रार्थना की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

संकट ग्रस्त कपड़ा मिलें

991. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के विलय की अनुमति देने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का सर्वेक्षण किया है जिनके बन्द होने का खतरा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मिलों की संख्या क्या है; और

(ङ) उन्हें पुनर्जीवित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). सम्भवतः 'संकटग्रस्त कपड़ा मिलों' से माननीय सदस्यों का अभिप्राय उन सूती कपड़ा मिलों से है जो वित्तीय तंगी अथवा अदक्ष प्रबन्ध के कारण कठिनाई में हैं। ऐसी मिलों की सहायता करने के विचार से 'संकटग्रस्त मिलों' का उन्नत/लाभप्रद मिलों में विलय करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ). ऐसी मिलों का कोई व्यापार सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु उपलब्ध जानकारी से मालूम होगा कि ऐसे मिलों की संख्या 100 से अधिक है, जिनको संकटग्रस्त कहा जा सकता है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूती मिलों को सहायता देने के लिये पहले ही किये जा चुके उपायों का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

(1) राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जिसने कार्य प्रारंभ कर दिया है, उन मिलों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्यक्रम शुरू करेगा जिन्हें उसने अपने हाथ में लिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त कार्यकारी दल के अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को हिदायत दी है कि ऐसी वस्त्र मिलों को जो इस प्रकार की सहायता की पात्र हैं, अतिरिक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गिरवी तथा बंधकीकरण पर दिये गये अग्रिम धन और सावधिक ऋण पर मार्जिन कम किया जाय।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी ऋण देने की नीति को उदार बना दिया है और वह उपयुक्त मामलों में स्वदेशी वस्त्र मशीनों पर सात वर्ष तक आस्थगित भुगतान की सुविधा दे रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पुनः पूर्वप्रापण सुविधा में भी छूट दे दी है।

(4) कपड़े की उच्च-मध्यम, बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्मों की कतिपय मदों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है, नियंत्रित कपड़ा तैयार करने की अनिवार्यता को उत्पादन के 40% से कम करके 25 कर दिया गया है, कोरी धोतियों तथा साड़ियों को छोड़कर नियंत्रित कपड़े के मूल्य में 2% की वृद्धि करने की अनुमति दी गई

है जिसे उत्पादन शुल्क में कमी करके प्रति संतुलित किया गया है। मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का अपनी अनिवार्यता से अधिक उत्पादन करने लिये उन्हें प्रोत्साहन देने और मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की उनकी अनिवार्यता के स्थान पर मुआवजा देने की एक योजना लागू की गई है।

(5) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर तीन माह की अवधि के लिये एक विशेष अतिरिक्त छूट दी गई है।

(6) तामिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारों को क्रमशः 50 लाख रुपये और 15 लाख रुपये के ऋण शीर्ष सहकारी समितियों को पुनः ऋण के रूप में देने के लिये मंजूर किये गये हैं ताकि ये समितियां मिलों को उनके धागे के अतिरिक्त स्टाक से राहत दिलाने के उद्देश्य से धागे (और तामिलनाडु के संबंध में कपड़े) का स्टाक कर सके।

(7) इसके अतिरिक्त इस समय वस्त्र उद्योग का विस्तार रोक दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंस

993. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 5 जनवरी, 1969 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित उस प्रेस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि योजना के पिछले 17 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में 125 करोड़ रुपये की पूंजी लागत वाले 215 औद्योगिक लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रकार औद्योगिक लाइसेंसों को रद्द करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस रद्द करने के संबंध में 5 जनवरी, 1969 के संडे स्टेट्समैन में प्रकाशित कोई भी समाचार नहीं देखा है। फिर भी, इस विषय में उसी तारीख के संडे स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक समाचार सरकार की जानकारी में आया है।

(ख) लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस में उल्लिखित समय के अन्दर अथवा किन्हीं विशिष्ट मामलों में सरकार द्वारा मंजूर किये गये बढ़ाये हुए समय के अन्दर उसकी स्थापना करने के लिए कारगर कदम न उठा सकने के कारण रद्द कर दिये जाते हैं।

कुछ मामलों में लाइसेंस की मान्यता की अवधि बढ़ा देने के लिए मंजूरी दे देने पर भी काफी समय तक लाइसेंस कार्यान्वित न हो सकने पर सरकार की नीति के अनुसार सामान्य रूप में ये लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार लाइसेंस रद्द किये जा चुके हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलान धागे का आयात

994. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल कितनी मात्रा में नायलान धागे का आयात किया गया;

(ख) निगम द्वारा आयात किये गये प्रत्येक प्रकार के नायलान धागे का मूल्य क्या है;

(ग) उक्त किस्म के नायलान धागों का विक्रय मूल्य क्या था; और

(घ) नायलान धागे के व्यापार से चालू वित्तीय वर्ष में निगम को कुल कितना लाभ हुआ ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अप्रैल '68-जनवरी' 69 की अवधि में 951 मी० टन।

(ख) नायलोन धागे के मूल्य विभिन्न देशों में अलग-अलग हैं और विभिन्न डेनियर तथा किस्मों के लिए भिन्न-भिन्न हैं। क्रय मूल्य भी किस्म, गुण तथा बारीकी के अनुसार और जिस देश से नायलोन धागे का आयात किया गया है, उसके अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ग) सितम्बर, 1968 तक राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलोन धागे के विक्रय मूल्य स्वदेशी नायलोन की वैसी ही किस्मों के भावों से कुछ कम थे। परन्तु पता लगा है कि अब सितम्बर, 1968 से स्वदेशी धागे के मूल्य कुछ कम हैं।

(घ) सीमा शुल्क, प्रतिशुल्क, भाड़ा, बीमा और उनके चढ़ाने-उतारने तथा वितरण का खर्च देने के उपरान्त राज्य व्यापार निगम को उसके द्वारा तीन बार घोषित मूल्य कटौतियों के पश्चात, लाभ अधिक नहीं हुआ है। इस लाभ को भी कृत्रिम रेशम के वस्त्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

मरियानी में रेलवे यातायात अधिकारियों की गिरफ्तारी

995. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 में माल की चोरी करने के आरोप में रेलवे यातायात विभाग के कुछ अधिकारी मरियानी में गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

राज्यों में लघु उद्योगों के लिये नये लाइसेंस

996. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में, वर्ष-वार लघु उद्योग स्थापित किये जाने के लिये राज्य-वार कितने नये लाइसेंस दिये गये;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक वर्ष में लघु उद्योगों के यदि कोई लाइसेंस रद्द किये गये थे तो राज्य वार कितने लाइसेंस रद्द किये गये और उसके क्या कारण थे; और

(ग) वर्ष 1968 के अन्त में नये लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

संयुक्त अरब गणराज्य लघु उद्योग दल का दौरा

998. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास का अध्ययन करने के लिये संयुक्त अरब गणराज्य से एक लघु उद्योग दल हाल में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो वह दल कहां-कहां गया था ; और

(ग) क्या संयुक्त अरब गणराज्य को लघु उद्योग स्थापित करने में भारत द्वारा मदद देने के कोई प्रस्ताव हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, लुधियाना, चण्डीगढ़ और आगरा।

(ग) लघु उद्योगों की स्थापना हेतु संयुक्त अरब गणराज्य सरकार से विशिष्ट सहायता प्राप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव या आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

Broad-Gauge Line from Shahdara to Saharanpur

999. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri P. C. Adichan :
Shri Himatsingka :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Balraj Madhok :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Kumari Kamla Kumari :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Ranjit Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether survey for laying broad-gauge railway line between Shahdara and Saharanpur has been completed ;

(b) if so, the amount of expenditure to be incurred by Government on this work ; and

(c) the time by which Government would undertake this scheme ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Not yet.

(b) Does not arise. The estimated cost of the work will be known only after the survey is completed.

(c) A decision regarding construction of this B. G. line will be taken after the surveys are completed and the survey reports are examined by the Railway Board.

Improvement in the Working of Hindustan Steel Limited

1000. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether there is some improvement now in the working of the Hindustan Steel Ltd. ;

(b) whether the losses being suffered by the said organisation have been reduced as a result thereof ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Although considerable improvement is anticipated in terms of production, despatches and sales realisations during the year 1968-69 as compared to the preceding year, according to the present indications, Hindustan Steel Limited is likely to sustain a loss during this year. The various remedial measures taken to improve the working of the Company (as outlined in the Pamphlet entitled "Performance of Hindustan Steel Limited" placed on the Table of the House on the 5th April, 1968), will take time in yielding tangible results.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

1001. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण का उसकी स्थापना के पश्चात कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितताएं पायी गईं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का कार्यकरण

1002. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में सरकार ने निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है ;

(ख) अनियमितताओं, चोरियों, स्टाक में कमी तथा आग की घटनाओं के कारण इस कारपोरेशन को उसकी स्थापना से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) अनियमितताओं के कारण से कोई हानि नहीं हुई है और न कोई बड़ी चोरी का मामला हुआ था। किताबों में स्टाकों के गलत लिखे जाने के कारण धुली हुई मिट्टी के कम हो जाने से 1964-65 और 1965-66 वर्षों में बट्टे खाते डाली गई रकम 3,23,968 रुपये थी। बिजली गिरने से लगने वाली आग से उपकरणों को नुकसान पहुंचने से होने वाली हानि, जो 1965-66 के लेखों में बट्टे खाते डाली गई, 81,783 रुपये थी।

(ग) खातों में धुली मिट्टी के गलत स्टाक लिखने के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और भविष्य में इस प्रकार की गल्तियों में पुनरावृत्ति को रोकने के लिये पर्याप्त नियन्त्रक उपाय लागू किये गये हैं।

उत्तर रेलवे (दिल्ली डिवीजन) टेलीफोन आपरेटर

1003. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे (दिल्ली डिवीजन) के बाकी उन सब टेलीफोन आपरेटरों को अपनी पूल क्लैरिकल ब्रांचों में शामिल होने के लिये नौकरी से छुट्टी मिल गई है जिनके लिए आदेश जारी हो गये थे तथा जिनके लिए रेलवे बोर्ड ने 1965 में आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो आदेशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). स्पष्टतः आशय रेलवे बोर्ड के 2-11-1964 के पत्र सं० ई (एन जी) 64 एस आर/6/18 से है जिसमें यह कहा गया था कि "17 टेलीफोन आपरेटरों में से केवल 5 को लिपिकीय पदों में समाहित करना बाकी है और उत्तर रेल प्रशासन उनका स्थानान्तरण करने के लिए भी यथासम्भव शीघ्र कार्रवाई कर रहा है।" वर्तमान स्थिति यह है कि एक को छोड़कर बाकी सबको भार-मुक्त कर दिया गया है। 1965 में इस आशय के सामान्य आदेश जारी किए गए थे कि टेलीफोन आपरेटर वर्ग के वर्तमान कर्मचारियों को लिपिकीय वर्ग अथवा टेलीफोन आपरेटर वर्ग वरण करने का विकल्प दिया जाये। इस कर्मचारी ने टेलीफोन आपरेटर वर्ग के लिए विकल्प दिया था और उसमें काम कर रहा है। इस तरह इस मामले में सम्बन्धित आदेशों से भिन्न कार्रवाई नहीं हुई है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स परियोजना पिंजौर

1004. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिंजौर की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स परियोजना की लगभग 60 प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए इस बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित एकक की इस समय लगभग 50 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग). पंजाब सरकार ने सुझाव दिया है कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जीटर 2011 ट्रैक्टरों के निर्माण की प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना का कार्यान्वयन पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंपा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने यह भी कहा है

कि वह पिंजौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक की अप्रयुक्त क्षमता का यथासम्भव प्रयोग ट्रैक्टरों के अधिक से अधिक पुर्जे बनाने में करेंगे। इस सुझाव के उत्तर में राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि भारत सरकार स्वयं भी विद्यमान सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित कारखाने और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर की फालतू क्षमता के प्रयोग में रुचि रखती है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० तथा माइनिंग एण्ड एलाइट मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दोनों ही एक संयुक्त प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें अपनी फालतू क्षमता का प्रयोग करने हेतु चेकोस्लोवाकिया के जीटर 2011 ट्रैक्टरों का या माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा विकसित ट्रैक्टर को केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण करना प्रारम्भ करना चाहिए। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से इन दो नमूनों के तुलनात्मक सम्भाव्यता अध्ययन सहित एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर लेने के पश्चात ही भारत सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने की स्थिति में हो सकेगी कि क्या वह जीटर 2011 ट्रैक्टरों की निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाये या उनका निर्माण कार्य किसी संगठन/प्राधिकार को सौंपा जाये।

आयात सम्बन्धी नीति

1005. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में उपमंत्री ने निर्माता द्वारा यह दावा करने के बावजूद कि वह अपेक्षित मात्रा का उत्पादन कर सकता है, आयातों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की नीति के सम्बन्ध में हाल में अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी ;

(ख) ऐसा वक्तव्य देते समय क्या मंत्री महोदय ने इस मामले में सरकार के विचार का संकेत दिया था और क्या आयात के सम्बन्ध में ऐसी कोई ढील देने का विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन आधारों पर जितना उपमंत्री ने संकेत दिया है, किन-किन वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). उपमंत्री ने किसी उत्पादक के इस कथन पर कि वह आवश्यक मात्रा में किसी वस्तु के उत्पादन में सक्षम है किन्तु वह उसे वास्तविक रूप से उत्पादित नहीं कर रहा है या उसने अभी उत्पादन प्रारम्भ ही नहीं किया है, इसे आधार मानकर किसी वस्तु के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की नीति पर व्यक्तिगत असंतोष व्यक्त किया है। अतः ऐसी कुछ वस्तुओं

जैसे पेन्सिल, स्लैट्स, एक्रिलिक शीट्स तथा चश्मों के अपरिष्कृत शीशों इत्यादि के आयात में ढील दी गई है ।

बड़ौदा डिवीजन में झंडी स्टेशन

1006. **श्री रा० को० अमीन :**
श्री द० रा० परमार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने बड़ौदा डिवीजन में अनेक छोटे स्टेशनों को झंडी स्टेशनों में बदलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम रेलवे के बड़ौदा डिवीजन के विभिन्न खण्डों पर, अभी तक, निम्नलिखित 13 ब्लाक स्टेशनों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है :

पावागढ़, सानधीया, भटपुर, नरेश्वर रोड, वागरा, वैलाछा, अजवा, वासनपुरा, मेवली, बेजपुर, तीन तलाव, वैजलपोर और कोरा ।

कपड़ा उद्योग

1007. **श्री रा० को० अमीन** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए किये गये विभिन्न उपायों के प्रभाव का पुनरीक्षण करने का सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई पुनरीक्षण करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए पहिले ही किये गये उपायों से उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में नई रेलवे लाइन

1008. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री प० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 में नई रेलवे लाइनें बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार केरल में फेरोक मेलाटूर रेलवे लाइन बनाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो यह कब शुरू हो जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जिन लाइनों पर काम हो रहा है, उनके अलावा निम्नलिखित नयी लाइनों को 1969-70 के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है :

(i) थुरभिटा-भपतियाही लाइन को फिर से बिछाना ।

(ii) फरक्का बांध और चामग्राम के बीच बड़ी लाइन सम्पर्क ।

(ख) से (घ). चौथी योजना में नयी लाइनों के लिए उपलब्ध होने वाली सम्भावित सीमित राशि के कारण उसमें विचारार्थ फेरोक-मेलातुर लाइन को समुचित अग्रता मिलने की सम्भावना नहीं है ।

स्टैण्डर्ड ड्रम कम्पनी

1009. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह पत्र जो एक संसद सदस्य ने मंत्री महोदय को कपाडिया परिवार द्वारा किलिक्क सार्थ समूह को अपने हाथ में लेने के बारे में लिखा था, मंत्री महोदय की फाइल से गायब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके इस प्रकार रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बारे में जांच का आदेश दिया गया था ;

(ग) उसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) क्या इस बीच एक और प्रति प्राप्त कर ली गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(च) इस बीच की गयी जांच का क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मंत्री के व्यक्तिगत अनुभाग में सम्बन्धित सदस्य के मूल-पत्र की प्राप्ति का अभिलेख नहीं है एवं समवेक्षी अन्वेषण के पश्चात भी, इसका पता न लग सका ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) सदस्य से अनुस्मारक प्राप्त होने के पश्चात, मंत्री के व्यक्तिगत अनुभाग के एक सदस्य द्वारा, सम्बन्धित सदस्य से अनुस्मारक में निदेशित पत्र की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली गई थी।

(ङ) तथा (च) कथित पत्र में अनेक विषयों का निर्देश है, और यह अभी तक परीक्षान्तर्गत है।

Political Interference in the Affairs of Steel Plants

1010. **Shri Ram Charan:**
Shri Molahu Prasad:
Shri Raghuvir Singh Shastri:

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the politicians interfere in the affairs of all the three steel plants and that the appointments to higher posts are made under political pressure; and

(b) if not, the names of those Administrative Officers, General Managers and Engineers of the three plants who are related to the present and former Central Ministers and Officers of the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) No, Sir.

(b) This information is not available.

तिरुनेलवेलि और कन्याकुमारी के बीच रेलवे लाइन

1011. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को तिरुनेलवेली तथा कन्याकुमारी के बीच और नगर कोईल तथा त्रिवेन्द्रम के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इन निर्माण कार्यों पर कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). नागरकोयल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम तक एक नयी लाइन तथा केप कमोरिन तक एक शाखा लाइन के लिये इंजीनियरिंग और यातायात सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये गये थे जिसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को 1966 में मिल गयी थी। उस रिपोर्ट से यह पता चला कि यह प्रायोजना आर्थिक दृष्टि से क्षम

नहीं थी विशेषकर इस कारण कि उस क्षेत्र में सड़क परिवहन की अच्छी व्यवस्था है। फिर भी, इस लाइन की वर्तमान लागत और यातायात तथा वित्तीय सम्भावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से, साथ ही इस क्षेत्र में और भी कोई विकास कार्य हुआ हो तो उसे भी ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि पिछले सर्वेक्षण रिपोर्ट का पुनर्मूल्यांकन किया जाये। इस निर्माण-कार्य को 1969-70 के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय तभी किया जायेगा जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा इसकी संशोधित रिपोर्ट का संकलन तथा जांच कर ली जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों का निर्माण

1012. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई रूपरेखा तैयार की गई है ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों क्षेत्र का निर्माण करने के लिये लाइसेंस हेतु कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है;

(ग) क्या देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन को वरीयता देने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) सरकार ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए किस सरकारी क्षेत्र में एक कारखाने की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, अंतिम निर्णय अभी किया जाना है।

(ख) ट्रैक्टर उद्योग से लाइसेंस हटा दिये जाने के बाद से विदेशी सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए नये उपक्रमों की स्थापना हेतु 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इनमें से एक प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप में सहमति दे दी गई है। सम्बन्धित फर्म ने हाल ही में अंतिम विदेशी सहयोग करार पुनरीक्षित अवस्थावद्ध निर्माण कार्यक्रम तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये आवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं जिनकी जांच की जा रही है। दो अन्य फर्मों से जिनमें एक मुश्त या प्रस्तावित विदेशी सहयोगियों को दी जाने वाली आवर्ती रायल्टी का प्रश्न

अन्तर्निहित नहीं है, पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा पुनरीक्षित अवस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम के बारे में अपने आवेदन सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये प्रस्तुत करने को कहा गया है। इनमें से एक फर्म ने हाल ही में सहयोग करार का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। उनसे पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये अपना आवेदन तथा पुनरीक्षित अवस्थावद्ध निर्माण कार्यक्रम शीघ्र ही प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। एक अन्य फर्म द्वारा सूचना प्रस्तुत न कर सकने के कारण उसका प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है।

एक अन्य आवेदक से यह कहा गया है कि वह प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय किये जाने से पूर्व निर्माण के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर की ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र, बुदनी में अपने ट्रैक्टर का परीक्षण करवा लें। दो अन्य आवेदकों को विस्तृत योजना प्रस्तुत करने एवम् अपने सहयोगियों का वह पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है जिसमें उनके द्वारा सहयोग करने की सहमति प्रकट की गई है। इन आवेदनों पर उपरोक्त ब्योरा प्राप्त हो जाने के बाद ही विचार किया जायगा। दो योजनाएं अधूरी होने के कारण पार्टियों से यह कहा गया है कि वे ब्योरा प्रस्तुत करें। शेष दो योजनाओं की जांच की जा रही है।

(ग) कृषि ट्रैक्टर उद्योग प्रमुख उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और इस उद्योग को पूंजीगत वस्तुओं एवं पुर्जों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित करने के मामले में पहले से ही प्राथमिकता दी जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bharat Heavy Electricals Ltd.

1014. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bharat Heavy Electricals Ltd., would face shortage of work after 1970-71 and 50 per cent of its installed capacity will remain idle; and

(b) whether the less use of heavy electrical machinery in the generation of electricity during the Fourth Plan is mainly responsible for the idle capacity in the aforesaid Company?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): The manufacturing load on Bharat Heavy Electricals Ltd., together with Heavy Electricals (I) Ltd., Bhopal during the next few years would naturally be dependent on the final programme for power development during the Fourth Plan Period, as these undertakings are primarily designed for the manufacture of Heavy Electrical Equipment for power generation. To the extent that the power development programme falls short of the manufacturing capacity in these plants during this period, there is likely to be surplus manufacturing capacity. The final picture in this regard would only emerge after the Fourth Plan for power development is finalised. Efforts are being made to diversify production in these undertakings to the extent possible so that the manufacturing capacity in the heavy electrical plants are utilised to the maximum extent.

Central Mechanical Engineering Research Institute

1015. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the tractor manufactured and tested by the Central Mechanical Engineering Research Institute had been found useful for agricultural purposes ;

(b) if so, the main features of the scheme prepared for their manufacture ; and

(c) the details of the scheme prepared for the manufacture of insecticide spraying machines invented by the said Institute ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) According to the report sent by Central Mechanical Engineering Research Institute, they have developed a 20 HP agricultural tractor. Ten prototypes are now in an advanced stage of manufacture. Arrangements for the trial of these prototypes have been made by them at the Tractor Training and Testing Station, Budni; U. P. Agricultural University, Pant Nagar; Punjab Agricultural University, Ludhiana; Indian Institute of Technology, Kharagpur; and with selected farmers. The usefulness of this tractor under Indian conditions will be known after the results of these tests become available.

(b) The Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur have proposed the manufacture of this tractor. They have, jointly with the Hindustan Machine Tools Ltd., commissioned the National Industrial Development Corporation to prepare a detailed project report and to recommend whether the CMERI-designed tractor or the Zetor—2011 tractor in collaboration with Czechoslovakia should be taken up for manufacture. The report of N.I.D.C. is expected by the end of April, 1969.

(c) According to the CMERI, the first insecticide sprayer developed by them has been on extensive tests since early 1967. No proposals for its manufacture have so far been finalised.

Diesel and Electric Engines

1016. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time by which India will become completely self-sufficient in the manufacture of diesel and electric engines ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : The manufacture of Diesel and Electric Locomotives in the country is expected to gradually attain an indigenous content of about 80-90 per cent during the course of the next four years. This extent of indigenisation is dependent on the supply of matching sets of electrical equipment by the Heavy Electricals Ltd., Bhopal, and the development of certain items by other ancillary industries in India.

It is not possible at this stage to give any firm indication in regard to further indigenisation. The import of a few items of a proprietary and of a very specialised nature including certain raw materials will continue to be necessary.

Foreign Exchange Earned by Railways

1017. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of foreign exchange likely to be spent and earned by the Railways during the current financial year ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): The estimated foreign exchange expenditure of Indian Railways during the financial year 1968-69 (including foreign exchange expenditure on production of rolling stock) is Rs. 26.6 crores and the estimated foreign exchange earnings are Rs. 98 lakhs on inspection fees and export of scrap steel and loco boilers.

Provision of more Berths in First Class Compartments

1018. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the obstacles in the way of designing more berths in the same space in Ist Class Railway Compartments; and

(b) whether it is a fact that the Railway Officers are against it and that is the reason why more berths are not being provided in First Class Compartments?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The amenity standards laid down for the comfort of passengers do not permit provision of more berths in the same space in Ist Class Railway Compartments.

(b) No.

इनटिगरल कोच फैक्टरी, मद्रास में तीसरी पारी

1019. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक कोचों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनटिगरल कोच फैक्टरी में तीसरी शिफ्ट कब शुरू की जायेगी ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के कोच बनाने वाले वर्तमान एकक के काम को इनटिगरल कोच फैक्टरी, दक्षिण रेलवे को सौंपने की कोई विशिष्ट योजना है ; और

(ग) इसकी नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सवारी डिब्बा कारखाना, पैरम्बूर में काम की तीसरी पारी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Central Projects in Uttar Pradesh

1020. **Kumari Kamala Kumari:** **Shri Narain Swarup Sharma:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi: **Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have not so far set up any special project in Uttar Pradesh, the biggest State in India ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to set up an Atomic Power House there keeping in view the population and the declining per capita income of that State, so that cottage industries could be encouraged there?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). Four large central industrial projects have been set up in Uttar Pradesh so far. They are: Diesel Loco Factory, Varanasi; Gorakhpur Fertilizers, Gorakhpur; Heavy Electrical Equipment Factory, Hardwar; and Antibiotics Plant at Rishikesh. In addition, a Heavy Structural Project is under implementation at Naini.

(c) A view regarding setting up of new Atomic Power Stations or extension of existing stations is proposed to be taken when the stations under construction go into operation and their economics and other relevant factors have been studied.

Demonstration by Workers of Heavy Engineering Corporation

1021. **Kumari Kamla Kumari: Shri Narain Swarup Sharma: Shri Ram Swarup Vidyarthi: Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Industriai Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thousands of workers of the Heavy Engineering Corporation staged demonstrations against the communal policy of the management and of its Chairman regarding the settlement of Hindu and Muslim workers in separate colonies; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): On the 25th, 27th and 29th November, 1968 about 300—400 workers demonstrated against the decision of the management of the Heavy Engineering Corporation to rehabilitate the Muslim employees of the Corporation, staying in the Artisan Hostels, in specified sectors of the Corporation township.

(b) A statement made by the Minister for Industrial Development and Company Affairs in the Rajya Sabha in this connection on the 2nd December, 1968 is attached.

Statement

Following the incidents of August, 1967, the Muslim employees of the Heavy Engineering Corporation, were moved into a building called "Artisan Hostel". They have continued to live in this building where the living space is limited and the conditions of living are unhealthy. A large number of them are huddled up in single rooms. Most of these employees have sent their families back to their homes. This concentration had created undesirable conditions for these industrial workers who were living in isolation. The Chairman, HEC, held a series of consultations with the Muslim workers with a view to persuading them to go back to their quarters. The Muslim employees represented that they were not feeling secure enough to return to their quarters where they would have to leave their wives and children while working in the plants. In view of the limitation of space, it was not possible for the Muslim employees and their families to accommodate themselves in the Artisan Hostel.

2. Prior to communal riots, a large number of Muslim employees lived at a place

known as Site V of Sector II. It was suggested by the Management of the HEC to move about 100 Muslim employees to this site as there were about 40 houses in this sector which were vacated by Muslims last year. If 50 to 60 more houses could be made available by the Hindu residents of this locality, the Management would arrange for the shifting of a group of Muslim employees to this locality. Accordingly, a general appeal was issued by the Management to all the residents of this locality suggesting, if they could vacate some houses purely on a voluntary basis, those who so offered would be given alternate accommodation. Whosoever liked to shift was requested to formally inform the Town Administration authorities, who would make all arrangements in this regard.

3. It is not correct to say that any intimation or compulsion was thought of or practiced. Yet some politically motivated groups of people, entered the HEC campus, held daily meetings and spread distorted news that Hindus of Site V of Sector II were being forced to make room for Muslims. Obviously this was done to arouse communal feelings. The advantage of selecting this site was that 3 dozen houses occupied by Muslims are already vacant and if another 60 houses could be available, the problem would have been solved to a great extent. This scheme of dispersal was discussed and generally agreed to by the representatives of all trade unions including the Shramik Sangh.

4. While all this was going on peacefully, expectations were that some houses could be voluntarily vacated to accommodate Muslim co-workers and while more than three dozen persons had already volunteered in writing to vacate their houses in favour of Muslims in Site V, suddenly some politically motivated people inspired a movement of pressurisation and intimidation in Site V Camp in which some political parties and workers from the town came to hold meetings in order to prevent willing workers from moving from there, although Section 144 was promulgated. Acts of indiscipline by about 80 workers were also noticed that they absented themselves from the workshop without leave. When disciplinary action was indicated, many of them joined in this campaign of pressurisation. If the workers belonging to a particular party had not come from outside to interfere in the legitimate and peaceful movement of our willing workers within the campus, the seheme would have been successful. People from outside continue to visit HEC's colony, thereby creating an atmosphere of defiance of Section 144 and they also tried to prevent an official of the Corporation, from explaining the situation to those concerned.

5. While under the scheme of the management, the effort was to break up Muslim concentration and help them to properly intergrate with the rest of the community, the politically motivated persons spread the rumour that the entire Sector 2 was being forcibly vacated by the authorities and new construction added in order to resettle Muslim employees at one place and also provide them with facilities to contact Muslims of the larger Ranchi town. All that HEC Management desire is to house the Muslim employees in a number of areas in the township to facilitate integration on the one hand and a sense of security on the other.

6. Recently, the Corporation Management has also decided to undertake additional construction of residential accommodation in different sectors of the HEC township for rehousing the employees. A sum of about Rs. 20 lakhs is proposed to be spent in the current year on this account.

7. The impression sought to be created that the Management was pressuring Hindu employees living in various residential areas to vacate their present accommodation in order to allot such vacated premises to the Muslim employees is baseless. The management have made a public statement to this effect. The effort being made is actually in the direction of breaking up the present Muslim concentration at one place in the Artisan Hostel and distributing their accommodation in a number of locations in the Township so as to avoid any concentration on the one hand and give them a sufficient sense of security on the other. Only persuation has been employed in these efforts and all this has been on the basis of an appeal to move on a purely voluntary basis.

Indian Iron and Steel Co. Ltd.

1022. **Kumari Kamala Kumari : Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Chengalaraya Naidu :
Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the shareholders of the Indian Iron and Steel Company Ltd., have complained to Government against misappropriation by the Management to the tune of crores of rupees ;

(b) whether it is also a fact that the shareholders are going to file a law suit against the company in view of Government's indifference to their complaint ;

(c) if so, whether any step has been taken to look into the affairs of this company ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Some complaints against the management of the company have been received.

(b) Government have no information.

(c) and (d). The matter is under examination.

Exports to Africa and South America

1023. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the items of goods exported by India during the year 1968 to the under-developed countries of Africa and South America and the amount of foreign exchange earned therefrom ;

(b) the concrete steps taken by Government to increase Indian exports to these countries ; and

(c) the targets fixed for exports to these countries for the year 1969 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) A statement is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-125/69.]**

(b) The following steps are taken to increase the exports:

(1) Negotiation of trade arrangements;
(2) Participation in Trade Fairs and Exhibitions;
(3) Deputation of Study and Sales Teams;
(4) Conducting of market surveys in foreign countries;
(5) Facilitating the setting up of industries abroad by the Indian Entrepreneurs;
(6) Exchange of Trade Delegation and discussions;
(7) Setting up Commercial Missions of the Government of India abroad.

(c) Although no export targets have been fixed for the year 1969, all possible efforts are being made to increase our exports to these countries to the maximum extent possible.

Administrative Control of Steel Plants

1024. **Shri Om Prakash Tyagi:**
Shri Molahu Prasad:

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the management of the three Steel plants is not in the hands of experts of industries but it is in the hands of bureaucrats;

(b) if so, whether Government propose to set up a soon an Indian Industrial and Business Management Services on the pattern of Indian Administrative Service keeping in view the heavy losses being incurred by these plants and to hand over the management of such plants to the officers and the trained employees under this service; and

(c) if not, the reasons for spending public money on these plants which are incurring losses?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) No, Sir. Selections have been made by Government after tapping various sources and on considerations of suitability, technical and administrative ability, experience, etc. of the officer concerned.

(b) Does not arise.

(c) As explained in the Pamphlet entitled "Performance of Hindustan Steel Ltd.," copy of which was placed on the Table of the House on 5th April, 1968, the working results of Hindustan Steel have been and continue to be affected by a number of factors, some of which are of a basic nature. Steps are being taken to improve the working of the Company.

राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के मामले

1025. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के मामलों में कितने अधिकारियों को पकड़ा गया था और इनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे ;

(ख) कितने मामले सिद्ध हो गये और उनमें दोष सिद्धी हो गई है अथवा दण्ड दिया जा चुका है ;

(ग) धोखाधड़ी, उपेक्षा तथा ऐसे अन्य कारणों से, जिनका बाद में पता लगाया गया था, राज्य व्यापार निगम को कितनी हानि हुई ;

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, विभागीय जांच समिति अथवा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किसी विशेष समिति द्वारा इस समय कितने मामलों की जांच की जा रही है और उनका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इन कदाचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम के 9 अधिकारियों ने जो कथित उपेक्षा, चोरी, गबन, पद-स्थिति आदि के दुरुपयोग के मामले में अन्तर्ग्रस्त थे, 8 दोषी पाये गये तथा उन्हें उपयुक्त सजाएं दी गई हैं।

(ग) तथा (घ). उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में, जिनके अन्तर्गत लगभग कुल 1,143 रु० राशि है, राज्य व्यापार निगम ने, एक मामले को छोड़कर जहां से वसूली होनी अभी बाकी है, सभी मामलों में पहिले ही उपर्युक्त राशि की वसूली कर ली है। इसके अतिरिक्त, पांच मामलों की जांच की जा रही है। कथित जालसाजी के दो मामलों में हुई हानि लगभग 49,300 रु० है।

(ङ) राज्य व्यापार निगम ने उच्च प्रबन्ध-मंडल की एक सतर्कता समिति स्थापित कर दी है। यह सतर्कता के लिये तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्य के लिये कार्यक्रम बनाती है और इसके कार्यान्वयन की देख-भाल करती है। केन्द्रीय जांच विभाग के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है। एक शिकायत अनुभाग है और दर्शकों से भेंट उन अधिकारियों द्वारा की जाती है, जो सहायक प्रभागीय प्रबन्धकों से कम पद के नहीं होते। सूचना प्रगटीकरण तथा विलम्बों को रोकने के लिये सुरक्षा तथा अन्य उपाय किये गये हैं।

भारतीय आर्थिक तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडल का लातीनी-अमरीकी देशों का दौरा

1026. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय आर्थिक तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत तथा उस क्षेत्र के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में लातीनी अमरीकी देशों का दौरा किया था ;

(ख) क्या प्रतिनिधिमंडल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं, अभी तक नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में लाभ का बढ़ना

1027. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में लाभ बढ़ाने के लिए तीन सूत्रीय योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या संघ मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई "परफोर्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" नामक पुस्तिका में यह बताया गया था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुछ कठिनाइयां रहीं जिनसे उसके कार्य-करण पर असर पड़ा । इन कठिनाइयों को हटाने या कम से कम करने के उपायों पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

लघु उद्योग

1028. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री यशपाल सिंह .
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों के विकास करने और उन्हें बड़े पैमाने के उद्योगों के बराबर लाने के लिये उनका नवीकरण करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छोटे उद्यमियों को इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव भेजने के लिये कहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार ने छोटे कारखानों में बनायी जाने वाली वस्तुएं सरकारी क्षेत्र में न बनाने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण एवं उन्नत टेक्नोलाजी है जिससे वे बढ़िया किस्म की वस्तुएं बना सकें और लाभ कमाने वाले एककों के रूप में कार्य करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें ।

(ख) और (ग). सरकार का कार्यक्रम उत्पादन के क्षेत्रों, संयंत्र के आकार तथा इस प्रकार की टेक्नोलाजी अपनाने के सम्बन्ध में भावी उद्यमियों का मार्गदर्शन कराने और उन्हें सुझाव देने पर आधारित है जिससे छोटे पैमाने पर उत्पादन करना भी लाभदायक सिद्ध हो सके । उद्यमियों के सुझावों का भी स्वागत किया जाता है ।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं किया गया है ।

Indo-Nepal Trade

1029. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the steps taken to increase the trade between India and Nepal during this session ; and

(b) the steps Government propose to take for strengthening the trade relations in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Trade between India and Nepal, which is governed under the provisions of the Treaty of Trade and Transit (1960), has been moving with the minimum restrictions considered necessary from either side. In their desire to expand the trade, Government of India have been holding periodical talks with H.M.G. Nepal, beside encouraging Indian Industrialists for individual or joint ventures.

एल्यूमीनियम का निर्यात

1031. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, मूलतः निश्चित तारीख 31 दिसम्बर 1968 के बाद उत्पादकों से प्राप्त अनुरोध पर भी एल्यूमीनियम के निर्यात की अनुमति दे दी है ; और

(ख) क्या देश में मंदी की स्थिति जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक इस धातु का निर्यात जारी रखने की संभावना है अथवा इसके लिए कोई लक्ष तिथि निर्धारित कर दी गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). जी, हां । एल्यूमिनियम उत्पादकों से एल्यूमिनियम धातु की खरीद

के सम्बन्ध में विदेशों से की गई पूछ-ताछों के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये गये प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप, देश की आन्तरिक मांग तथा सप्लाई की स्थिति का पुनरावलोकन करने के पश्चात् भारतीय उत्पादकों द्वारा 31 दिसम्बर, 1968, के परे और 1969-70 वर्ष के दौरान भी एल्यूमिनियम और सैमिज के निर्यात की नीति जारी रखने का निश्चय किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि उत्पादकों की निर्यात सम्बन्धी बचनबद्धताएं देश में दुर्लभता की स्थितियां न उत्पन्न कर दें, उत्पादन, आन्तरिक मांग और सम्भावित निर्यात वचनबद्धताओं के सम्बन्ध में स्थिति के त्रैमासिक पुनरावलोकन करने का निश्चय किया गया है।

ग्रैफाइट अयस्क का आयात

1032. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **बैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रैफाइट अयस्क का आयात किन देशों से किया जाता है और भारतीय उद्योगों के लिये इसकी कितनी मात्रा में आवश्यकता है ;

(ख) आयातित ग्रैफाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिये सरकारी क्षेत्र में कच्चे ग्रैफाइट की किस्म सुधारने का एक कारखाना आरम्भ करने का कोई विचार है ?

बैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) प्राकृतिक ग्रैफाइट का आयात अधिकांशतः श्री लंका, कोरिया, प० जर्मनी, स० रा० अमरीका तथा ब्रिटेन से किया जाता है। प्रमुख उद्योगों की वर्तमान आवश्यकता लगभग 2,500 मे० टन प्रति वर्ष है।

(ख) आयातित प्राकृतिक ग्रैफाइट में 90 प्र०श० से अधिक ग्रैफाइट कार्बन होता है। वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में क्रमशः 12 लाख 84 हजार तथा 15 लाख 66 हजार रुपये के ग्रैफाइट का कुल आयात हुआ।

(ग) जी नहीं।

भरतपुर जिले में खस-तेल आसवन उद्योग

1033. **श्री प० मु० सईद :**

श्री मणि भाई जे० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भरतपुर जिले में खस-तेल आसवन उद्योग का विकास

करने तथा इसके आधुनिकीकरण की काफी गुंजाइश है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस उद्योग के प्रयोजन के लिए भरतपुर में सर्वोत्तम कच्चा माल उपलब्ध है ;

(ग) क्या देहरादून वन अनुसंधान संस्था ने वहां पर उपलब्ध कच्चे माल की क्षमता का पता लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस उद्योग से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ; और

(च) यदि हां, तो इस उद्योग का शीघ्र विकास करने तथा इसके आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लक्कदीव का सर्वेक्षण

1034. **श्री प० मु० सईद** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव में खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिए लक्कदीव का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) और (ख). जी, हाँ। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1963-64 वर्ष के दौरान लक्कदीव में चूने-पत्थर और फास्फेट के लिये अन्वेषण किया गया था। अब तक की गई खोजों से फास्फेट के एक छोटे से निक्षेप और 20,000 लाख मैट्रिक टन अनुमानित उपलब्ध राशियों के उच्च श्रेणी चूना-पत्थर के निक्षेपों के पाये जाने का पता लगा है। तट के दूर के क्षेत्रों के सर्वेक्षण से कारावती लैगून में 46 लाख मैट्रिक टन और कलपेनी लैगून में 110.0 लाख मैट्रिक टन के चूनेदार तलछट की सम्भावित उपलभ्य राशियों के संकेत मिले हैं। इन क्षेत्रों में आगे कार्य प्रगति पर है।

टेलीविजन सेटों का आयात

1036. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी, आयरलैंड तथा यूगोस्लाविया से आयात किये जाने वाले

टेलीविजन सेटों की तुलना में जापान से आयात किये गये टेलीविजन सेटों की भारत पहुंचने पर लागत कम है परन्तु उपर्युक्त देशों की तुलना में जापान से कम सेटों का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो जापान से कम टेलीविजन सेटों का आयात करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जापान से आयातित टेलीविजन सेट 16 स्क्रीन के थे जबकि हंगरी, आयरलैंड तथा यूगोस्लाविया से आयातित टेलिविजन सेटों की स्क्रीम 23 है, इसलिए उनकी भारत में पहुंचने की लागतों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। किन्तु जापानी सेटों के आयात की अनुमति अफ्रीका से स्वदेश लौटने वाले एक भारतीय को उसके प्रत्यावर्तन पर अपनी बिक्री के अन्य माल के साथ लाने के लिये दी गई थी, अतः उसके सीमित होने के कारण केवल उसके पास उपलब्ध जापानी सेटों का ही आयात करने दिया गया था।

तंजौर तथा रामनाथपुरम में लघु उद्योग

1037. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तंजौर तथा रामनाथपुरम में लघु उद्योगों का विकास करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग सेवा संस्था ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्रास द्वारा रामनाथपुरम और तंजौर जिलों में किये गये क्षेत्र विकास सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित उद्योगों के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं।

जिला रामनाथपुरम

(1) पाइरो टेकनिक एल्यूमिनियम पाउडर।
(2) ओटने की मिलों के पुर्जे।
(3) लकड़ी का फर्नीचर।
(4) क्राउन कार्क।
(5) ताप सह मिट्टी की बनी वस्तुएं।
(6) एल्यूमिनियम के खोखले बर्तन।

जिला तंजौर

(1) चूने के भट्टे ।
(2) गत्ता ।
(3) चावल की भूसी का तेल ।
(4) काजू की गिरी का परिष्करण ।
(5) काजू के छिलके से तेल निकालना ।
(6) पीतल के ढलाई कारखाने ।
(7) कांच की नकियां ।
(8) बिजली के पीतल के बने बल्वों के होल्डर ।
(9) लकड़ी के पेंच ।
(10) लीथो और आफसेट छपाई ।
(11) जहाजी रसायन ।
(12) चमड़ा कारखाना ।
(13) साइकिल के हिस्से और सहायक सामान ।
(14) नारियल से तेल निकालना ।
(15) शार्क मछली का तेल ।

2. सिफारिश का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की आशा है ।

यूरोप में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित माल जोड़ने का कारखाना

1038. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** **श्री अदिचन :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की वस्तुओं के विदेशी खरीदारों को हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार यूरोप में एक निर्माणशाला स्थापित करने की सम्भावना का पता लगा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की वस्तुओं की सप्लाई करने के बारे में कनाडा तथा अमरीका की फर्मों के साथ ठेके किये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर विदेश के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताएं विशेष रूप से माल देने की तारीख और मशीनों, औजारों तथा सहायक पुर्जों के विविध

विशिष्ट विवरणों को पूरा करने के लिये यूरोप में पुर्जे जोड़कर मशीनें तैयार करने का एक संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने अपने द्वारा बनाई मशीनों की कनाडा और अमरीका में बिक्री के लिये इन देशों की फर्मों के साथ संविदा किये हैं ।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर तथा उसके विदेश स्थित एजेन्टों के साथ किये गए प्रबन्ध वाणिज्यिक संविदाओं के रूप में हैं और उसके ब्योरे बताना उपयुक्त नहीं समझा जाता है ।

(घ) कम्पनी की वस्तुओं के विदेशों को भेजे जाने वाले माल का 1968-69 में 114 लाख रुपये के मूल्य का लक्ष्य रखा गया है जो 1970-71 में बढ़ कर 200 लाख रुपये कर दिया जायेगा ।

केरल में बीड़ी उद्योग का पुनर्गठन

1039. **श्री गार्डिलिगन गौड़ :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य के बीड़ी उद्योग के पुनर्गठन के लिये एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । कैनानूर जिले की गणेश, भारत और दरबार बीड़ी फैक्टरियों के बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार दिलाने की एक योजना केरल सरकार से प्राप्त हुई है ।

(ख) योजना में 20 प्राथमिक और एक केन्द्रीय सहकारी समिति के गठन द्वारा उन 10.325 बीड़ी कर्मचारियों को रोजगार दिलाने और उन्हें अनुदान और ऋण देकर आर्थिक सहायता देने का उल्लेख है जो बीड़ी सिगार अधिनियम के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गए हैं । पांच वर्षों की अवधि के लिये सोची गई कुल सहायता की राशि अनुदान के रूप में 7.07 लाख रुपये और ऋण के रूप में 108.05 लाख रु० है । राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि रिजर्व बैंक इस योजना को पुनः वित्त प्रदान के लिये स्वीकार करे और स्टेट कोआपरेटिव बैंक, सरकार की प्रतिभूति पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करे ।

(ग) योजना विचाराधीन है ।

प्रतापनगर से छोटा नागपुर तथा राजपिपला से अंकलेश्वर स्टेशनों तक बड़ी रेलवे लाइन

1040. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे पर प्रतापनगर (बड़ौदा) छोटा उदयपुर तथा राजपिपला-अंकलेश्वर रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के प्रस्तावों को अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया है;

(ख) क्या उक्त प्रस्तावों के बारे में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों में से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). इस समय पश्चिम रेलवे छोटी लाइन की कार्य-प्रणाली की समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा में प्रतापनगर-छोटा उदयपुर (न कि छोटा नागपुर) और अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन खण्ड शामिल हैं। इन खण्डों को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर इस समीक्षा के परिणामों का पता चलने और रेलवे बोर्ड द्वारा उनकी जांच किये जाने के बाद विचार किया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को ऋण

1041. **श्री भगवान दास :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) क्या ऋण को कम करने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) क्या एक प्रस्ताव अतिरिक्त विनियोजन द्वारा ऋण के भाग को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त पूंजी किस प्रकार लगाई जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31 मार्च, 1968 तक सरकार द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, को 53150 लाख रुपयों ऋण के रूप में दिया जा चुका था जिसमें कि 1100 लाख रुपये का अल्प-कालीन ऋण भी शामिल है।

(ख) से (घ). 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई "परफार्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" नामक पुस्तिका में यह बताया गया था कि इस्पात कारखानों को कुछ कठिनाइयां रहीं जिनका उनके कार्यकरण पर असर पड़ा। इन कठिनाइयों को दूर करने या उन्हें कम से कम करने के लिए अभिकल्पित उपाय विचाराधीन हैं।

Central Small Industries Corporation, Indore

1042. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5976 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the agency through which financial assistance is provided to small-scale industrial units by the Central Small Industries Corporation, Indore and Small Industries Service Institutes;

(b) the justification for setting up of the Corporation ; and

(c) their functions ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) The Small Industries Service Institutes do not give financial assistance to small scale Industrial units. There is also no Central Small Industries Corporation at Indore.

(b) and (c). Do not arise.

British India Corporation Units

1043. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the units of the British-India Corporation Limited, Kanpur are running into losses ;

(b) whether it is also a fact that the Managing Director and other Directors of the above Corporation have disposed of many of its units in an illegal manner and have retrenched thousands of labourers ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) While the Cooper Allen and North-West Tannery Branches of the British India Corporation Limited have been incurring losses for thc past few years, the woollen branches also incurred heavy losses during 1967.

(b) and (c). According to the information obtained from the company, the company has not sold any of its units in an illegal manner and the question of retrenchment of thousands of labour does not arise. However if the Hon'ble Member has in mind the sale of shares in two sugar companies or some bungalows to its subsidiary, these matters will be looked into by the Investigating Authority appointed under the Industries (Development and Regulation) Act. There is also a civil suit pending before the Calcutta High Court regarding the sale of shares in sugar eompanies. If the reference is to the Cooper Allen and North-West Tannery Branches, the position is that at the Extraordinary General Meeting held on the 14th February, 1969, the shareholders of the British India Corporation Limited passed a resolution unanimously approving the transfer of the said Branches to Government on certain conditions.

Employees in the Undertakings

1044. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 368 on the 12th November, 1968 regarding the number of employees working in the undertakings and state :

(a) whether the information asked for has since been collected :

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

Factories Registered with Directorate General of Technical Development

1045. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5975 on the 27th August, 1968 and state :

(a) the reasons for not supplying the information regarding the registered industrial units stated to be available in the handbooks of indigenous manufacturers of (i) Engineering Stores, and (ii) Chemical and Miscellaneous Stores published by the Directorate-General of Technical Development from time to time; and

(b) when the Directorate-General of Technical Development was established, reasons for its establishment; how it was established and the justification thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The number of industrial units registered with the Directorate-General of Technical Development, at any given time, aggregate to several thousands. Since the information desired could be had from the priced publication indicated, it has not been considered necessary to duplicate the effort.

(b) The Directorate-General of Technical Development, earlier known as the Development Wing, was established in 1951 to meet the post-war needs of consolidation in the industrial field. It was intended to assist in securing a well balanced and properly coordinated pattern of industrial development in the country. On the declaration of the Emergency in 1962, this organisation was re-designated as the Directorate-General of Technical Development with the added responsibility of guiding in the mobilisation of production for Defence purposes. This organisation serves as the model Technical Advisory Agency to the Government of India on all matters concerning industrial development both in the private and public sector.

वाराणसी के निकट ट्रैक्टर कारखाना

1046. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के निकट ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई नया स्थान चुना गया है ।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). ट्रैक्टर परियोजना, जिसकी स्थापना के लिये वाराणसी के समीप स्थल को चुना गया था चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से जीटर 2011 ट्रैक्टर बनाने की पूर्णत: नई परियोजना थी । इसके पश्चात् केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसंधान संस्था और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर ने एक 20अश्व शक्ति के ट्रैक्टर का आद्यरूप तैयार किया है । यह सुझाव दिया गया है कि प्रस्तावित परियोजना इस नमूने के ट्रैक्टरों के निर्माण का काम हाथ में ले । यह भी वांच्छनीय समझा गया है कि परियोजना माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थिति एकक में उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करे । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को इन सब पहुलओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने और सिफारिश करने के लिये कहा गया है । अंतिम निर्णय इस प्रतिवेदन की प्राप्ति तथा जांच के बाद ही किया जायेगा ।

अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन

1047. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल जनवरी, 1969 में भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे का क्या परिणाम निकला और बातचीत का यदि कोई परिणाम निकला तो क्या ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) उनके दौरे का उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि जनरल मोटर्स के योरुप के संयंत्र के लिये हिन्दुस्तान मोटर्स से किस सीमा तक मोटर गाड़ियों के हिस्सों तथा पुर्जों जिनमें ढलाई हुआ समान भी सम्मिलित है को खरीदा जा सकता है। दल द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों में हुई बातचीत से यह पता चला कि मोटर गाड़ियों की सहायक वस्तुओं तथा पुर्जों के निर्यात वस्तुओं के विकास की सम्भावनाएं हैं।

स्कूटर टायरों का आयात

1048. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्कूटर टायरों का सम्भरण बढ़ाने के लिये उनका आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने टायर आयात किये जाने की सम्भावना है और उसका मूल्य क्या होगा; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 11 लाख रुपयों की अनुमानित कीमत के करीब 38,500 स्कूटर टायर।

(ग) लगभग 11 लाख रुपये।

तमिलनाडु के विद्यार्थियों द्वारा गाड़ियां रोकना

1049. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से समाचार प्रसारण के प्रश्न पर 9 जनवरी, 1969 को तमिलनाडु के विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन किये जाने के कारण दक्षिण रेलवे पर 25 से अधिक गाड़ियां रोकी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन तथा गाड़ियों के रोके जाने के परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 13,373 रुपये ।

कुदुरेमुख में लोह अयस्क निकालना

1050. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 26 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदुरेमुख में लोह अयस्क के खनन के बारे में तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहारिकता और संयंत्र के बारे में अग्रिम अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अयस्क के वाणिज्यिक खनन के बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं । अध्ययन 1 दिसम्बर, 1968, से प्रारंभ किये गये हैं और उन्हें पूरा करने में 18 महीने लगेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Provision of Passenger Facilities in Railway Bogies

1051. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the number of Ist Class, IInd Class and IIIrd Class bogies being used for railway travel in the country ;

(b) the number out of them in which all the passenger facilities like fan, electricity, etc. are not available ;

(c) the time by which these deficiencies would be removed ; and

(d) whether Government propose that these bogies would not be used so long as all the facilities are not available in them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-126/69.]**

(b) and (c). Electric lights and fans have been provided in all the coaches. In some old passenger coaches, however, which have since completed their useful life, only fans are not provided. These coaches are due to be condemned and replaced. It is not proposed to provide fans in such coaches.

(d) No.

मैंगनीज अयस्क खनन उद्योग

1052. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज़ अयस्क खनन उद्योग संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संकट को दूर करने तथा उद्योग को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारत में मैंगनीज उद्योग विकट परिस्थितियों में से गुजर रहा है ।

(ख) इस उद्योग को सहायता प्रदान करने की संभावनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन कानपुर की कूपर एलन तथा नार्थ वेस्ट टैनरी शाखायें

1053. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री नन्दकुमार सोमानी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कूपर एलन और नार्थ-वैस्ट टैनरी ब्रांचों को अपने हाथ में लेने का इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन शर्तों पर लिया जा रहा है; और

(ग) इन एककों की क्रियान्विति के लिए स्थापित किये जाने वाले निदेशक बोर्डों का गठन तथा कार्यप्रणाली क्या होगी तथा इन एककों के प्रबन्ध तथा नियंत्रण में सरकार तथा निजी भागीदारों का कितना-कितना हाथ होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इन दो एककों के प्रबन्ध के लिए पूरे सरकारी स्वामित्व की एक नई कम्पनी जिसका नाम टैनरी एण्ड फुट वेयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बनाई गई है ।

विवरण

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के दो एककों को हस्तगत करने की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के प्रबन्धक इन दो एककों की अचल आस्तियां जैसे भूमि, इमारतें तथा मशीनें और अन्य आस्तियां नई कम्पनी को एक रुपये के नाम-मात्र मूल्य पर सौंप देंगे ।

(2) कच्चे माल, स्टोर तथा उन चालू फालतू पुर्जों को जो कि काम आ सकने वाले हों को नई कम्पनी को उस मूल्य पर हस्तान्तरित किया जायगा जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म मैसर्स बाटलीबाय एण्ड कम्पनी भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी दल के परामर्श से तय करेगी । चार्टर्ड एकाउंटेंट की फर्म द्वारा इन आस्तियों का मूल्य 17,57,991 रुपये आंका गया है और उनका प्रतिवेदन इस समय विचाराधीन है ।

(3) नई कम्पनी ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन इन दो एककों के बिक्री तिथि से पूर्व के किसी ऋण देयता कर्जा, अग्रिम धनराशि और दायिता की जिम्मेवार नहीं होगी । यह जिम्मेदारी ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की होगी और इनका भुगतान वह जैसे भी उपयुक्त समझे करेगा । इसी प्रकार नई कम्पनी उक्त कारपोरेशन की इन दो शाखाओं को बिक्री तिथि से पूर्व दिए गए जमा खातों और अग्रिम धनराशियों को नहीं लेगी ।

(4) बिक्री तिथि तक निर्मित उत्पादों को नई कम्पनी नहीं लेगी ।

(5) उन कर्मचारियों की जिन्हें नई कम्पनी अपनी नौकरी में रखेंगी ग्रैच्युटी आदि की पूरी जिम्मेदारी नई कम्पनी की होगी और वे कर्मचारी अपनी इकट्ठी की गई छुट्टी को लेने के हकदार होंगे और ऐसे कर्मचारी जिन्हें नई कम्पनी अपनी नौकरी में नहीं रखेगी उनको देय राशि जिनमें नौकरी से हटाए जाने का हरजाना भी सम्मिलित है की जिम्मेदारी कारपोरेशन की होगी ।

आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन

1054. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष दिसम्बर के चौथे सप्ताह में आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन को केन्द्रीय समिति का सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या मांगें तथा प्रस्ताव रखे गये थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) उनके संकल्प की एक प्रति (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 127/69]**

(ग) अखिल भारतीय उत्पादक संघ द्वारा की गई सिफारिशों को नोट कर लिया गया है।

Resignation of Traffic Apprentices on North-Eastern Railway

1055. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the conditional resignations of Traffic Apprentices belonging to the Scheduled Castes, who tendered these resignations due to the discriminatory treatment meted out to them, have been accepted by the North-Eastern Railway ;

(b) whether it is a fact that the resignations were printed and according to rules the signatures were not in ink ;

(c) whether it is also a fact that resignations were not accepted by the said Railway in the first instance ;

(d) whether these rejected resignations were accepted later on whereas no resignation was given second time ; and

(e) the reasons for not holding an open enquiry into these illegal deeds and for not taking action against the responsible officers ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). No, Sir.

(d) and (e). Do not arise.

Scheduled Caste Traffic Trainees on North-Eastern Railway

1056. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports on the 12th November, 1968 and 1st January, 1969 from the Members of Parliament in regard to the ill-treatment meted out to the Traffic Trainees belonging to the Scheduled Castes by the North-Eastern Railway officials during 1965—68 ;

(b) whether it has been made clear in those reports that the basic question is that of the payment of pay and other emoluments and other facilities, which facts have been given in the reports with references ; and

(c) whether Government propose to associate the affected employees and hold an open enquiry ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Yes; but the reports are not correct.

(c) No, Sir.

Railway Guards

1057. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether according to the rules of the Railway Ministry, right of those temporary employees, who are selected for higher posts either by department or by Railways Service Commission to get themselves confirmed on their previous posts is reserved till they are confirmed on the new posts;

(b) whether it is a fact that the names of some Guards appointed on the 3rd November, 1960 were removed from the employees roster by the Jodhpur Division illegally because they went on training for higher post;

(c) whether some of the Guards out of them were declared permanent after the dates on which the Guards, whose names were removed from the roster, were working there;

(d) whether such Guards will now be declared permanent; and

(e) the reasons for not punishing the officers responsible for making changes in the Rules?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

विदेशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी का समर्थन

1058. **श्री बेदब्रत बरुआ :**
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी का समर्थन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या भारत में उद्योगपतियों के संगठनों ने इस बात का विरोध किया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) तकनीकी ज्ञान के आयात की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने यह

निश्चय किया है कि उन क्षेत्रों में विदेशी पार्टियों के साथ समन्वित रूप से पत्र-व्यवहार किया जाना चाहिए जिनमें :

(1) पहले से ही अनेक विदेशी सहयोग करार किये जा चुके हैं और उसी अथवा उसी प्रकार की तकनीकी जानकारी के लिए कोई नई पार्टी पुनः आवेदन करती है; अथवा

(2) उन्हीं क्षेत्रों में देश में लगभग उसी समय अनेक नये कारखाने लगाने का विचार है, जिसका उद्देश्य :

(क) विदेशी मुद्रा को बाहर जाने में कमी करना;

(ख) देश में अनुसंधान और टेक्नोलाजी के विकास को प्रोत्साहन देना।

सरकार का बिचार ऐसे अधिकरण की स्थापना का नहीं है जो कि तकनीकी ज्ञान को खरीद कर, उसे विकसित कर और उन्हें चाहने वालों को बेचे। सरकार का काम प्रारम्भिक अवस्था में विदेशी तथा भारतीय कम्पनी से केवल विचार-विमर्श का होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार विभिन्न चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के अध्यक्षों के विचारों की जांच करने पर इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके अधिकांश भ्रम सरकार की नीति को ठीक रूप से न समझने के कारण थे। सरकार उनके भ्रम निवारण के लिए समय-समय पर अपनी नीति स्पष्ट करती रही है। मैंने 29 अक्तूबर, 1968 के प्रेस सम्मेलन में नीति की स्पष्ट व्याख्या कर दी थी।

उत्तरी बंगाल में बाढ़ के कारण रेलवे पटरियों की क्षति

1059. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के अन्त में उत्तर बंगाल में बाढ़ के कारण असम को मिलाने वाली रेलवे पटरी को जो क्षति हुई थी क्या उसकी इस बीच पूरी तरह मरम्मत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में होने वाली संभावित तबाही से बचाने के लिये, इस पटरी में सुधार करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने के बारे में आगे क्या कार्य करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) असम को मिलाने वाली रेलवे लाइन को हुई क्षति की अस्थायी रूप से मरम्मत कर दी गयी है और स्थायी पुनर्स्थापन काम हो रहा है।

(ख) और (ग). मीटर लाइन रेल सम्पर्क पर आगे जो निर्माण-कार्य करने का विचार है वे इस प्रकार हैं :—कटिहार-सिलीगुड़ी खण्ड के गलगलिया-पिपरीथान स्टेशनों के बीच और तायबपुर-आलुबाड़ी स्टेशनों के बीच रेल के तट को ऊंचा उठाना; और बोंगाईगांव-अलीपुरद्वार खण्ड पर जोड़ई और श्रीरामपुर असम के बीच मीटर लाइन के संकोश पुल का विस्तार। जहां

तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का सम्बन्ध है, उस पर आगे निर्माण-कार्य सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा नियुक्त उत्तर बंगाल में बाढ़ों के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की अन्तिम सिफारिशों पर निर्भर करेंगे ।

बड़ी लाइन का गोहाटी तक विस्तार

1060. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में गोहाटी तक बड़ी लाइन के विस्तार करने का निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका डिब्रूगढ़ तक अग्रेत्तर विस्तार किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). बड़ी लाइन को गुवाहाटी तक बढ़ाने के प्रस्ताव की आवश्यकता और आर्थिक सक्षमता का पता लगाने की दृष्टि से हाल में ही बोंगाईगांव-गुवाहाटी खंड के बदलाव के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण और निचली ब्रह्मपुत्र घाटी की परिवहन आवश्यकताओं के बारे में गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण कराये गये हैं । इन जांचों के परिणाम मालूम होने के बाद ही इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जा सकता है । बड़ी लाइन सम्पर्क को गुवाहाटी तक बढ़ाने का निर्णय कर लेने के बाद ही डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

सीमेन्ट आवंटन तथा समन्वय संगठन निधियों के बारे में जांच

1061. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री क० रमानी :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कं० हाल्दर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट आवंटन तथा समन्वय संगठन द्वारा विकास निधि से रुपया निकाल कर राजनैतिक दलों की चुनाव निधि में देने के बारे में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब पूरी किये जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत सीमेंट आवंटन तथा समन्वय संगठन के लेखे की किताबों का निरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। सुनिश्चित तथ्यों से लगाये गये अनुमान की प्रकृति, तथा इसके पश्चात् किये जाने के लिये कार्यवाही, विधि मंत्रालय के परामर्श से, परीक्षान्तर्गत है। परीक्षा के मध्य, विधि मंत्रालय ने प्रलेखों की मांग की, जो सीमेंट का आवंटन तथा समन्वय संगठन के सम्पूर्ण संघटक एककों से प्राप्त करने थे। मामला अभी तक परीक्षान्तर्गत है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में जांच करने के लिये समिति

1062. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जागेश्वर यादव :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री जनार्दनन :
श्री क० लकप्पा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री ज० अहमद :
श्री दिनकर देसाई :
श्री समर गुह :
श्री ब्रजभूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री सूरज भान :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीतियों के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समिति ने सरकार को सूचित किया है कि उसका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होने के कारण सम्बन्धित जानकारी और आंकड़ों को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में

अनुमान से अधिक समय लग गया है। समिति को आशा है कि वह सरकार को जून, 1969 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

बाढ़ों के कारण उड़ीसा में रेल की पटरी तथा सम्पत्ति को हानि

1063. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की बाढ़ों तथा तूफान के कारण उड़ीसा में रेलवे की पटरियों तथा सम्पत्ति को कितने मूल्य की हानि हुई ;

(ख) क्या क्षतिग्रस्त पटरियों की पूरी मरम्मत कर ली गई है ;

(ग) इस मार्ग पर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों को पुनः चालू न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विभिन्न स्थानों पर, जहां दरारें पड़ी थीं, बाढ़ का पानी निकालने के लिये बनी पुलियां चौड़ी की जा रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर उन्हें कितना चौड़ा किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) लगभग सत्तर लाख रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) लाइनों में टूट-फूट के कारण जिन गाड़ियों को रद्द किया गया था, उनमें से 99 अप/100 डाउन को छोड़कर बाकी सबको चलाना उत्तरोत्तर शुरू कर दिया गया है। आशा है 1 मार्च, 1969 तक ये गाड़ियां भी चलने लगेंगी।

(घ) जी हां, जहां आवश्यक समझा गया।

(ङ) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्धा रोड-पलांसा खण्ड पर सोलारी और बालूगांव स्टेशनों के बीच पुल नं० 838 में 40 फुट का एक अतिरिक्त स्पैन लगाया गया है।

विदेशी सहयोग प्राप्त परियोजनाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात

1064. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहयोग संबंधी समझौतों पर निर्यात करने के बारे में कोई प्रतिबंध लगाये गये हैं ;

(ख) क्या देश में उत्पादित कर रही विदेशी सहयोग प्राप्त परियोजनाओं से वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो देश के कुल निर्यात की तुलना में इन परियोजनाओं में निर्मित वस्तुओं के निर्यात की प्रतिशतता क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां, पुराने करारों में, विशेषतया जबकि देश औद्योगिक विकास के भारी कार्यक्रम को आरम्भ कर रहा था। तथापि अब नीति यह है कि जब निर्यात की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले वर्तमान सहयोग करार नवीकरण के लिये आयें अथवा जब नये करार किये जायें तब इस प्रतिबन्ध को पूर्णत: समाप्त कर दिया जाये अथवा काफी हद तक हटा दिया जाये, सिवाय शायद विदेशी सहयोगकर्ता के देश के संबंध में अथवा उन देशों के विषय में जहां विदेशी सहयोगकर्ता उत्पादन के उसी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम चला रहा हो।

(ख) कुछ प्रायोजनाओं, जिन्हें विदेशी सहयोग से स्थापित किया गया है, के उत्पादों को निर्यात किया जा रहा है।

(ग) सही जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

भारत-रूस व्यापार

1065. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री श्रीचन्द गोयल
श्री क० लकप्पा
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री अदिचन :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 के लिये रूस के साथ भारत की व्यापार योजना को अन्तिम रूप देने हेतु एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल ने उस देश का हाल में दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस सरकार भारत-रूस व्यापार के ढांचे में जो कि काफी समय से चल रहा था, पुन: समायोजन करने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो रूस सरकार जिस पुन: समायोजन के लिये सहमत हुई है, उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1968 में एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल सोवियत संघ गया था और उसने प्रबन्ध को अन्तिम रूप दिया था जैसा कि वर्ष 1969 के लिये भारत और सोवियत संघ के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान हेतु सोवियत संघ के साथ दीर्घकालीन व्यापार तथा भुगतान करार में अपेक्षित है।

प्रतिनिधिमण्डल ने इस अवसर से लाभ उठाकर सोवियत प्रतिनिधिमंडल को यह समझाया कि गत कुछ वर्षों में भारत में औद्योगिक क्षमता का, विशेषतः भारी उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है, जिससे तैयार संयंत्र तथा मशीनरी की अपेक्षा कच्चे माल की हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। सोवियत प्रतिनिधिमण्डल ने इस बात को समझा जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के आदान-प्रदान को इस तरह समायोजित किया गया है कि भारतीय आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

1066. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के 1,200 मुसलमान कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था के दो विशेष होस्टलों में रहने की व्यवस्था की गयी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनको वहां बसाने के लिये कुल कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) इन कर्मचारियों को किस प्रकार की विशेष सहायता दी गयी है और इस सहायता पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) इन कर्मचारियों को अलग रखने और दो समुदायों के बीच कृत्रिम दूरी पैदा करने की बजाय इनमें भावनात्मक एकता बढ़ाने के विचार से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विभिन्न क्षेत्रों में इन कर्मचारियों को न बसाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अगस्त, 1967 के साम्प्रदायिक दंगों से कितने हिन्दू कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ा था और उन्हें अब तक कितनी और क्या विशेष सहायता दी गयी है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). अगस्त 1967 में रांची में हुए उग्र साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप अधिकांश मुस्लिम कर्मचारियों और उनके परिवारों को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की बस्ती में प्रशिक्षण संस्थान के दो छात्रावासों में रखा गया था ताकि उन परिवारों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जा सके। लगभग 500 परिवार इस समय भी इन छात्रावासों में रह रहे हैं। 25 अगस्त, 1967 से लेकर 15 अक्तूबर, 1967 तक प्रबन्धक-वर्ग ने इन परिवारों के लिए मुफ्त भोजन, दूध, ईंधन आदि की व्यवस्था की थी। तत्पश्चात् इन परिवारों को निम्न प्रकार से सहायता दी गई है :—

1—22 अगस्त, 1967 से 15 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि के लिए अनुपस्थिति विशेष आकस्मिक छुट्टी मानी गई है।

2—इन कर्मचारियों को काम से अनुपस्थिति के समय के लिए वेतन दिया गया है और दो मास का मूल वेतन अग्रिम रूप में दिया गया है।

3—प्रत्येक जानी नुकसान के लिए 500 रुपये की रकम अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में दी गई है और दंगों में मारे गये कर्मचारियों के नाम खड़े अग्रिम धन की रकम को माफ कर दिया गया है—ऐसे अग्रिम धन की रकम को छोड़कर जो मोटर कार तथा अचल सम्पत्ति को खरीदने के लिए दी गई थी।

4—मृतक कर्मचारी के परिवार के उस पर आश्रित एक सदस्य को नौकरी दी गई है। प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को सहायता और पुनर्वास पर किया गया कुल व्यय 5.14 लाख रुपये है।

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का प्रबन्धक वर्ग इन मुसलमान कर्मचारियों को इस निगम की बस्ती के विभिन्न सेक्टरों में बसाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार इनको बसाने और किये गये अन्य उपायों के द्वारा प्रबन्धक वर्ग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है कि बस्ती में विभिन्न सम्प्रदाय मिल-जुल कर और शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें।

(घ) तीन हिन्दू कर्मचारियों को, जो दंगों से प्रभावित हुए थे, कुल 950 रुपये अग्रिम वेतन के रूप में दिये गये थे।

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

1067. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी को कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क का उल्लंघन करते हुए 23,105 रुपये अधिक देने पर डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) फरवरी, 1967 में यह गैर-कानूनी कार्य किये जाने तथा 20 अगस्त, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर में दिये गये आश्वासन के बावजूद निश्चित कानूनी कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). विधि मंत्रालय का परामर्श प्राप्त कर लिया है व इसका अध्ययन किया जा रहा है।

M/s. Kila Chand Devi Chand and Co., Bombay

1068. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the capital of M/s. Kila Chand Devi Chand and Company, Bombay and its allied

establishments prior to Independence and at present ;

(b) the number of companies set up under this establishment during the last twenty years ; and

(c) the percentage of increase in the capital of this company from 1947 to 1968 ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) According to the information collected by the Monopolies Enquiry Commission, the aggregate paid up capital of M/s. Kila Chand Devi Chand and Company, Bombay and 11 other companies included in 'Kila Chand Group' was of the order of Rs. 9.3 crores during 1963-64. The figure stood at Rs. 9.9 crores during 1966-67. Information for the earlier and later years is not available.

(b) Out of the 12 companies included by the Monopolies Inquiry Commission in Kila Chand Group, 7 were established after 1949.

(c) The aggregate paid up capital of companies included by the Monopolies Inquiry Commission in Kila Chand Group showed an increase of 6.5% during the period from 1963-64 to 1966-67. There was however no increase in the paid up capital of M/s. Kila Chand Devi Chand and Company Ltd. itself during this period. Information for the earlier and the later years is not available.

Export of Walnuts and Walnut Wood

1069. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that walnuts and walnut wood are exported to foreign countries in huge quantities ;

(b) if so, the quantity exported to each country during the last five years ;

(c) whether most of the fruit and wood for export is supplied from Jammu and Kashmir ; and

(d) if so, whether Government are taking any steps to increase its production and also improve its quality in that State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak): (a) (i) **Walnuts** : Yes, Sir.

(ii) **Walnut Wood** : Export of walnut wood is not normally allowed in huge quantities as this wood is in short supply even to meet domestic demand, part of which goes into the manufacture of articles which are exported.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-128/69]**

(c) Yes, Sir.

(d) A detailed study of the various aspects of production and exports of Walnuts is being made by the Director of Horticulture, Government of Jammu and Kashmir and the Central Government.

व्यापारिक गतिविधियों में विदेशी सहयोग

1070. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल में व्यापारिक गतिविधियों में विदेशी सहयोग की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से किया है ; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होंगे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। केवल उन्हीं व्यापार कार्यों में विदेशी सहयोग की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है जहां ऐसे सहयोग का एकमात्र उद्देश्य हमारी निर्यात बिक्रियों को बढ़ाने का हो।

(ख) तथा (ग). ऐसी छूट से बड़ी विदेशी व्यापार संस्थाओं की तकनीकी जानकारी तथा उनके विपणन माध्यमों का उपयोग करना सुकर हो जायेगा तथा दुर्गम बाजारों में विशेषतया भारत के परम्परागत निर्यातों के लिये, प्रवेश करने में सहायता मिलेगी।

Export of Iron Ore by National Mineral Development Corporation

1071. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Mineral Development Corporation has suffered a loss of Rs. 5 crores approximately in the export trade of iron ore last year ;

(b) if so, the reasons thereof ; and

(c) the steps taken to check the loss in the export trade of iron ore in future ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The loss incurred by the National Mineral Development Corporation on the supply of iron ore to Japan during the financial year 1967-68 was Rs. 141 lakhs roundly, and not Rs. 5 crores.

(b) Production from the Kiriburu and Bailadila Iron Ore Mines is exported to Japan at prices negotiated by the Minerals and Metals Trading Corporation Ltd., with Japanese Steel

Mills. The F. O. B. T. sales realisation is utilised to defray the following items of expenses :—

		Average % of FOBT sales realisation
1.	Export Duty ..	14.6
2.	Port Charges ..	14.4
3.	Railway freight ..	48.7
4,	MMTC's commission ..	1.4
5.	Royalty to State Govt. and Labour Welfare Cess ..	3.2
6.	Interest charges on Govt. loan, Yen Credit and working capital ..	3.6
7.	Depreciation ..	6.8
8.	Mine operating cost ..	12.5
	Total ..	105.2

After items of expenses as at 1–5 above have been met out of the total FOBT sales realisation, only residual amount is available to the National Mineral Development Corporation to meet the operational cost and the depreciation provision as would be seen from the above table, in as much as, after payment of various charges only 14.1 per cent of FOBT sales realisation is left for National Mineral Development Corporation to meet the operating cost and depreciation which really amount to 19.3 per cent. This deficit of 5.2 per cent represents the national loss booked in N.M.D.C's accounts. There is, however, no loss to the National Economy because of the earning of export duty @ Rs. 10.50 per tonne, which amounted to Rs. 2.36 crores.

(c) For considerations of overall national economy, the loss of Rs. 141 lakhs is out weighed by the export duty—Rs. 2.36 crores received by the Government and the valuable foreign exchange of about Rs. 10.82 crores earned.

Improvements being effected in the mining, transport to the ports and shipping of ores, are expected to reduce the loss.

Iron and Steel Plants in the Country

1072. **Shri Lakhan Lal Gupta :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number and names of Iron and Steel Plants in the Public Sector in the country and the production capacity of each ;

(b) the items manufactured in these Plants for house building purposes ;

(c) whether retail shops have been opened in these plants for the sale of their products ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) There are in the public sector, three integrated steel plants at Bhilai, Rourkela and Durgapur, one Alloy Steels Plant at Durgapur and the Mysore Iron and Steel Works at Bhadravati. At the end of current expansion, Bhilai, Rourkela and Durgapur Steel Plants will respectively have an installed capacity of 2.5, 1.8 and 1.6 million ingot tonnes per annum.

The Alloy Steels Plant at Durgapur will have a capacity of 1,00,000 tonnes of ingot production, The Mysore Iron and Steel Works will have a capacity of 77,000 tonnes of Alloy and Special Steels.

(b) These plants manufacture a variety of items which can be used for house-building purposes, e.g., Structurals, Bars and Rods, Galvanised Sheets, Skelp, Hot Rolled Coils, etc.

(c) and (d). These are tonnage plants where economical production requires a certain minimum tonnage and quick clearance. The manufactured items are sold in bulk. No retail shops have, therefore, been opened in these plants. Hindustan Steel Limited, however, serves the public and meets local demands through a net work of stockyards at important centres like Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi, Jullundur, Kanpur, Madras, etc.

Wagon Repair Shop, Raipur

1073. **Shri Lakhan Lal Gupta :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees recruited for different posts in Wagon Repair Shop, Raipur (S. E. Railway) from Ist January, 1968 to 31st December, 1968 ; and

(b) the number of local persons amongst those newly recruited persons and their names ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No one has been recruited from the open market, as staff rendered surplus elsewhere are being absorbed in the Wagon Repair Shop, Raipur.

(b) Does not arise.

लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सरलीकरण

1074. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस देने की वर्तमान जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रमुख व्यापारियों और उद्योगपतियों ने सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं, जिससे वे गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित कर सकें और वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की जा सके ;

(ख) क्या उपरोक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). केन्द्रीय औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् की नई दिल्ली में 3 और 4 जनवरी, 1969 को हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने लाइसेंस प्राप्त करने की दुरूह प्रक्रिया का उल्लेख किया है। औद्योगिक लाइसेंसों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है और जहां सम्भव है लाइसेंसों के नियन्त्रण को

ढीला किया जा रहा है। ऐसे औद्योगिक एककों को (कुछ विशिष्ट उद्योगों में लगे हुए एककों को छोड़कर) जिनकी अचल आस्तियां 25 लाख रुपये तक हैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त करना, कुछ उद्योगों से लाइसेंस हटा लेना और औद्योगिक उपक्रमों को कुछ शर्तों के आधीन बिना लाइसेंस प्राप्त किए अपनी लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति प्रदान करना ये कुछ कदम हैं जो सरकार ने इस दिशा में उठाए हैं। जहां तक निर्मातोन्मुख उद्योगों की स्थापना का सम्बन्ध है सरकार उन पर विशेष ध्यान रखती है।

रूसी सहायता प्राप्त कारखानों के लिये रूसी कर्मचारी

1075. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी प्रतिनिधिमण्डल, जिसने हाल ही में रूसी सहायता प्राप्त कारखानों के कार्यकरण का सर्वेक्षण किया था, द्वारा बोकारो में 500 तकनीशनों और विशेषज्ञों के लगाने के क्या कारण हैं जबकि पहले ही रूस में प्रशिक्षण प्राप्त भारतीयों की संख्या पर्याप्त है ;

(ख) रूसियों के प्रस्तावों से कहां तक सहमति व्यक्त की गयी है ;

(ग) इस समय बोकारो में कितने रूसी कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) पदों का पूर्ण भारतीयकरण करने हेतु उन्हें वापस भेजने सम्बन्धी चरणवार कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रूसी प्रतिनिधिमण्डल ने बोकारो में रूसी तकनीशनों और विशेषज्ञों के लगाने के प्रश्न पर बातचीत नहीं की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 जनवरी, 1969 को बोकारो में 145 रूसी विशेषज्ञ कार्य कर रहे थे।

(घ) बोकारो स्टील लिमिटेड रूसी विशेषज्ञों को 3 मई, 1966 को सोवियत संगठन के साथ किये गये करार के अन्तर्गत 1 से लेकर 5 वर्ष तक की अवधियों के लिए रख रहे हैं। सोवियत विशेषज्ञ इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार टोलियों में आ रहे हैं और वे प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर रूस वापिस लौट जायेंगे।

संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

1076. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय देश में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों की संख्या 60 हो गई है ।

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष संकटग्रस्त कपड़ा मिलों की संख्या में वृद्धि होने के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या उच्च स्तर की कार्यकुशलता प्राप्त करने हेतु इन मिलों को खुली प्रतियोगिता की अनुमति देने की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार किया जायगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का उल्लेख उन मिलों के संबंध में है जो बंद पड़ी हैं । यदि ऐसा है, तो उत्तर 'हां' में है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 1968 के अन्त में बंद पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या 56 थी ।

(ख) उन कपड़ा मिलों की कठिनाइयां, जो अच्छी अवस्था में नहीं हैं, मुख्यतः उत्पादन कार्यकुशलता के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप हैं जिसके कारण ये हैं :—मशीनें पुराने ढर्रे की होना, ऋण-पूंजी अनुपात में पर्याप्त वृद्धि, धन की कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि और मांग में मंदी और साथ ही अनेक मामलों में कुप्रबन्ध भी ।

(ग) तथा (घ). सूती कपड़ा मिलों के विरुद्ध सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के उपबंध के अंतर्गत केवल तभी कार्यवाही करती है जबकि सरकार का यह मत होता है कि मिल का प्रबन्ध इस ढंग से हो रहा जो कि उद्योग अथवा सार्वजनिक हित के लिये अत्यन्त हानिकारक है ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये निर्माण सामग्री की पूर्ति

1077. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के लिये गत वर्ष दिये गये लगभग 1,60,000 टन की निर्माण सामग्री के आर्डरों को सन्तोषजनक ढंग से और कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से सप्लाई करने वाले किस्म तथा माल पहुंचाने सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केवल लागत के आधार पर टेन्डर चुनने के लिये इस नीति का पुनरीक्षण किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने गत वर्ष बोकारो इस्पात कारखाने के लिए 1,43,000 टन संरचनात्मक सामग्री के आर्डर दिये हैं। सामान्यतः कारखाने के निर्माण कार्यक्रम के अनुसार इनको पूरा किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के बोंडामुंडा स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान किराया

1078. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के बोंडामुंडा स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता हालांकि यह स्टेशन रूरकेला औद्योगिक बस्ती के बिल्कुल निकट है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस भत्ते के शीघ्र मंजूर करने के बारे में कार्यवाही की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). यदि अन्यथा अनुमत हो, तो बोंडामुंडा में काम करने वाले कर्मचारियों को 1-8-68 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मकान-किराया भत्ता उसी दर पर मंजूर किया गया है जिस दर पर रूरकेला के कर्मचारियों को दिया जाता है।

Raid on Ramnathpur Station (North-Eastern Railway)

1079. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that students had raided Ramnathpur Railway Station of the North-Eastern Railway in November, 1968 and as a result thereof Railways have suffered heavy loss ; and

(b) if so, the amount of loss suffered and the number of students arrested in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. On 30-11-1968 about 250—300 students attacked the station and damaged Railway property.

(b) Loss suffered estimated to be of Rs. 758/-. Four arrests, including two students, were made by Government Railway Police.

Export of Steel to U. S. A.

1080. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the quantity of Steel exported from India to U. S. A. from the 1st January, 1967 to-date ; and

(b) the amount of foreign exchange earned by Government as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) and (b). 1168.44 Tonnes of steel valued at Rs. 664,404 (f.o.b.) were exported to USA during the period from 1st January, 1967 to 30th November, 1968.

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1081. **Shri Hukam Chand Kachwai**: **Shri A. K. Gopalan**:
Shri Prakash Vir Shastri: **Shri P. Ramamurthi**:
Shri Jyotirmoy Basu: **Shri M. Mohammad Ismail**:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindu employees of Sector 2 site 5 of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi have been asked to vacate their quarters ;

(b) whether it is also a fact that Muslim employees are being allotted quarters there so that they may be able to live collectively with Muslim employees in one colony ;

(c) whether the employees belonging to the minority community are being settled collectively in a separate colony ;

(d) if so, the reasons therefor and whether Government do not consider this action unjustified ; and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) to (e). A statement was made on this question by Minister of Industrial Development and Company Affairs in the Rajya Sabha on the 2nd December, 1968 in response to a calling attention motion. This statement explains the position fully. A copy of the statement is attached.

Statement

Following the incidents of August, 1967, the Muslim employees of the Heavy Engineering Corporation, were moved into a building called "Artisan Hostel". They have continued to live in this building where the living space is limited and the conditions of living are unhealthy. A large number of them are huddled up in single rooms. Most of these employees have sent their families back to their homes. This concentration had created undesirable conditions for these industrial workers who were living in isolation. The Chairman, HEC, held a series of consultations with the Muslim workers with a view to persuading them to go back to their quarter. The Muslim employees represented that they were not feeling secure enough to return

to their quarters where they would have to leave their wives and children while working in the plants. In view of the limitation of space, it was not possible for the Muslim employees and their families to accommodate themselves in the Artisan Hostel.

2. Prior to communal riots, a large number of Muslim employees lived at a place known as Site V of Sector II. It was suggested by the Management of the HEC to move about 100 Muslim employees to this site as there were about 40 houses in this sector which were vacated by Muslims last year. If 50 to 60 more houses could be made available by the Hindu residents of this locality, the Management would arrange for the shifting of a group of Muslim employees to this locality. Accordingly, a general appeal was issued by the Management to all the residents of this locality suggesting, if they could vacate some houses purely on a voluntary basis, those who so offered would be given alternate accommodation. Whosoever liked to shift was requested to formally inform the Town Administration authorities, who would make all arrangements in this regard.

3. It is not correct to say that any intimidation or compulsion was thought of or practiced. Yet some politically motivated groups of people, entered the HEC campus, held daily meetings and spread distorted news that Hindus of Site V of Sector II were being forced to make room for Muslims. Obviously this was done to arouse communal feelings. The advantage of selecting this site was that 3 dozen houses occupied by Muslims are already vacant and if another 60 houses could be available, the problem would have been solved to a great extent. This scheme of dispersal was discussed and generally agreed to by the representatives of all trade unions including the Shramik Sangh.

4. While all this was going on peacefully, expectations were that some houses could be voluntarily vacated to accommodate Muslim co-workers and while more than three dozen persons had already volunteered in writing to vacate their houses in favour of Muslims in Site V, suddenly some politically motivated people inspired a movement of pressurisation and intimidation in Site V Camp in which some political parties and workers from the town came to hold meetings in order to prevent willing workers from moving from there, although Section 144 was promulgated. Acts of indiscipline by about 80 workers were also noticed that they absented themselves from the workshop without leave. When disciplinary action was indicated, many of them joined in this campaign of pressurisation. If the workers belonging to a particular party had not come from outside to interfere in the legitimate and peaceful movement of our willing workers within the campus, the scheme would have been successful. People from outside continue to visit HEC's colony, thereby creating an atmosphere of defiance of Section 144 and they also tried to prevent an official of the Corporation, from explaining the situation to those concerned.

5. While under the scheme of the management, the effort was to break up Muslim concentration and help them to properly integrate with the rest of the community, the politically motivated persons spread the rumour that the entire sector 2 was being forcibly vacated by the authorities and new construction added in order to resettle Muslim employees at one place and also provide them with facilities to contact Muslims of the larger Ranchi town. All that HEC Management desire is to house the Muslim employees in a number of areas in the township to facilitate integration on the one hand and a sense of security on the other.

6. Recently, the Corporation Management has also decided to undertake additional construction of residential accommodation in different sectors of the HEC township for rehousing the employees. A sum of about Rs. 20 lakhs is proposed to be spent in the current year on this account.

7. The impression sought to be created that the management was pressurising Hindu employees living in various residential areas to vacate their present accommodation in order to allot such vacated premises to the Muslim employees is baseless. The management have made a public statement to this effect. The effort being made is actually in the direction of breaking up the present Muslim concentration at one place in the Artisan Hostel and distrbuting their accommodation in a number of locations in the Township so as to avoid any concentration on the one hand and give them a sufficient sense of security on the other. Only persuation has been employed in these efforts and all this has been on the basis of an appeal to move on a purely voluntary basis.

विदेशों में भारतीय गुलाब के फूलों की मांग

1082. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गुलाब के फूलों की विदेशी मंडियों विशेषतः यूरोप और अमरीका में बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो इन मंडियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। किन्तु पश्चिम यूरोप में शीतकाल के मौसम में, जबकि उन देशों में तोड़े हुए फूलों की कमी होती है, निर्यात बाजार विकसित करने की संभाव्यता है ।

(ख) तोड़े हुए फूलों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एयर इण्डिया रियायती भाड़ा ले रहा है । राज्य व्यापार निगम भी भारतीय गुलाब के फूलों की विपणन संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये जांच कर रहा है और इस समय प्रयोगात्मक आधार पर थोड़ा-थोड़ा माल भेज रहा है ।

(ग) भारतीय गुलाब के फूलों के निर्यातों की संभाव्यता के बारे में इतनी शीघ्र कोई निश्चित राय बनाना संभव नहीं है ।

मुजफ्फरपुर के निकट गाड़ी दुर्घटना होते होते-बचना

1083. **श्री समर गुह :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री विश्वम्भरन : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जनवरी, 1969 को उत्तर-पूर्व रेलवे पर मुजफ्फरपुर से 50 किलोमीटर दूर चकिया और महरी स्टेशन के निकट एक गाड़ी की दुर्घटना होते-होते बच गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच की है ; और

(घ) समय पर पता लगाने के लिये रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कार देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 9-1-1969 को पूर्वोत्तर रेलवे के चकिया और मेहसी स्टेशनों के पास रेल दुर्घटना टल जाने का ऐसा कोई मामला नहीं हुआ ।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में अधिकारी

1084. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों के बारे में इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सरकारी क्षेत्र के उत्पादनरत उपक्रमों से प्राप्त अब तक की जानकारी (अंग्रेजी उत्तर के साथ) विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 129/69]

रेलवे स्लीपर्स

1085. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्लीपरों के लिये प्रतिवर्ष निलनबुर बन से कितनी मात्रा में लकड़ी प्राप्त की जाती है ;

(ख) इन स्लीपरों में से कितने कटे हुए स्लीपरों को प्रतिवर्ष पालघाट के करिओसोटिंग प्लांट में भेजा जाता है ;

(ग) प्रतिवर्ष करिओसोटिंग प्लांट पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या वर्ष 1967-68 में कोई हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केरल राज्य से लकड़ी के स्लीपरों की खरीद अधिकांशतः केरल राज्य वन विभाग के माध्यम से की जाती है ; कभी-कभी इस क्षेत्र के व्यापारियों से भी कुछ सामान लिया जाता है । इसलिए ठीक-ठीक यह बताना सम्भव नहीं है कि राज्य के किस-किस वन से कितने-कितने स्लीपर खरीदे गये ।

(ख) पालघाट में लोबान लगाने का रेलवे का कोई कारखाना नहीं है । सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय ओलावक्कोट के रेलवे शोधन कारखाने से है । फिर भी, जैसा कि ऊपर (क) के उत्तर में कहा गया है, यह बताना सम्भव नहीं कि निलनबुर बन की लकड़ियों से संभरणकर्ताओं ने कितने स्लीपर काटे और कितनों को ओलावक्कोट के रेलवे शोधन कारखाने में शोधन के लिये भेजा ।

(ग) ओलावक्कोट के रेलवे शोधन कारखाने द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1965-66—18,67,411 रुपये
1966-67—16,96,878 रुपये
1967-68—12,69,793 रुपये

(घ) इस रेलवे कारखाने में लाभ या हानि होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शोधित स्लीपरों का मूल्य कच्चे सामान और शोधन की लागत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्यकरण

1086. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री इ० के० नायनार :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य के नवीनतम मासिक परिणामों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) क्या सरकार को आशा है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड चालू वर्ष में अपने कार्य में सुधार दिखायेगी अथवा घाटे में ही चलती रहेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान संकेतों से ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी को चालू वित्त-वर्ष में भी लगभग 40 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा ।

मनमाड और ढोंढ के बीच मेल/एक्सप्रेस गाड़ी

1087. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनमाड और ढोंढ के बीच कोई मेल/एक्सप्रेस गाड़ी न चलने के कारण उत्तर और मध्य भारत से पूना और शोलापुर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या सरकार मनमाड-ढोंढ मार्ग पर कोई मेल/एक्सप्रेस गाड़ी चलायेगी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ग) और (घ). उत्तर या मध्य भारत के किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र और शोलापुर के बीच सीधी गाड़ी चलाने की कोई मांग नहीं की गयी है । नागपुर और पूना के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने की मांग की गई है, लेकिन वहां जितना यातायात होता है, उसे देखते हुए ऐसी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है । इस समय नागपुर और पूना के बीच मनमाड और ढोंढ के रास्ते तीसरे दर्जे का एक शयन यान चलाया जा रहा है, जो 321 डाउन सवारी गाड़ी/29 डाउन एक्सप्रेस और 30 अप एक्सप्रेस/402 अप सवारी गाड़ी में लगाया जाता है । 1-4-1969 से, इन गाड़ियों में पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला अतिरिक्त सीधा डिब्बा और चलाने का विचार है । इस अतिरिक्त डिब्बे से यात्रियों की आवश्यकताएं ठीक तरह से पूरी हो जायेंगी ।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र

1088. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री एम० नारायण रेड्डी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष श्री के० एम० जार्ज ने अपना त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके त्यागपत्र के क्या कारण हैं ;

(ग) कारखाने के निर्माण तथा सामान खरीदने और इससे सम्बन्धित नीतियों के बारे में दिल्ली से मंत्रालय के अधिकारी किस सीमा तक कार्य का पर्यवेक्षण करते तथा उसमें हस्तक्षेप करते हैं ; और

(घ) नये अध्यक्ष की नियुक्ति अथवा वर्तमान अध्यक्ष के जारी रहने के बारे में अन्तिम निर्णय क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). श्री के० एम० जार्ज ने, जो बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक थे, न कि अध्यक्ष। 9 फरवरी, 1969 को पंचवर्षीय इकरारनामे की अवधि की समाप्ति पर अपने पद का कार्यभार छोड़ा था।

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वतंत्र कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है और समवाय-अन्तर्नियम में उल्लिखित हद तक सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में है। अध्यक्ष के अतिरिक्त कम्पनी के संचालक-मण्डल में 2 वरिष्ठ सरकारी अफसर हैं। सरकार भी समय-समय पर कम्पनी के काम की समीक्षा करती है और ये समीक्षायें सदन में प्रस्तुत की जाती हैं। कारखाने के निर्माण-कार्य की प्रगति का भी पुनर्विलोकन किया जाता है और सरकार ऐसे अनुदेश भी देती है जिन्हें वह काम को कुशल ढंग से और समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक समझती है।

(घ) नये प्रबन्धक-निदेशक की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। कम्पनी के अध्यक्ष अपने पद पर पदारूढ़ हैं। उनके लिए कोई विशिष्ट पदावधि निर्धारित नहीं है।

Voltas Ltd.

1089. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the time when the Voltas Ltd., Bombay, had applied for licence and the time when this Company started functioning ;

(b) the terms and conditions which were laid down for running this company and the articles being produced by the company ; and

(c) the total production of this company since it was started ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Union Carbide India Ltd.

1090. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Union Carbide India Ltd., Calcutta applied for licence and since when it started functioning ;

(b) the terms and conditions prescribed for running this Company and the nature of articles manufactured by it ; and

(c) the quantum of articles manufactured by it since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

National India Traders (Pvt.) Ltd., Bombay

1091. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the National India Traders (Private) Ltd., Bombay, started functioning and the date on which it applied for licence ;

(b) the terms and conditions for running this company and the nature of articles being manufactured by it ; and

(c) its total production since it started functioning ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Glass Carboys and Pressed Wares Ltd., Bombay

1092. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) when the Glass Carboys and Pressed Wares Ltd., Bombay applied for licence and when it started functioning ;

(b) the terms and conditions of setting up of the said company and the commodities being produced by it ; and

(c) the total production of this company since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). An application was received on 20.3.1961 from M/s. Glass Carboys and Pressed Wares Ltd., Bombay for the grant of a licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 for establishing a new undertaking in the State of Maharashtra for the manufacture of Glass carboys and Glass Pressedwares of special type such as Glass Bricks and Tiles and Electrical Fittings. The party were granted an industrial licence in October, 1961 and they commenced production in February, 1966.

(c) This information is not available as the firm has not been submitting their production returns regularly. However, their production between February and October, 1966 was reported as 1,28,975 Nos. of glass Carboys of 25 litre capacity.

Central Distributors Ltd., Bombay

1093. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Central Distributors Ltd., Bombay applied for licence and the date on which it started functioning ;

(b) the terms and conditions laid down for running the said company and the nature of goods manufactured by the company ; and

(c) the quantum of goods manufactured by the said company since it started functioning ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग

1094. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1968 से अब तक पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में बिना टिकट यात्रा के परिणामस्वरूप सरकार को लगभग कितने रुपये की हानि हुई ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में बिना टिकट यात्रा के लिये कितने व्यक्तियों को कारावास का दण्ड दिया गया तथा जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-9-1968 से 31-1-1969 तक पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने के कारण गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 14,963 थी।

(ख) यह अनुमान नहीं लगाया गया है कि उपर्युक्त अवधि में बिना टिकट यात्रा करने के कारण सरकार को लगभग कितनी हानि हुई। फिर भी, कुछ समय पहले विशेष जांच के

आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बिना टिकट यात्रा करने के कारण सरकार को होने वाली अनुमानित हानि लगभग 3 करोड़ रुपये वार्षिक है।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर उपर्युक्त अवधि में बिना टिकट यात्रा के कारण कारावास को भेजे गये व्यक्तियों की संख्या 5,800 थी और जुर्माने के रूप में 3,20,708 रुपये की रकम वसूल की गयी थी।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों का अपने प्रस्थान से गन्तव्य स्थान पर विलम्ब से पहुंचना

1095. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों के अपने प्रस्थान स्थान से गन्तव्य स्थान तक विलम्ब से पहुंचने के बारे में शिकायतें निरन्तर बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यात्री गाड़ियों का अपने गन्तव्य स्थान पर समय पर न पहुंचना एक सामान्य बात हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई नये उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा०रामसुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे जोन की उपेक्षा

1096. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजनों, डिब्बों आदि की सप्लाई तथा महत्वपूर्ण मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की सुविधाओं के मामले में पूर्वोत्तर रेलवे सर्वाधिक उपेक्षित जोन बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात के क्या कारण हैं कि जब कि उत्तर-दक्षिण, पश्चिम तथा मध्य रेलवे ने अपनी मुख्य तथा अन्य लाइनों पर डाक, एक्सप्रेस तथा यात्री गाड़ियों में वृद्धि की है, पूर्वोत्तर रेलवे ने डाक, एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियां अभी तक नहीं बढ़ाई हैं और इस अपर्याप्त तथा बुरी व्यवस्था के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) यह ठीक नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। उदाहरण के लिए 1961-62 से लेकर 1968-69 (31 अक्तूबर, 1968 तक) की अवधि में तेज एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 72 नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं। यातायात में वृद्धि को सम्हालने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न खण्डों पर 39 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। मोटे तौर पर पूर्वोत्तर रेलवे पर जितना और जिस प्रकार का यातायात होता है उसकी जरूरतों को उस रेलवे पर इस समय चलने वाली यात्री गाड़ियां संतोषजनक ढंग से पूरा करती हैं।

गैर-सरकारी रेलवे व्यवस्था

1097. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिनियम की कौन-कौन धाराएं देश में गैर-सरकारी रेलवे व्यवस्था पर तो लागू होती हैं किन्तु सरकार द्वारा संचालित रेलवे पर लागू नहीं होती हैं ;

(ख) इस भेदभाव वाले कानून का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या देश में सभी रेलवे पर समान रूप से लागू करने के हेतु भारतीय रेलवे अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) धारा 49, 50, 51, 51 क और 87 से 98।

(ख) उपर्युक्त धाराएं जो गैर-सरकारी रेलों पर तो लागू होती हैं लेकिन सरकारी रेलों पर नहीं लागू होतीं ; भेदभाव परक नहीं है क्योंकि इनका एक मात्र उद्देश्य निजी कम्पनियों के कार्य-संचालन के नियमन से है।

(ग) और (घ). भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

सीमेंट का मूल्य

1098. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनियन्त्रण से अब तक सीमेंट के मूल्य कितनी बार बढ़ाने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) प्रत्येक बार सीमेंट की दर कितनी बढ़ाई गई है ; और

(ग) प्रत्येक बार मूल्य बढ़ाये जाने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सीमेंट से नियन्त्रण हटाने के बाद से सरकार ने 1-4-1966 से सीमेंट से रेल तक निःशुल्क गन्तव्य स्थान तक विक्रय मूल्य में 70 पैसे प्रति मी० टन तथा 1-4-1967 से 1.20 रु० प्रति मी० टन मूल्य बढ़ा देना स्वीकार कर लिया है। इन वृद्धियों के

लिए स्वीकृति सीमेंट के लाने ले जाने के भाड़े पर अधिक व्यय होने के कारण दी गई थी। इसके अतिरिक्त जूट की बोरियों के बाजार भावों तथा नई और पुरानी बोरियों के इस्तेमाल के अनुपात के आधार पर एक निर्धारित सूत्र के अनुसार सीमेंट के पैकिंग प्रभारों का हर तिमाही पुनरीक्षण किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टील के मजदूर संघ की मान्यता समाप्त करना

1099. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील के कर्मचारी संघ, दुर्गापुर को दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकतर मजदूरों तथा कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संघ की मान्यता समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन, दुर्गापुर इस्पात कारखाने की मान्यता प्राप्त यूनियन है। हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन को मान्यता प्रदान करने का मामला अप्रैल, 1966 में राज्य सरकार को, जो सदस्यता का सत्यापन करने और मान्यता प्रदान करने के बारे में सलाह देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, भेजा गया था। मामला अभी भी उनके विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

द्रुतगामी डीजल इंजनों की खरीद

1100. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैपिटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए खरीदे गये द्रुतगामी डीजल इन्जन का मूल्य क्या है ;

(ख) यह कहां से खरीदा गया है ;

(ग) क्या यह इंजन अप्रयुक्त पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). राजधानी एक्सप्रेस (कैपिटल एक्सप्रेस) को चलाने के लिए कोई नया डीजल इंजन नहीं खरीदा गया है। 1961-64 में अमरीका के मेसर्स जनरल मोटर्स द्वारा भारतीय रेलों को 72 डीजल इंजन सप्लाई किये गये थे, जिनमें से प्रत्येक की लागत 13,54,000 रुपये थी। इनमें से एक इंजन का उपयोग राजधानी एक्सप्रेस चलाने के लिये किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

चाय निगम

1101. **श्री भगवान दास :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन भेजा है कि अलाभप्रद चाय बागान के प्रबन्ध के लिए एक चाय निगम की स्थापना की जाए ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या लिखा गया है तथा क्या सरकार का विचार चाय निगम बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या चाय के बाजार में भेजने का काम भी यही निगम करेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). बन्द चाय बागानों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भांति एक चाय निगम की स्थापना करने का एक सुझाव आसाम सरकार ने दिया है। सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

औद्योगिक लाइसेंस देने के नियमों में संशोधन

1102. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यायार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों से सम्बन्धित नियमों में हाल ही में संशोधन किये हैं ;

(ख) क्या संशोधित नियमों के अनुसार कुछ प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए अब लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ;

(ग) क्या विदेशी पूंजी निवेषकों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं ;

(घ) उन संशोधित नियमों का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) उन नियमों में संशोधन करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अ अहमद) : (क) से (ङ). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों अनुसार अधिनियम की तालिका 1 में वर्णित उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। औद्योगि

विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और लघु तथा दरम्याने पैमाने के उद्योगों के लिए निर्धारित औपचारिकताओं को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिनियम की धारा 298 के अन्तर्गत 13 जनवरी, 1964 को एक अधिसूचना जारी कर कुछ विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर ऐसे उद्योगों को अधिनियम के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से छूट दे दी है जिनकी अचल आस्तियां अर्थात् भूमि, इमारत तथा मशीनों आदि का मूल्य 25 लाख रुपये से कम हो। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता त्वरित स्थापित करने के उद्देश्य से जिनमें आयातित पुर्जे और कच्चा माल आवश्यक नहीं है या ऐसे उद्योग जिनमें लघु उद्योगों की रुचि नहीं है, समय-समय पर अधिनियम के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से मुक्त करती रही है। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को और उदार करने के लिए सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों को अपनी लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत क्षमता के 25 प्रतिशत तक कुछ शर्तों के अधीन बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए उत्पादन में विविधता लाने की छूट दे दी है।

औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के नियम विदेशी विनियोजकों के लिए भी एक समान है और विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए इनमें संशोधन नहीं किये गये हैं।

भारतीय इंजीनियरी सामान का निर्यात

1103. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक प्रति वर्ष कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया तथा कितने मूल्य के सामान का आयात किया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में निर्यात किए गए सामान के मूल्य में से इंजीनियरी सामान का मूल्य कितना है ;

(ग) वर्ष 1968-69 में आयात तथा निर्यात का लक्ष्य क्या है ; और

(घ) वर्ष 1969-70 में निर्यात के लक्ष्य में से इंजीनियरी सामान कितना होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 130/69]

(ग) तथा (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना में आयात तथा निर्यात के मदवार लक्ष्य तैयार किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में कृषि उद्योग

1104. **श्री बदरुद्दुजा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951-52 से अब तक पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में स्थापित किये गये

कृषि उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1951-52 से अब तक इस राज्य के प्रत्येक जिले में वर्षवार कुल कितने मूल्य का सामान बनाया गया ; और

(ग) इन उद्योगों में रोजगार की कितनी अतिरिक्त सम्भावनायें हैं, तथा 1951-52 से अब तक प्रत्येक जिले में इन कृषि उद्योगों के कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Dohad-Khandwa Railway Line

1105. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposed Dohad-Khandwa railway line would facilitate the construction of Dam over Narmada river and even afterwards it would be very beneficial particularly for the development of that area ;

(b) whether this Ministry has formulated some scheme in this connection in consultation with the Planning Commission .

(c) whether there is coordination between his Ministry and the Planning Commission regarding the implementation of such schemes ;

(d) if so, whether a joint survey of the area has again been carried out ; and

(e) if not, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Neither the Planning Commission nor the Government of Madhya Pradesh have approached this Ministry for the construction of the Dohad-Khandwa railway line to facilitate building of a Dam over the river Narmada. Construction of this line may help in the development of the area, as generally, new lines provide additional transport facilities.

(b) No.

(c) Schemes for new lines are finalised only with the concurrence of the Planning Commission.

(d) No. It is not the general practice to undertake such joint surveys.

(e) Due to financial stringency it is not possible to consider the construction of this rail link at present.

Railway Line between Dohad and Khandwa

1106. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has considered the necessity of laying down a railway line between Dohed and Khandwa in view of the development of agriculture and industries and the increasing population there ;

(b) whether Government have felt the necessity of laying down this railway line for the welfare of Adivasis who constitute 40 per cent of the population in the four districts between Dohad and Khandwa ; and

(c) if not, the reasons therefor and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). No proposal for construction of a direct rail link between Khandwa and Dohad was considered in the past. With the object of providing rail transport facilities for the people of this rather backward area for its general development, engineering and traffic surveys for a metre gauge or a broad gauge rail link from Indore to Dohad were carried out during 1953—55. The survey reports revealed that the line would be financially unremunerative and hence the proposal for its construction was shelved. As the funds likely to be made available for new lines in the Fourth Five Year Plan may be extremely meagre and as no important developments appear to have taken place in the area likely to generate large volumes of traffic to sustain the proposed rail link so as to make it financially remunerative at the present day heavy costs, the proposal for a rail link in this area may have to wait for better times for consideration.

Khandwa-Dohad Railway Line

1107. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the cost which was estimated at the time of survey regarding the laying of railway line between Khandwa and Dohad and the present estimated cost ;

(b) whether according to his Ministry the position of the said area is still the same as was about 65 years ago;

(c) whether it is a fact that no attention has been paid by his Ministry to about one crore people living between Dohad and Khandwa who would derive benefit therefrom ; and

(d) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No surveys for a direct rail link between Dohad and Khandwa were ever carried out in the past.

(b) to (d). Taking into account the developments that might have taken place in the area and also to serve people of this backward area, engineering and traffic surveys for a metre gauge or a broad gauge rail link from Indore to Dohad were carried out in 1953-1955. The survey reports revealed that the line would be financially unremunerative and hence the proposal for its construction was shelved. As the funds likely to be made available for new lines in the Fourth Five Year Plan may be extremely meagre and as no important developments appear to have taken place in the area likely to generate large volumes of traffic to sustain the proposed rail link so as to make it financially remunerative at the present day heavy costs, the proposal for a rail link in this area may have to wait for better times for consideration.

Khandwa-Dohad Railway Line

1108. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the dates on which Khandwa-Dohad railway line connecting West and East Nimar district was first surveyed in early twentieth century ;

(b) the details of that survey and the reaction of the Ministry thereto; and

(c) the dates on which subsequent survey was conducted in that area and of that line alongwith details thereof?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No survey for a direct rail link between Dohad and Khandwa was ever carried out in the past.

(b) Does not arise.

(c) In this area, surveys were carried out only for Indore-Dohad proposed B. G./M.G. rail link in 1953. This link, if constructed would have connected Dohad and Khandwa as Indore and Khandwa are already connected by metre gauge. The cost of the Indore-Dohad rail link by a shorter route via Jhabua (175 Kms.) was then estimated to be Rs. 7.95 crores for B. G. and Rs. 5.95 crores for M. G. The cost of this rail link by a longer route via Jobat (223 Kms.) was Rs. 11.71 crores for B. G. and Rs. 8.86 crores for M. G. The line was found to be financially unremunerative both for B. G. and M. G. and the proposal for its construction was dropped.

The length of a direct rail link between Dohad and Khandwa would be about 285 Kms. and its present day cost of construction Rs. 28.5 crores for B. G. As there have been no important developments in the area likely to generate a large volume of traffic to sustain the proposed rail link, it is unlikely that this link would be financially viable and therefore its construetion may have to wait for better times for consideration.

Throwing out a Lady Passenger from Allahabad Passenger Train

1109. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri Shrinibas Mishra :
Shri Surendra Nath Dwivedy:
Shri K. Lakkappa :
Shri S. M. Krishna :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether his attention has been drawn to the news report that a gang of dacoits threw out a lady from a Second Class Compartment of the Allahabad Passenger running train between Ferozabad and Makhanpur Stations of the Northern Railway and they injured her husband and threw out their luggage also on the 13th January, 1969 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) A case has been registered by Government Railway Police, Tundla. Two of the accused have been arrested so far and are in jail. Efforts to arrest the other two absconding accused continue.

Instructions have been issued to tighten up security measures on trains in this area.

आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों की बिक्री के बारे में शिकायतें

1110. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसधारियों द्वारा आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों के दुरुपयोग तथा विक्रय के बारे में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 में ऐसे कितने मामले पकड़े गये तथा उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की बातों को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

शिवरावपेट स्टेशन पर यात्रियों से आय

1111. **श्री द० ब० राजू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे की भीमावरम गुडिवाडा रेलवे लाइन पर शिवरावपेट स्टेशन पर यात्रियों से प्रतिदिन औसतन कितनी आय होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों की धूप और वर्षा से रक्षा के लिए प्लेटफार्म पर 'शैल्टर' की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या सरकार यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए प्लेटफार्म पर शैल्टर की व्यवस्था करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) 1,554 रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छतों की व्यवस्था एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाती है । यदि धन उपलब्ध हुआ तो रेल प्रशासन भविष्य में निर्माण कार्यक्रम तैयार करते समय इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था करने के बारे में विचार करेगा ।

उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण

1112. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1867-68 में उड़ीसा में कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर किए गये हैं ;

(ग) क्या 1968-69 और 1969-70 के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और किन-किन जिलों के सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी, हां। 1967-68 के क्षेत्रीय कार्य-मौसम के दौरान, सैथला, बोलनगिर जिले और सुन्दरगढ़ जिले में सरगिपल्ली में आधार धातु खनिजायन के लिये, मयूरभंज जिले में ऐस्बेस्टस के लिए, बोलनगिर जिले के उप-प्रभाग तितलागढ़ में ग्रैफाइट के लिए, कोरापुट जिले में सोने, चीनी-मिट्टी, क्रोमाइट और कांच-रेत के लिए सर्वेक्षण किये गये थे। सुन्दरगढ़ जिले में गंगपुर कर्तन क्षेत्र में बहु-धातु खनिजायन के लिए भी भूरासायनिक सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) 1968-69 के क्षेत्रीय कार्य-मौसम में किये जा रहे खनिज अन्वेषणों में सुन्दरगढ़ जिले में सरगिपप्ली में और मयूरभंज-कर्तन क्षेत्र में आधार धातु अयस्कों के लिए कटक जिले में सूरआबिल और मयूरभंज जिले में सिमलिपल बेसिन में निकल अयस्कों के लिये, बोनाई-क्योन्झार पट्टी में मैंगनीज अयस्कों के लिये, बोलनगिर—पटना जिले में ग्रैफाइट के लिये और कोरापुत जिले में सोने के लिए अन्वेषण सम्मिलित हैं। मुख्य अन्वेषणों के 1969-70 के क्षेत्रीय कार्य-मौसम में जारी रहने की आशा है। 1969-70 के दौरान किये जाने वाले कार्यक्रम के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

सूरत और भड़ौंच के बीच शटल गाड़ी चलाने की मांग

1113. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-भड़ौंच यात्री संस्था द्वारा सूरत और भड़ौंच के बीच शटल गाड़ी चलाये जाने की काफी समय से मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकारियों ने इस शटल सेवा को आरम्भ करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के कारण।

स्टेशनों का वर्गीकरण

1114. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा), अजमेर ने लेखा चल निरीक्षकों को किसी स्टेशन का 'ख' श्रेणी में वर्गीकरण न करने के निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पश्चिम रेलवे के इन स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन्हें 1969 में 'ख' श्रेणी में रखा गया ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं।

रेलवे में वाणिज्यिक निरीक्षक

1115. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री 16 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त रेलवे जोनों में वाणिज्यिक निरीक्षकों के 75 प्रतिशत रिक्त स्थान पर उचित वाणिज्यिक निरीक्षकों को नियुक्त किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण-पूर्व और पूर्व रेलों में क्लेम्स ट्रेसर, सहायक वाणिज्यिक निरीक्षक तथा अन्य निरीक्षकों के पदों पर क्लर्कों को भी नियुक्त किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यिक श्रेणी में कार्यालय क्लर्कों द्वारा उनके प्राप्य हकों को समाप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस बारे में सरकार अखिल भारतीय वाणिज्यिक लिपिक संघ के अभ्यावेदन पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) बहुत-सी रेलों पर वाणिज्यिक निरीक्षकों के पद वाणिज्यिक क्लर्कों और कुछ अन्य वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति की सरणि में आते हैं।

(ख) पूर्व रेलवे पर कार्यालय क्लर्क एक विशिष्ट कोटे के लिये क्लेम ट्रेसरों के रूप में और उसके बाद सहायक दावा निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति पाने के हकदार हैं। इस प्रकार कार्यालय क्लर्क भी सहायक दर निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति पाने के हकदार हैं। यह संवर्ग बहुत छोटा है। वाणिज्यिक क्लर्कों समेत ये कर्मचारी इसके आगे नियमित वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति पाने के हकदार हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे पर और उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर भी कार्यालय क्लर्कों को क्लेम ट्रेसरों और बाद में अन्य कर्मचारियों के साथ वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत करने के लिये ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

(ग) और (घ). वाणिज्यिक विभाग के कार्यालय क्लर्कों को एक सीमित सीमा में निरीक्षक संवर्ग के पदों पर लगाना उपर्युक्त रेलवे पर पदोन्नति की पुरानी सरणि रही है और इसलिये इसकी वजह से वाणिज्यिक क्लर्कों की पदोन्नति को सरणि का अधिक्रमण नहीं होता।

यूगोस्लाविया से व्यापार संतुलन

1116. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष के आरम्भ में तथा इस समय रुपयों में यूगोस्लाविया को हमें कितना भुगतान करना है ;

(ख) इसके विरुद्ध यूगोस्लाविया को भारतीय निर्यात में वृद्धि करने के बारे में क्या विशेष कार्यवाही की गई और किन-किन नई वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(ग) दिसम्बर, 1968 को समाप्त हुए समझौते को बनाये रखते हुए उस देश से क्या कोई नया समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो नये करार का ब्योरा क्या है और भारतीय निर्यात के दृष्टिकोण से उस देश को क्या अतिरिक्त लाभ होगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सामान्य बैंक कार्यप्रणाली के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक में विदेशी बैंकों के लेखाओं के ब्योरे प्रकट करना संभव नहीं है।

(ख) यूगोस्लाविया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में विशाल पैमाने पर भाग लेने के अतिरिक्त, सरकार ने व्यवसाय प्रतिनिधि मंडलों तथा व्यवसायियों को यूगोस्लाविया की पसंद की नई तथा विशेषत: अपरम्परागत मदों का पता लगाने के लिये यूगोस्लाविया की यात्रा करने के लिये प्रोत्साहन दिया है। निर्यात की नई मदों की सूची में वाणिज्यिक गाड़ियां जिनमें जीपें, मोटरों के फालतू पुर्जे तथा सहसाधन शामिल हैं, बैटरियां, वेल्लित इस्पात उत्पाद तार रस्से तथा तार उत्पाद, लिनोलियम रसायन तथा औषधीय उत्पाद आदि शामिल हैं।

(ग) तथा (घ). 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले करार के नवीकरण के लिये बातचीत पूरी होने की प्रतीक्षा में करार की अवधि अस्थायी तौर पर 31 मार्च, 1969 तक बढ़ा दी गई है। इस समय यूगोस्लाविया के एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ व्यापार वार्ता चल रही है।

देश में निर्मित मशीनों का प्रयोग करने वालों को प्रोत्साहन

1117. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित मशीनों और उपकरणों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को अधिक प्रोत्साहन देने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सारा मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

अलौह धातु की मांग

1118. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **इस्तपात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में विभिन्न अलौह धातुओं की अनुमानत: कितनी मांग होगी ;

(ख) इनमें से कितनी मांग देश में किये गये उत्पादन और कितनी मांग आयात द्वारा पूरी की जायेगी ;

(ग) आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) विभिन्न धातुओं का देश में उत्पादन करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये विकासात्मक योजनाओं के प्रतिपादन करने के सम्बन्ध में स्थापित अलौह-धातुओं विषयक आयोजना दल के द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर अनुमानित, आगामी पांच वर्षों के दौरान अलौह-धातुओं की मांग, 1969-70 और 1973-74

वर्षों के दौरान संभावित स्वदेशी उत्पादन और न्यूनता आदि नीचे सूचित की गई है :

धातु	अनुमानित मांग					सम्भावित स्वदेशी उत्पादन और न्यूनता			
	1969-70	70-71	71-72	72-73	73-74	1969-70		1973-74	
						उत्पादन	न्यूनता	उत्पादन	न्यूनता
	(हजार मैट्रिक टनों में)								
एल्यूमिनियम	184	221	254	280	315	142	42.0	पूरी आवश्यकता	कुछ नहीं
तांबा	84.9	93.4	102.8	113.0	124.3	9.6	75.3	50	74.3
जस्ता	96.8	106.5	117.1	128.9	142	38.0	58.8	76	66.0
सीसा	66.6	73.2	80.5	88.6	97.4	2.5	64.1	3.5	93.9
टिन	5.5	6.5	7.0	7.5	8.0	कुछ नहीं	5.5	कुछ नहीं	8.0
निकल	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	कुछ नहीं	3.5	कुछ नहीं	6.0
एन्टीमोनी	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.0	—	1.5	कुछ नहीं

टिप्पणी 1—एल्यूमिनियम की मांग के अनुमानों में निर्यात के लिये व्यवस्था भी सम्मिलित है।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान एल्यूमिनियम की मांग का, योजना की अवधि के दौरान बिजली विकास पर संभावित परिव्यय को विचार रखते हुए, और आगे पुनरावलोकन किया जा रहा है।

3—एन्टीमोनी का उत्पादन आयातित अयस्कों पर आधारित है।

(2) तथापि, विभिन्न अलौह-धातुओं का वास्तविक आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और कार्यान्वित की जा रही अतिरिक्त योजनाओं द्वारा की गई प्रगति पर निर्भर होगा। और भी, इन पर लगने वाली विदेशी मुद्रा की राशि, विभिन्न धातुओं के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों पर, जो समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं, निर्भर होगी।

(3) देश में ही विभिन्न अलौह-धातुओं के उत्पादन करने के लिये किये जा रहे प्रयास और अब तक प्राप्त की गई प्रगति संक्षेप में नीचे दी गई है :

(1) **एल्यूमिनियम :** एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन के लिये वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 117,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिये अनुज्ञप्त/अनुमोदित अतिरिक्त योजनाएं 356,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता की हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र में 150,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता भी सम्मिलित है जिसके चौथी योजना के दौरान और पांचवी योजना की प्रारम्भिक अवधि में प्राप्त किये जाने की संभावना है।

(2) **तांबा :** देश में इस समय केवल एक ही तांबा प्रद्रावक है (गैर-सरकारी क्षेत्र में), इस एकक को 16,500 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तांबे का उत्पादन करने के लिये एक स्फुरण-प्रद्रावक की स्थापना करने के लिये लाइसेंस दिया गया है, जिसके 1970 तक पूरे किये जाने की संभावना है। 31,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का एक तांबा प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी (राजस्थान) में भी स्थापित किया जा रहा है जिसके 1971 में प्रारम्भिक उत्पादन शुरू करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बिहार में राखा क्षेत्र के और आंध्र प्रदेश में अग्निगुन्डला क्षेत्र के तांबा निक्षेपों के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

(3) **जस्ता :** सरकारी क्षेत्र में जावर (राजस्थान) के सीसा जस्ता निक्षेपों पर आधारित एक नया जस्ता प्रद्रावक जनवरी 1968 में चालू किया गया था और इसका उत्पादन 18,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की निर्धारित क्षमता से बढ़ गया है। 20,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता के (आयातित अयस्कों/संकेन्द्रकों पर आधारित) एक अन्य जस्ता प्रद्रावक को (गैर-सरकारी क्षेत्र में) 1967 के प्रारम्भ में चालू किया गया था। आंरभिक कठिनाइयों के कारण से, यह प्रद्रावक अभी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर सका है।

सरकारी क्षेत्र के जस्ता प्रद्रावक ने अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिये लगभग 37.82 करोड़ रुपये (मिल्लिंग संयंत्रों की लागत मिला कर) की अनुमानित लागत पर जावर क्षेत्र में अयस्क की अतिरिक्त उपलभ्य राशियां सिद्ध करने के लिये एक योजना तैयार की है। अयस्क उत्पादन में इस वृद्धि के 1970 से यथार्थ रूप लेने की संभावना है और इसके पश्चात् प्रद्रावक का विस्तार किया जायेगा, जिसके लिये उपयुक्त प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र के जस्ता प्रद्रावक के विस्तार के लिये प्राप्त प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

(4) **सीसा** : इस समय देश में, जावर निक्षेपों पर अधारित, केवल एक सीसा प्रद्रावक है। यद्यपि इस प्रद्रावक की क्षमता लगभग 5,400 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है, परन्तु जावर अयस्क निक्षेपों में घटती जा रही सीसा मात्रा के कारण से उत्पादन केवल 2500 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष ही हुआ है।

(5) **टिन और निकल** : देश में ज्ञातव्य वाणिज्यिक उत्पादन योग्य निक्षेपों के अभाव में इस समय देश में इन धातुओं का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता है।

(6) **ऐंटिमोनी** : देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस समय आयातित अयस्कों से ऐंटिमोनी उत्पादन करने वाला केवल एक एकक, गैर-सरकारी क्षेत्र में है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 1973-74 तक इस संयंत्र का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

(4) **अलौह-धातुओं की खोज :**

अलौह-धातुओं के महत्व की दृष्टि से, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने देश में विस्तृत समन्वेषण का एक तीव्र कार्यक्रम हाथ में लिया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा देश के कई भागों में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, गढ़े और खाइयां खोदने, भूरासायनिक और भूभौतिक सर्वेक्षणों, व्यधन, समन्वेषी खनन आदि के द्वारा अब तक किये गये अन्वेषणों से आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तांबे, सीसे और जस्ते की कई महत्वपूर्ण संभावनाओं का पता लगाया है। इन अयस्कों की छोटी मात्रा की उपलभ्य राशियों के मद्रास और मैसूर में भी पाये जाने के संकेत मिले हैं।

और आगे, "आपरेशन हार्ड राँक" द्वारा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हवाई सर्वेक्षण भी किये गये हैं। इन हवाई भूभौतिक सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, लगभग 6,000 संख्या के कुल विषमता स्थलों का पता लगाया गया है।

Production of Steel

1119. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of steel produced in the country during the current year and each of the preceding two years separately ; and

(b) the quantity of steel exported and utilized within the country separately and the quantity of remaining stock of steel ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Quantity of Ingot Steel and Saleable Steel produced in the country during the last three years are given below :

			'In thousand Tonnes'
	1968-69 (Up to Dec. '68)	**1967-68**	**1966-67**
Steel Ingots (Not for sale)	4,666	6,171	6,462
Saleable Steel	3,382	4,437	4,752

(b) The quantity of Steel exported, consumed internally and stocks are given below :

			'In thousand Tonnes'
	1968-69 (Up to Dec. '68)	**1967-68**	**1966-67**
Export of Steel (Excluding Export of Pig Iron).	531	666	2,908
Steel consumed internally.	2,751	3,837	4,461
Stock of Saleable Steel on the last day of the month.	213	Not available	N. A.

आमों का निर्यात

1120 **श्री को० सूर्य नारायण :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में 30 जून, 1968 तक विभिन्न देशों को कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत की आमों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ख) विभिन्न राज्यों से किन-किन किस्मों के आमों का निर्यात किया गया ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 131/69]**

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आमों के निर्यात के आंकड़े किस्मवार/राज्यवार नहीं रखे जाते ।

Deposits of Rock Phosphate in Rajasthan

1121. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are importing Rock Phosphate from foreign countries for

manufacturing fertilizers despite the fact that large deposits of Rock Phosphate are found in Udaipur area, Rajasthan ; and

(b) whether Government have under consideration any scheme for the development of these Mines in Udaipur area with a view to stop import of Rock Phosphate ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The entire requirements of rock phosphate are being imported at present as the deposits located in the country are still in the exploratory stage.

(b) Yes, Sir.

Manufacture of Remington Rand Typewriters

1122. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Company manufacturing Remington Rand Typewriters is not being allowed to instal machine plant for manufacturing small typewriters ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that M/s. J. K. Business Machines Ltd., is being permitted to manufacture such typewriter machines exclusively ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). M/s. Remington Rand of India submitted an application for licence under the Industries (D. and R.) Act, 1951, for the manufacture of Portable Typewriters for a capacity of 12,000 number per annum. The application of the Company is under consideration of Government.

(c) No, Sir ; Not exclusively.

(d) Does not arise.

Western Railway Passenger Train No. 161

1123. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the Capitals of newly formed States and new Districts, the Ministry of Railways propose to take a policy decision and get it implemented immediately that during the day at least one train should leave the District Headquarters and arrive at the State Capital at 10 O'clock in the morning and carry back the passengers to the district headquarters in the evening so that the passengers have not to stay for an additional day ; and

(b) whether, with a view to providing such facility, it is proposed to make the time table of the fast passenger train No. 161 of the Western Railway in such a way that this train carrying the passengers of Alwar city should leave Rewari and arrive at Jaipur before 12 O'clock in the morning and leave for the district headquarters at 5 O'clock in the evening ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is not operationally feasible to link every District Headquarters with the State Capital in the manner suggested. However, the needs of passengers wishing to travel to and from State Capitals are taken into

account when framing the Time Table and the facility referrred to has been provided for a large number of district towns.

(b) It is not feasible to extend 161 Up/162 Dn. Passenger trains to and from Jaipur and to reschedule them as suggested, as any major change in the present timings of these trains will seriously inconvenience passengers originating on the Rewari-Alwar section and proceeding to Alwar to attend courts, government offices, etc. The present connections between 161 Up and 4 BRR Ratangarh-Rewari Passenger at Rewari will also be missed.

Railway Bridge at Level Crossing in Alwar

1124. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a scheme for constructing an under or over-bridge at the level crossing in Alwar city, Rajasthan, which lies on National Highway No. 8 and is the District Headquarters and centre for tourists, has been under the consideration of Railways for several years ; and

(b) the reasons for slackness in the construction of work despite a letter by the Chief Minister of Rajasthan ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Under the extant rules the cost of replacement of any level crossing by road over/under bridge is to be shared between the Railway and the Road authority. Broadly, under the rules now in force 50% of the cost of road over/under bridge for a 24 ft. wide roadway and its approaches (excluding cost of land) is borne by the Railways and the balance 50% as well as the cost of acquisition of any land required for approaches is borne by the road authority. A proposal for a road overbridge in replacement of the existing level crossing on the National Highway at Alwar was made by the Government of Rajasthan in January, 1962, but the scheme could not be progressed due to the State Government not having given necessary priority and other relevant technical details. The Alwar Municipality to whom the matter was referred by the Railway in June, 1968, also expressed their inability to bear their share of the cost. The Government of Rajasthan has however again indicated in December, 1968, their willingness to take up the proposal during the Fourth Five Year Plan. As soon as the State Government/ Municipality agree to bear their share of cost, the Railways on their part would take suitable action for the replacement of the level crossing by a road overbridge and to carry out their share of work promptly.

Utilisation of Deposits of Gypsum in Rajasthan

1125. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Gypsum deposits in Rajasthan are being properly utilised ;

(b) whether Government propose to set up any factory in Rajasthan for proper utilisation of this mineral wealth ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तेलगांना के आन्दोलनकर्ताओं द्वारा रेलवे सम्पत्ति को क्षति

1126. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अदिचन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेलंगाना निवासियों के लिये अच्छी रेलवे सेवा सम्बन्धी सुविधा दिये जाने के बारे में दक्षिण में किये गये प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को क्षति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे को कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 45,410 रुपये ।

मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी

1127. **श्री रवि राय :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता लगातार ये मांग कर रही है कि यदि आवश्यक हो तो खुले बाजार में इस कम्पनी के शेयरों को खरीद कर ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर एलन यूनिट को तुरन्त हाथ में ले लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी वित्तीय संस्थाओं समेत ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के शेयर पर्याप्त संख्या में हैं क्या सरकारी ऋण को इक्विटी शेयरों में बदला जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कूपर एलन तथा नार्थ-वेस्ट टेनरी नामक एककों का जिन्हें सरकार खरीद के आधार पर ले रही है, प्रबन्ध करने के लिए "टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०" के नाम से एक पूर्णतया सरकारी कम्पनी बनाई जा रही है ।

खेत्री ताम्बा उद्योग समूह

1128. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे लाइन और बिजली की सप्लाई कम होने के कारण खेत्री

ताम्बा उद्योग समूह में काम की गति धीमी है; और

(ख) इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी, हां। प्रगति पर बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और रेल-संबंधों के अभाव के कारण से दुष्प्रभाव पड़ा है।

(ख) खेतड़ी संयंत्र के स्थान को निकटतम रेल-संबंधों के साथ जोड़ने का मामला रेलवे बोर्ड के साथ उठाया गया है और उनके विचाराधीन है।

खेतड़ी तांबा प्रायोजना को पर्याप्त बिजली सप्लाई करने के मामले का राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के साथ जोरदार अनुसरण किया जा रहा है। अब ऐसी संभावना है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल खेतड़ी तांबा प्रायोजना को मार्च, 1969 के पहले सप्ताह तक अपने खेतड़ी स्थित 220 के० वी० के उप-बिजलीघर से, जिसका निर्माण-कार्य प्रगति पर है, अपेक्षित मात्रा में बिजली सप्लाई करने के योग्य हो जायेगा।

मैसूर में लाइसेंस जारी किये जाने के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1129. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में उद्योगों को आरम्भ करने के लिये लाइसेंस दिये जाने के बारे में कितने आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) वे आवेदन-पत्र कितने समय से विचाराधीन हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस दिये जाने के लिये 31 दिसम्बर, 1968 तक प्राप्त 309 आवेदन-पत्रों में से 1 फरवरी, 1969 को 67 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे।

(ख) 35 आवेदन-पत्र 1 वर्ष से अधिक, 14 छः महीनों से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम और 18 आवेदन-पत्र छः महीनों से कम समय से विचाराधीन हैं

भूमिगत रेलवे

1130. **श्रीमती तारा सप्र :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
डा० रानेन सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों में यातायात के बढ़ जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में बम्बई तथा

कलकत्ते में भूमिगत रेलवे चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगर परिवहन दल महानगरों में अति द्रुत परिवहन प्रणालियों के लिये प्रारम्भिक अध्ययन कर रहा है। इस सम्बन्ध में भी सहमति व्यक्त की गयी है कि इस मामले में रेलों पर आने वाले वित्तीय और परिचालनिक उत्तरदायित्व की जांच करने के बाद रेलें कलकत्ता में अति द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन करेंगी ।

(ख) व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन पूरे होने पर ही लागत का पता चल सकेगा ।

Cutting of Rail Wire between Agra and Dholpur

1131. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received a report about the cutting of rail-wire between Agra and Dholpur on the 18th January, 1969;

(b) if so, whether any arrest has been made in this connection and if not, the action being taken in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) On 18-1-1969 Post and Telegraph wires and not railway wires were found cut in between Mania and Jajau and also in between Jajau and Bhandai Stations on Dholpur-Agra section.

(b) No arrests have been made so far. Investigations by the Police are in progress.

Damage to Railway Property

1132. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent of damage caused to the Railway property during the last two months, statewise ;

(b) the number of persons arrested and awarded punishment in this connection ; and

(c) whether these persons had the support of some political parties also and if so, the names of those political parties?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The extent of damage caused to the Railway property during the last two months (December, 68 and January, 69) Statewise is as under :—

	Rupees
Andhra Pradesh	44,149
Bihar	7,900
Gujarat	621
Haryana	50
Punjab	460
Tamil Nadu	19,423
Uttar Pradesh	1,493
Total	74,096

(b) In all 76 persons were arrested out of which 4 were convicted and cases of others are still under police investigation or under trial.

(c) No political party has so far been found to be involved.

Express Train between Jhansi and Varanasi

1133. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a proposal to introduce an Express train from Jhansi to Varanasi (Via Manikpur-Allahabad) ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ; and

(c) the time by which the said train would be introduced ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). There has been no proposal for running an Express train between Jhansi and Varanasi. However, a proposal for the introduction of a fast train between Jhansi and Allahabad was examined. It was found that while on the one hand there was not adequate traffic justification, on the other hand, the introduction of such train was also not feasible due to insufficient line capacity on the Manikpur-Allahabad Section.

बम्बई-इलाहाबाद रेल मार्ग पर डीजल इंजन चलाना

1134. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों की प्रायः सभी मुख्य लाइनों पर डाक तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डीजल इंजिनों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु मध्य रेलवे के बम्बई-इलाहाबाद मार्ग की इस दृष्टि से सर्वथा उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस लाइन पर भी डीजल इंजिन चलाये जायेंगे और यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) से (ग). फिलहाल भारतीय रेलों पर कुल मिलाकर डीजल इंजनों की कमी है और संतृप्त खण्डों पर आवश्यक माल यातायात को ढोने के लिये इनकी बहुत अधिक जरूरत है। इसलिए सवारी गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाने का काम एक चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर ही शुरू किया जा सकता है। जब और जैसे ही डीजल इंजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होने लगेंगे बम्बई-इलाहाबाद मार्ग पर डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाने के प्रश्न पर अन्य खण्डों से होने वाली इस प्रकार की अन्य मांगों के साथ यथावत विचार किया जायेगा।

जबलपुर-इटारसी सेक्शन की यात्री रेल-गाड़ियों के संचलन समय में वृद्धि

1135. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे के जबलपुर-इटारसी सेक्शन में दोहरी रेलवे लाइन बिछ जाने तथा तेज गति वाले इंजिन

चलाये जाने पर भी यात्री गाड़ियों के संचलन समय में 1955-56 तथा उससे पहले समय की अपेक्षा में अधिक वृद्धि हो जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : 1960—65 के वर्षों में जबलपुर-इटारसी खंड पर चलने वाली यात्री गाड़ियों के चालन समय को इसलिये बढ़ाना पड़ा क्योंकि इस मार्ग पर 5 अतिरिक्त स्टेशन खोले गये तथा दोहरी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में निर्माण-कार्य करना पड़ा ।

1965 के बाद, इस खण्ड की गाड़ियों के चालन समय में उत्तरोत्तर कमी होती रही है तथा अगले वर्ष दोहरी लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाने पर चालन समय को और अधिक कम करने के प्रयास किये जायेंगे ।

Phosphate Reserves

1136. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Phosphate reserves have been found at some places in the country ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to tap them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) Yes, Sir.

(b) Detailed explorations in the promising blocks are being carried out by the Geological Survey of India for the development of the deposits.

सरकारी उद्यमों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश

1137. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन चल रहे सरकारी उपक्रमों को करों के भुगतान के बाद कितनी लाभ अथवा कितनी हानि हुई है;

(ख) वेंकटरामन समिति द्वारा बिजली के लिये पूंजी निवेश पर कम से कम 11 प्रतिशत लाभ निश्चित किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुये क्या कारण है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिये जनता में शेयर नहीं बेचती जिससे बुद्धिमान पूंजी निदेशकों का सहयोग प्राप्त किया जा सके;

(ग) उन पूंजी निदेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर दिये जाने वाला न्यूनतम लाभ देने में क्या आपत्ति है जबकि अन्यथा ऋण प्राप्त करने पर भी हमें उतना ही ब्याज देना पड़ता है; और

(घ) विदेशी सहयोगियों को उनकी विदेशी पूंजी के बराबर पूर्व में हिस्सा देने की पेशकश न की जाने के क्या कारण हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे फालतू पुर्जों की बिक्री की अपेक्षा उद्यम से प्राप्त होने वाले लाभ में अधिक रुचि ले सकें ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लन्दन में मैसूर सरकार का व्यापार अभिकर्त्ता

1138. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि क्या लन्दन में चन्दन की लकड़ी के सम्बन्ध में मैसूर सरकार के स्वतन्त्र अभिकर्ता द्वारा किये जाने वाले कार्य को सरकार के वर्तमान कर्मचारी कर सकते हैं; और

(ख) क्या इस पद की आवश्यकता के बारे में वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के साथ परामर्श किया गया था क्योंकि इसमें वाणिज्य और विदेशी मुद्रा का मामला आता है और यदि नहीं तो क्या सरकार अब इस पर विचार करेगी ।

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). इस मामले की सरकार के सभी सम्बन्धित अंगों द्वारा व्यापक जांच की जा रही है ।

मणिपुर में उद्योग

1139. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में बड़े और छोटे उद्योग कितने-कितने स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त छोटे तथा बड़े उद्योगों के लिए अलग-अलग तथा उद्योगवार कितना धन नियत किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख). राज्यों तथा मणिपुर समेत संघ राज्य क्षेत्रों के चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन हैं । मणिपुर में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक एककों तथा उनके लिए आवंटित वित्त सम्बन्धी ब्यौरे योजना पर अन्तिम निर्णय हो जाने के पश्चात् उपलब्ध होंगे ।

Development of Undeveloped and Backward Areas

1140. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to develop undeveloped and backward areas ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of the areas where that scheme is proposed to be implemented ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The whole matter regarding development of undeveloped and backward areas including regional dispersal of industries is, at present, under the consideration of the Government.

बल्गारिया के साथ व्यापार

1141. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री अदिचन :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्गारिया के प्रधान मंत्री ने अपने हाल के दौरे में भारत तथा बल्गारिया के बीच व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिये बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों को सुधारने में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). भारत तथा बल्गारिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार की संभाव्यताओं पर बल्गारिया के प्रधान मंत्री के साथ सामान्य रूप में बातचीत हुई । वर्ष 1968 में पारस्परिक व्यापार में उत्साहप्रद वृद्धि तथा विविधीकरण पर दोनों ओर से सन्तोष प्रकट किया गया । और आगामी वर्षों में अतिरिक्त वृद्धि की संभाव्यताओं पर ध्यान दिया गया । औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया ।

सीमेंट का निर्यात

1142. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से सीमेंट के निर्यात में वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 की तुलना में वर्ष 1968 में भारत ने विभिन्न देशों को

कितना-कितना सीमेंट भेजा और इन वर्षों में निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गयी; और

(ग) यदि नहीं, तो सीमेंट का निर्यात बढ़ाने के लिये यदि सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु० में

क्रमांक	देश का नाम	वर्ष 1967		1968	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	नेपाल	31432	37.21	48953	59.01
2.	कतार तथा ट्रूश्यिल ओमान	215	0.33	50	0.08
3.	सऊदी अरब	—	—	6125	8.70
4.	मस्कत	115	0.18	5535	7.59
5.	श्रीलंका	—	—	75405	69.43
6.	कुवैत	—	—	19275	24.53
7.	कीनिया	50	0.14	35	0.11
8.	तंजानिया	10	0.03	60	0.22
9.	अन्य	—	—	496	0.46
	योग ...	31822	37.89	155934	170.13

सरकारी क्षेत्र में कागज निगम की स्थापना

1143. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री सीताराम केसरी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कागज तथा अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में एक कागज निगम की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है इसलिए इसका ब्योरा दिया जाना सम्भव नहीं है ।

अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा

1144. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिहार में अशोक पेपर मिल्स, दरभंगा का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मिल को निर्माण अवस्था में ही छोड़ दिया गया है । आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेना उचित नहीं समझती ।

दक्षिण रेलवे में वाणिज्यिक क्लर्क

1145. **श्री पीलू मोदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में डिवीजनवार 1 जनवरी, 1962 और 1 नवम्बर, 1968 को वाणिज्यिक क्लर्क कितने थे;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में यातायात और वाणिज्यिक विभागों में केवल वाणिज्यिक क्लर्कों की श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कम की गई है जो सिद्धातों के प्रतिकूल हैं, जबकि उपरोक्त अवधि में रेलवे के यातायात में और उसकी आय में सतत् वृद्धि हुई है; और

(ग) वर्ष 1961 से 1968 तक की अवधि में सहायक स्टेशन मास्टरों (गार्डों) टिकट-परीक्षकों के संवर्गों में कम किये गये कर्मचारियों का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सहायक स्टेशन मास्टर	—	205
गार्ड	—	31
चल टिकट परीक्षक	—	31

उत्तर रेलवे के मुख्यालय में आशुलिपिक

1146. **श्री विद्याधर वाजपेयी :** **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री निहाल सिंह : **श्री सूरज भान :**

क्या **रेलवे** मंत्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4604 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन किये जाने के लिए कोई तिथि निर्धारित की है और रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के लिए दायित्व भी निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि विभागों के अध्यक्षों और डिवीजनों के अधीक्षकों ने उपरोक्त आदेशों की प्राप्ति के पश्चात् इस बात पर बल देते हुए कि विद्यमान कसौटी व्यवहार्य नहीं है, 210-425 वेतनमान वाले आशुलिपिकों संबंधी अपनी आवश्यकताएं एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को भेज दीं;

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी आवश्यकताओं पर यथोचित ध्यान दिया गया और तदनुरूप कर्मचारियों का चयन किया गया;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां हो तो, लक्ष्य-तिथि क्या है और रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). जी हां। रेलवे बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर रेल प्रशासन ने जो तारीख नियत की थी वह 30 जून, 1968 थी। प्रवर वेतनमान के प्रत्येक अधिकारी को एक-एक आशुलिपिक देने के उद्देश्य से मंडल अधीक्षकों और कुछ विभागाध्यक्षों ने आशुलिपिकों की व्यवस्था करने वाले वर्तमान मानदण्ड में संशोधन करने पर बल दिया था और उपर्युक्त आदेशों के मिलने के बाद 210-425 रुपये के वेतनक्रम में अतिरिक्त आशुलिपिकों की मांग की थी। रेल-प्रसाशन अब उन मांगों की जांच कर रहा है और जब तक मांगे गये इन पदों की मंजूरी नहीं दी जाती अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए चुनाव नहीं किया जा सकता। ऊपर जो स्थिति बतायी गयी है उसे देखते हुए, उत्तर रेलवे के अधिकारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने का सवाल नहीं उठता।

रेलवे में आशुलिपिकों के लिये प्रोत्साहन-परीक्षा

1147. **श्री विद्याधर वाजपेयी :**
श्री सूरज भान :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की भांति रेलवे सेवा आयोग आशुलिपिकों को प्रोत्साहन-परीक्षा 100 तथा 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर लेता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो लोग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 100 या 120 शब्द प्रति मिनट की गति वाली परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें 210-530 रुपये का वेतन-मान दिया जाता है जबकि रेलवे सेवा आयोग की इसी स्तर की परीक्षा में सफल होने वालों को केवल कुछ अग्रिम वेतन वृद्धि देकर 130-300 रुपये का वेतनमान ही दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रेलवे द्वारा ली जाने वाली प्रोत्साहन-परीक्षा में सफल होने वालों को स्वत: 210-425 रुपये का वेतनमान दिये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रेलों में 130-300 रुपये वेतन-मान के आशुलिपिकों की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए रेल सेवा आयोगों द्वारा उनकी प्रोत्साहन परीक्षाएं ली जाती हैं। ये केवल अर्ह परीक्षाएं हैं। परीक्षा में सफल होने वाले आशुलिपिकों को अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं लेता है, वे 210-530 रुपये वेतनमान के उन आशुलिपिक की प्रारम्भिक भर्ती के लिए होती हैं जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्त किया जाता है जिसमें रेल मंत्रालय, भारतीय विदेश सेवा, सेना मुख्यालय आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उन्हें अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जाती हैं और उन्हें स्वत: ही ऊंचा ग्रेड देने का औचित्य नहीं है क्योंकि वह पदोन्नति ग्रेड है और रिक्तियों पर वास्तविक रूप से पदोन्नत होने पर यह ग्रेड मिल सकता है।

न्यूजीलैण्ड के साथ व्यापार

1148. **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री अदिचन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलैण्ड के प्रधान मंत्री श्री कीथ होलीओक ने यह सुझाव दिया था कि भारत को न्यूजीलैण्ड से दुग्ध-चूर्ण तथा ऊन का अधिक आयात करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो न्यूजीलैण्ड के विषम व्यापार सन्तुलन को ठीक करने के लिये दोनों देशों के बीच कोई व्यापार-समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस समय ऊन और दुग्ध-चूर्ण किन-किन देशों से भारत में मंगाया जाता है और उनके मूल्य न्यूजीलैण्ड द्वारा इन वस्तुओं के प्रस्तावित मूल्यों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) न्यूजीलैण्ड के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के दौरान मूल्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया । किन्तु, 1967-68 तथा 1968-69 (अक्तूबर, 1968 तक) की अवधि में जिन देशों से कच्ची ऊन तथा दुग्धचूर्ण का आयात किया गया था उनके नामों तथा आयातों की मात्रा तथा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 132/69]**

रेल के माल डिब्बों की सप्लाई

1149. **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से रेल के माल डिब्बों के निर्यात के सम्बन्ध में विभिन्न देशों से कुल कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : वर्ष 1965-66 से जनवरी, 1969 तक रेल माल डिब्बों/सवारी डिब्बों तथा फालतू पुर्जों के निर्यातों का मूल्य लगभग 10 करोड़ 82 लाख रुपये रहा है । इस समय लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात क्रयादेशों पर काम चल रहा है और कतिपय मामलों में इन क्रयादेशों के आधार पर आंशिक पोत लदान कर दिया गया है और इन्हें ऊपर दिये गये निर्यात उपार्जनों में दिखाया गया है ।

दक्षिण कोरिया को उसके रेलवे के विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये सहायता

1150. **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया ने अपनी रेलों के विद्युतीकरण के लिये भारत से

सहायता प्राप्त करने में रुचि दिखायी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए दोनों देशों ने बातचीत आरम्भ कर दी है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडोनेशिया के साथ व्यापार

1151. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में इंडोनेशिया से कितने मूल्य का माल मंगाया गया और उसे कितने मूल्य का माल भेजा गया;

(ख) इंडोनेशिया के साथ किन-किन वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इंडोनेशिया के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की दिशा में हाल ही में कोई नये प्रयत्न किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). दो विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखे जाते हैं जिनमें वर्ष 1964-65 से 1968-69, (अक्तूबर, 1968 तक), इंडोनेशिया से वस्तुवार आयातों तथा उसको किये निर्यातों को दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 133/69]

(ग) तथा (घ). दिसम्बर, 1966 में दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार हो जाने तथा इंडोनेशिया की सरकार को 10 करोड़ रु० का ऋण देने के परिणामस्वरूप गत कुछ वर्षों में भारत-इंडोनेशिया के व्यापार सम्बन्धों में काफी सुधार हो गया है। इंडोनेशिया के साथ व्यापार अवसरों का प्रचार करने के अतिरिक्त, सरकार इंडोनेशिया की व्यापारिक यात्राओं के लिए प्रोत्साहन दे रही है तथा उस देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये भी प्रोत्साहन दे रही है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1967-68 तथा 1968-69 में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में काफी वृद्धि हुई है।

गत सप्ताह, भारत तथा इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। मंत्रियों ने तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय ढूंढने तथा अपनाने और पारस्परिक लाभ के लिये व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव किया। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए, इस बात पर सहमति प्रगट की गई कि दोनों पक्षों को ऐसे सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये आगे विचार-विमर्श जारी रखना चाहिए।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात व्यापार

1152. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क के निर्यात में भारत को विकासशील देशों से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतियोगिता का प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मैंगनीज अयस्क के लिये भारत को जिस प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है उसके प्रधान कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) विश्व भर का उत्पादन 1965 में 1.76 करोड़ मे० टन से बढ़कर 1967 में 1.87 करोड़ मे० टन हो गया जब कि उसी अवधि में विश्व भर के कुल व्यापार में मामूली वृद्धि, 80 लाख से बढ़कर 81 लाख मे० टन हुई है;

(2) बेहतर भौतिक विशेषताओं तथा रासायनिक रचना वाले ग्रेडों के बद्ध स्रोतों (प्रमुखतः ब्राजील, गाबौन तथा घाना) के उत्पादन का विस्तार;

(3) आस्ट्रेलिया जैसे नये स्रोतों का आविर्भाव;

(4) भारतीय अयस्क की सापेक्ष बाधाएं अर्थात् उच्च उत्पादन लागत, अपेक्षाकृत लम्बा रेल मार्ग, अपर्याप्त पत्तन तथा लदान सुविधाएं;

(5) स्वेज नहर का बन्द होना जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम यूरोप तथा सं० रा० अमरीका को बिक्री के लिये जाने वाले माल के समुद्री भाड़े में 2 डालर प्रति मे० टन से अधिक बृद्धि ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम प्रतिकूल बाजार दशाओं के बावजूद अपने बाजार को काबू में रखने के लिये निरन्तर बिक्री संवर्धन उपाय कर रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में इस निगम के प्रतिनिधिमंडल ने बाजार दशाओं का अध्ययन करने तथा सौदे तय करने के लिये पश्चिमी यूरोप, सं० रा० अमरीका तथा जापान की यात्रा की। उन्होंने प्रतियोगी मूल्य प्रस्तुत किये और हमारे परम्परागत खरीदारों को भारतीय मैंगनीज-अयस्क खरीदते रहने के लिये राजी कर लिया है।

स्वदेश में परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के लिये समेकित प्रायोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके पूरा हो जाने पर समुद्री भाड़े में कमी हो जायेगी और इस प्रकार भारतीय अयस्क प्रतियोगिता शक्ति में सुधार हो सकेगा।

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना

1153. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट कारपोरेशन ने विभिन्न राज्यों में कई सीमेंट कारखाने खोलने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में भी सीमेंट का एक कारखाना खोला जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

हाइड्रोसल्फाइड सोडे का आयात

1154. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाइड्रोसल्फाइड सोडे की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में हाइड्रोसल्फाइड का देश में कुल कितना उत्पादन हुआ, उसकी मांग कितनी थी और उसका कितना आयात किया गया ;

(ग) किन कारणों से हाइड्रोसल्फेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जबकि उसके आयात हकदारी-लाइसेंसों की अवधि शेष थी और उसका नितान्त अभाव भी था ; और

(घ) हाइड्रोसल्फेट के समुचित वितरण के लिये इसका देश में उत्पादन बढ़ाने और इसके आयात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत दो वर्षों में हाइड्रोसल्फाइट सोडे का स्वदेशी उत्पादन, मांग तथा आयात निम्नलिखित रहा है :

	वर्ष	मात्रा
(1) उत्पादन	1967	4,309 मे० टन
	1968	5,646 मे० टन
(2) मांग	7,000 मे० टन प्रति वर्ष (अनुमानत:)	
(3) आयात	1966-67	4,196 मे० टन
	1967-68	3,799 मे० टन

(ग) स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये आयातों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है ।

(घ) हाइड्रोसल्फाइट सोडे की वर्तमान स्थापित क्षमता 7,160 मे० टन प्रति वर्ष है और इसे बढ़ाकर 9,260 मे० टन प्रति वर्ष किया जा रहा है। बर्धित क्षमता का परीक्षण के तौर पर उत्पादन आरम्भ किया जा चुका है।

हाइड्रोसल्फाइट सोडे की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये इसकी कुछ मात्रा का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने और इसके वितरण का काम भी उसी संगठन को सौंपने का विचार है।

रेलगाड़ियों में कंडक्टर और अटेंडेंट

1155. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों में कंडक्टरों और अटेंडेन्टों की व्यवस्था किन प्रयोजनों से की जाती है ;

(ख) क्या उनके कार्य पर कोई निगरानी रखी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रियों को डिब्बों में स्थान दिलाने, उनकी सुविधा पर ध्यान देने और उन्हें सभी सम्भव सहायता पहुंचाने के लिये कंडक्टरों की व्यवस्था की गयी है।

पूरे गलियारेदार टाइप के पहले दर्जे के सभी सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने और ऐसे सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा और सामान्य आराम की देखभाल करने के लिये सवारी डिब्बा परिचरों की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) जी हां, पर्यवेक्षक अधिकारी प्रायः उनके कार्यों की जांच करते रहते हैं।

(ग) इन जांचों से पता चलता है कि कर्मचारियों का काम सामान्यतया संतोषजनक है और वे यात्री जनता की उपयोगी सेवा करते हैं। जब कभी इन कर्मचारियों की गलतियां पकड़ी जाती हैं या उनकी रिपोर्ट मिलती है तो उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती और सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

Demonstration by the Employees of Central Cottage Industries Emporium, New Delhi

1156. **Shri T. P. Shah :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demonstration was staged by the workers of the Central Cottage Industries Emporium in front of the official residence of the former Commerce Minister in New Delhi in December, 1968 ;

(b) if so, the reasons for staging the demonstration ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) This demonstration was a part of agitation launched by some of the employees of the Emporium protesting against the promotion of a few employees of the Emporium to a senior cadre and to press for other demands, such as revision of pay scales and other benefits.

(c) Some of the demands falling under the Labour rules have been referred to the Department of Labour, Delhi Administration, while for others, efforts are being made to resolve the differences between the Management and the employees.

रूस को रेल के माल डिब्बों का संभरण

1157. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि रेल के माल डिब्बे 60,000 रुपये प्रति डिब्बे की दर से रूस को बेचे जायें तो करों में की गई कटौती को शामिल करने के बाद प्रति रेल माल डिब्बा कितनी हानि होगी ;

(ख) अन्य देशों को ये डिब्बे किस मूल्य पर बेचे गये हैं और क्या भविष्य में हमारा विक्रय मूल्य वही होगा जो मूल्य इस समय रूस से लिया जा रहा है ;

(ग) प्रति डिब्बे के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक डिब्बे का मूल्य कितना होता है ; और

(घ) इस समय रूस के साथ हमारी व्यापार संतुलन स्थिति क्या है और मूल्य सहित उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका आयात करने का प्रस्ताव भारत ने किया है किन्तु उन्हें सप्लाई करने से रूस ने मना कर दिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सोवियत संघ के प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) इस प्रकार के डिब्बों का न तो भारत में निर्माण हुआ है और न वे किसी अन्य देश को अभी तक बेचे ही गये हैं ।

(ग) थोक उत्पादन में स्वदेशी कच्चे माल तथा संघटकों का अधिकतम सम्भव सीमा तक प्रयोग किया जायेगा। जिस सीमा तक स्वदेशी आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, उस हद तक निर्यातों के पहले अंश के लिये विशेष इस्पात तथा पहियों के सेटों का कुछ मात्रा में निर्यात करना पड़ सकता है। ऐसे आयातों के वास्तविक मूल्य का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(घ) विगत तीन वर्षों में सोवियत संघ के साथ भारतीय व्यापार में आयात अथवा

निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(रुपये में)

	आयात	निर्यात
1966	88.4 करोड़	109.5 करोड़
1967	99.7 करोड़	127.0 करोड़
1968 अक्तूबर तक	105.8 करोड़	118.5 करोड़

भारत में आयात के लिये भारत-रूस व्यापार प्रबन्धों में शामिल वस्तुओं की सामान्यतः भारत को पूर्ति कर दी गई है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

1158. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा इस्पात कारखानों के कार्य-संचालन में कुछ परिवर्तन करने के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक पूंजी नियोजन में कमी कर के रुकी हुई पूंजी के कुछ भाग को बट्टे खाते में डालकर ऋण के अनुपात में कमी करके तथा मूल्यह्रास की दरों में कमी करके लाभ में वृद्धि करने के लिये प्रस्तावित परिवर्तनों का भार कौन वहन करेगा ;

(ग) ये परिवर्तन ब्रिटेन जैसे अन्य देशों के इस्पात कारखानों की लागत ढांचे की तुलना में कैसे हैं ; और

(घ) यदि मूल्य में 5 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो मुख्य श्रेणियों के सम्बन्ध में यह विश्व के मूल्यों की अपेक्षा कितनी अधिक होगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा इस्पात कारखानों के कार्य-संचालन में परिवर्तन करने सम्बन्धी दिये गये किसी वक्तव्य की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

मंगलौर रेलवे स्टेशन

1159. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर-इन-चार्ज आफ वर्क्स ने मंगलौर रेलवे स्टेशन का दौरा कब किया था और क्या उन्होंने स्थान की दुर्गन्धपूर्ण स्थिति के बारे में कोई निरीक्षण टिप्पण रिकार्ड किया था;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों को आर० एम० एस० तथा जी० आर० पी० से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सड़ रही मछली तथा पानी से और कच्ची सड़क की धूल से, जो कि उनके कार्यालयों के साथ-साथ बनी है तथा जिस पर भारी यातायात रहता है, आने वाली दुर्गन्ध के कारण उनके लिए कार्यालयों में बैठना असम्भव है ;

(ग) मछली के पानी के निपटान, सड़क को पक्का बनाने, पानी के तालाबों की व्यवस्था करने तथा नाली को रेलवे स्टेशन से रेलवे लाइन पर स्थानान्तरित करने के लिये क्या अनुमान तैयार किये गये हैं ;

(घ) आर० एम० एस० के लिये आवास की कमी को ध्यान में रखते हुए बरांडे को बैल्ड में से ढकने, जिससे कि डाक के थैलों को सुरक्षा से रखा जा सके, सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) रेलवे स्टेशन पर सफेदी तथा पेंट कब किया गया था और इस समय स्टेशन पर इसकी बिगड़ी स्थिति के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्रीनगर में पवित्र स्थानों को आग लगाने की योजना बनाने के कारण श्रीनगर में और काश्मीर के अन्य भागों में पाकिस्तान-समर्थक तत्वों के पकड़े जाने के समाचार

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

"श्रीनगर में पवित्र स्थानों को आग लगाने और उथल-पुथल पैदा करने की योजना बनाने के कारण श्रीनगर में और काश्मीर के अन्य भागों में पाकिस्तान-समर्थक तत्वों के पकड़े जाने के समाचार ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : राज्य में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की जांच के फलस्वरूप इस बात का पता चला है कि उक्त कार्यवाहियों में जासूसी के काम के लिये भूमिगत दलों का आयोजन किया जाना, एजेन्टों का प्रशिक्षण, हथियार प्राप्त करना और उपद्रवों की योजना भी शामिल है । सभा को याद होगा कि जुलाई, 1968 में पुलिस ने श्रीनगर में इस्लामिया कालेज पर हमले के उस प्रयास को असफल कर दिया था जो एन०सी०सी० के हथियारों को छीन लेने के उद्देश्य से किया गया था । इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां हुयीं ।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से पूछताछ करने पर संगठन की कुछ अन्य शाखाओं का पता चला और उसके फलस्वरूप और गिरफ्तारियां हुई तथा कुछ व्यक्तियों को नजरबंद किया गया। पूछताछ से उस दो वर्ष पुराने मामले को तैयार करने में भी सहायता मिली जिसमें सीमा सुरक्षा बल के संतरी को मारा गया था और उसकी राइफल छीन ली गई थी। इस मामले के कथित 5 अभियुक्तों में से 4 को पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार व्यक्तियों से अभी तक बरामद किये गये सामान में दो राइफलें हैं। जिनमें से एक राइफल सीमा सुरक्षा बल के उस संतरी की है जिसकी हत्या की गई थी और कुछ ऐसा बिस्फोटक सामान है जिस पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चिह्न अंकित हैं। तोड़फोड़ की कार्यवाही करने वाले इन दलों की योजना में जासूसी करने, जनता में असन्तोष फैलाने, भय पैदा करने, आग लगाने तथा धार्मिक और पवित्र स्थानों को अपवित्र करने के कार्य भी शामिल हैं।

अब तक की गई जांच का पूरा ब्योरा देना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। जासूसी और तोड़-फोड़ के कार्यों से निपटने के लिये राज्य की पुलिस और सुरक्षा बल पूर्णतया सतर्क और सक्षम है।

श्री सु० कु० तापड़िया : भारत सरकार तथा काश्मीर सरकार दोनों ही बार-बार यह दावा करते हैं कि वे तोड़-फोड़ करने वाले गिरोहों का सफाया करते आ रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी जल्दी-जल्दी उनका सफाया करने पर भी, हमारी सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, होम गार्ड्स, अतिरिक्त पुलिस आदि को इन गिरोहों का पता केवल तभी चलता है जब वे सीमा से लगभग 100 मील अन्दर चलकर श्रीनगर पहुंच जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन गिरोहों का ब्योरा क्या है जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि उन्हें नष्ट कर दिया गया है। कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये हैं और क्या उन्हें कारावास भेजा गया है, क्या यह सच है कि उनमें से बहुत से व्यक्ति किसी तरह भाग निकले हैं और उन्हें जेल में बन्द नहीं किया जा सका ? पकड़े गये गोला-बारूद तथा राइफलों पर क्या निशान पाये गये हैं और वे किन-किन वर्षों के बने हैं और अन्त में, सरकार स्थिति को आंकने के लिये तथा ऐसे व्यक्तियों को सीमा क्षेत्रों में पकड़ने के लिये और न कि बाद में जबकि वे श्रीनगर पहुंच जाते हैं, अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इतनी जल्दी-जल्दी इन बातों का पता लगने से जाहिर है कि पुलिस संगठन इन बातों के बारे में बहुत सक्रिय तथा सतर्क है। जहां तक जब्त किये गये हथियारों पर निशानों का सम्बन्ध है, कुछ विस्फोटक पदार्थों तथा राइफलों पर पी० ओ० एफ० के निशान मिले हैं। मैं उन ही हथियारों का उल्लेख कर रहा हूं। कठिनाई यह है कि कभी-कभी कुछ हथियारों पर कोई निशान ही नहीं होता ; वे किस वर्ष के बने हैं ऐसा उन पर कोई चिह्न नहीं है। यह सच नहीं है कि बहुत से लोग भाग निकले हैं। बहुत से व्यक्ति नजरबन्द हैं जिनके बारे में जांच चल रही है। यह सच है कि दो व्यक्ति जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया था, जेल से निकल भागे हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): I want to know whether (a) Government are aware of the existence of any arms factory in the Pakistan occupied areas of Kashmir; (b) whether these saboteur rings are under the direct control of Pakistan; (c) the names of religious shrines and holy places the arson of which was aimed at; and (d) the names of the veterans who are involved in this conspiracy as was indicated by the Chief Minister of Jammu and Kashmir while speaking to the Press?

Shri Y. B. Chavan: So far as arms factories are concerned, the Hon. Member also knows that there are such factories in Pakistan, so there is nothing to ask about it. So far as the persons who are involved in it, are concerned, the investigation is still on and I would not be able to disclose any further information.

जहां तक उन लोगों पर पाकिस्तान के डायरेक्ट कन्ट्रोल का सम्बन्ध है, इस मामले में दो बातें हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों का एक इरादा यह था कि धार्मिक स्थानों को अपवित्र करके लोगों में असन्तोष फैलाये जायें। ये लोग पाकिस्तान के घुसपैठिये नहीं हैं, ये लोग तो खुद श्रीनगर तथा काश्मीर घाटी में रहने वाले लोग हैं। जैसा कि ये योजनाएं पाकिस्तान समर्थक योजनाएं हैं इसलिये इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके तथा पाकिस्तानी जासूसी गतिविधियों के बीच बड़ा निटक सम्पर्क रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): क्या पश्चिम पाकिस्तान जिसका चीन की ओर थोड़ा झुकाव लगता है और जिसका प्रमाण उनके कुछ नेताओं के वक्तव्यों से मिलता है, मैं हाल में गड़बड़ी के रुख को देखते हुए, सरकार इस नई घटना की ओर गौर कर रही है तथा सीमाओं पर गंभीर कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रही है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: भारत के चारों ओर जो कुछ हो रहा है, हम स्वभावतः उस पर गंभीर रूप से गौर कर रहे हैं। इस बारे में मुझे यही कुछ कहना है। यह सच है कि वर्ष 1965 के पश्चात् इन जासूसी गिरोहों को कई बार तोड़ना पड़ा है, ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों में भी घुसपैठ करने की एक प्रकार की योजना है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया: (जालोर): वर्ष 1965 में पहलीबार एक दम बड़े पैमाने पर 12,000 घुसपैठिये श्रीनगर में घुस आये थे और उसके बाद भी बीच-बीच में ऐसी घटनाएं होती रही हैं और जिनके बारे में हम सुनते रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इन लोगों को चाहे वे जासूस हों, अथवा पाकिस्तानी तत्व, श्रीनगर में या उसके आस-पास ही उनका पता लगता है और वहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है लेकिन सीमाओं के नजदीक नहीं, हमारे पास सेना है, पुलिस है, होम गार्ड हैं, फिर भी हम उन्हें सीमा पर गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते—उन्हें वहीं पर क्यों नहीं रोक सकते? दूसरी बात—जिन तीन व्यक्तियों को सजाये मौत दी गई थी, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वे सरकारी मोटर गाड़ी में बैठकर जेल से भागे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री को यह बात मालूम है और यदि नहीं तो क्या वह इस बारे में समुचित जांच करायेंगे?

तीसरी बात यह कि श्री भुट्टो तथा विभिन्न अन्य पाकिस्तानी तत्वों द्वारा हाल में दिये गये वक्तव्यों को देखते हुये तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य मशीनरी पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से स्थिति नियंत्रण रखने में असफल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सन्तुष्ट है कि राज्य प्रशासन का कुछ अंश इन गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि उन्हें केवल श्रीनगर में इस कारण गिरफ्तार किया जाता है कि उनमें से अधिकतर लोग श्रीनगर के हैं। जहां तक सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों का सम्बन्ध है, इस बारे में चर्चा कभी अन्य अवसर पर होनी चाहिये क्योंकि इस समय मैं केवल वही तथ्य दे रहा हूं जो मुख्य मंत्री के हाल के वक्तव्य पर आधारित हैं। जहां तक भाग निकले लोगों का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार उनकी संख्या दो है और इस बारे में मेरी और आगे जानकारी यह है कि वे सरकारी मोटर गाड़ी में नहीं भाग निकले थे।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं सन्तुष्ट हूं कि राज्य प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ, पाकिस्तान में जासूसी पार्टियों का एक इरादा सरकारी कर्मचारियों में घुसने का भी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं।

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये के विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में, माननीय मंत्री जी ने दो अथवा तीन दिन का समय मांगा है और मैंने उन्हें समय दे दिया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I submit that I should be heard at least. I assure that I will not go against the wishes of the chair. The notice of the motion was given long back —during the last session of Parliament. But the matter has been so delayed. You were pleased to ask me the other day to raise it on Friday last. Later on you revised your decision and informed me accordingly that as the New Minister had wanted two or three days' time to go through the relevant papers, I should raise it on Tuesday. And today is Tuesday. Again the Minister wants to be given two or three days' more time. My motion is not against any Minister. I am raising this matter on behalf of the whole House, because two high officials of the Government gave and furnished false evidence before the P. A. C. which is the most powerful body of the two Houses of Parliament.

Everyone knows, that in democracy it is the Minister concerned who is pulled up for the omissions and commissions of his officials. I do not know why the Minister wants to put obstacles in or prolong the matter. I do not want anything more than a simple and formal discussion on the matter before it is referred to the committee on privileges.

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने इसकी सूचना पिछले सत्र में दी थी। मंत्री महोदय ने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया है। वे सभी सम्बन्धित कागजों का अध्ययन नहीं कर सके।

अत: मंत्री महोदय उत्तर तैयार करने के लिये कुछ और समय चाहते हैं। मैंने उनको समय दे दिया है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : क्या वह इस मामले का कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये विरोध करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वह पूरे तथ्य जानने के पश्चात् इस पर सहमत हो जायेंगे।

श्री रंगा : हम नहीं चाहते इस सभा द्वारा इस मामले पर अब कोई निर्णय लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह तथ्यों का अध्ययन करना चाहते हैं और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उनको अध्ययन के लिए समय मिलना चाहिए।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : प्रस्ताव लोक लेखा समिति के समक्ष दिये गये झूठे साक्ष्य के बारे में है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया—सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 107/69]

खनिज रियायत (संशोधन) नियम तथा कोयला बोर्ड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रो रसायन, खान तथा धातु मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 154 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 108/69]

(2) कोयला बोर्ड, कलकत्ता के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 109/69]

दामोदर घाटी निगम के बजट अनुमान

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : डा० कु० ल० राव की ओर से मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1969-70 के बजट अनुमानों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-110/69]

रांची-हांटिया में साम्प्रदायिक उपद्रवों के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं रांची-हांटिया में साम्प्रदायिक उपद्रवों (अगस्त 22—29, 1967) सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०** 111/69]

कपड़ा समिति के लेखा-परीक्षित लेखे व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का वार्षिक प्रतिवेदन

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन कपड़ा समिति के वर्ष 1966-67 के लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 112/69]

(2) व्यापार तथा व्यापारिक माल चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अधीन 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 113/69]

(3) व्यापार तथा व्यापारिक माल चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अधीन व्यापार तथा व्यापारिक माल चिह्न (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 23 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 397 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 114/69]

(4) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के सरकारी संकल्प संख्या 14 (1) टार/68 का शुद्धिपत्र संख्या 14 (1)-टार/68 दिनांक 9 जनवरी, 1969 की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 115/69]

(5) चाय बोर्ड के वर्ष 1966-67 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 116/69]

(6) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) सेफ्टी ग्लास का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 जो दिनांक 15 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 165 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 जो दिनांक 16 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 268 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) हैसियन-बैग्स का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 जो दिनांक 17 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 272 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 18 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 277 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) वाइनिल फिल्म तथा शीटिंग का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 जो दिनांक 1 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 457 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 117/69]

पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में उद्घोषणा का रद्द किया जाना

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं राष्ट्रपति द्वारा 25 फरवरी, 1969 को जारी की गई उद्घोषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अधीन 25 फरवरी, 1969 को प्रकाशित हुई है। जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 118/69]

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि ईद्दुजुहा गुरुवार 27 फरवरी के बजाये अब शुक्रवार 28 फरवरी को होगी। इसलिए बजट पेश किये जाने के अतिरिक्त प्रश्नों तथा गैर-

सदस्यों का कार्य जोकि 28 फरवरी, 1969 को किया जाना था अब गुरुवार 27 फरवरी, 1969 को किया जायेगा। सामान्य बजट पेश किये जाने के लिये सभा शुक्रवार 28 फरवरी, 1969 को 5 बजे म० प० पर समवेत होगी।

लोकपाल तथा लोकआयुक्त विधेयक
LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन पेश किये जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कतिपय मामलों में सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक कार्यवाही की जांच के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों के लिए तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 29 मार्च, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

श्री बाबर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : मैं समय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। उप प्रधान मंत्री ने, जोकि प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन भी थे, एक विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और अनुरोध किया है कि उस पर तुरन्त चर्चा की जाये। तीन वर्ष गुजर गये हैं परन्तु अभी तक प्राथमिक अवस्थाएं भी नहीं गुजरी हैं। यदि सरकार यह आश्वासन दे कि इसको वर्तमात सत्र में ही लिया जायेगा तो समय बढ़ाये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय मामलों में सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से अथवा कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रशासनिक कार्यवाही की जांच के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों के लिये तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 29 मार्च, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। आज हम सारा दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगी। कुछ दलों का समय भी अभी शेष है। मैं निर्दलीय सदस्यों को भी समय देना चाहता हूं।

कांग्रेस पार्टी का केवल एक घंटा शेष है। यदि इसमें से माननीय मंत्री भी समय चाहें तो मैं अलग से उनको समय नहीं दे सकूंगा।

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : I want to draw the attention of the House on para 35 of the Address wherein it has been said that we should try to build India of Mahatmaji's dream. I have to say with great regret that nothing has been done for the upliftment of the Harijans during the last twenty years. Hon. Members on both sides have done nothing to remove untouchability. No effective steps have been taken by Government in this direction. These people who are17 crore in number are leading a worse life than the animals. No attention has been paid towards their upliftment. Most of these people are agricultural labourers, but nothing in the Address has been said about their upliftment or allotment of land to them. I want that my colleagues who are in the cabinet and who are representing the Harijans should force the Government for formulating and presenting a constructive programme for the upliftment of these classes or they should resign from the cabinet.

Much has been said about the success of the Family Planning programme. I can challenge it. You can collect the figures about any particular area and see yourself that only aged unproductive people has been operated upon.

The Hon. President has not said anything about the development of Urdu or declaring it a regional language. When he was not President of the country he was fighting for the development of Urdu and he brought forward a memorandum bearing 22 lakh signatures in which it was demanded that Urdu should be declared a regional language and that it should be given due recognition.

I also want to draw the attention towards the problems of the people of Budha religion. Necessary facilities are not provided to people who adopt Budha religion.

Unemployment, casteism and corruption is rampant in the country.

The report of the scheduled castes/schedule tribes Commission is stlll lying in the waste paper basket. No action is being taken on it.

Roads have important role in the development of the country. Many roads which link villages are in poor state of affairs. They are not being repaired. On my raising a question about their repair it was said that they are near the China border and that it is not out of danger to repair them or to construct new ones. But Mr. Speaker, it is necessary for the development of that area to construct the roads or repair the old ones.

The Government should bring into reality at least half of the things which have been mentioned in the Address. I admit that India is progressing but still it is too backward as compared to other countries because casteism is still rampant in the country.

Dr. Shushila Nayar (Jhansi) : I rise to support the motion of thanks on the President's Address. The President has not tried to give the credit to the Government for the hand work and sacrifices made by the people. On the other hand it has been said in the beginning of the Address that the manner in which our people faced the difficulties with courage and fortitude is a matter for pride. It is clear that the Hon. President has tried to give due credit to the people. But I may say that Government has also some responsibility and we should admit

that policies of the Government in regard to the agriculture have met with success. Production in the fields has inereased. But Government should put more efforts in the supply of water and fertilizers to the farmers. If this can be done, India can become a grain exporter country.

It is good to have buffer stock of the grains if they are not allowed to rot. Proper attention has to be paid on their maintenance otherwise labour of the farmers will go waste.

It has also been said in the Address that income of the country has increased to the tune of 1393 crores of rupees last year. But there is a need to pay attention to its distribution. We should have decentralized planning for the upliftment of people of the rural areas. Their increased income should be spent for their welfare. We should not try to take away this increase in their income in any way. More streets and roads should be constructed. Agriculturist will produce more if he is happy.

I have seen myself in the villages during the elections that people are opposed to family planning. They are even not allowing the family planning in the villages. We should try to know why this change has come in the people. I know that Jan Sangh people have made wide publicity against family planning. But they alone cannot bring this change in the minds of the people. There is definitely something wrong in the implementation of the programme. I think that we should have the local leaders with us in this matter. They can make the people understand that this is for their betterment.

So far as Public undertakings are concerned I may say that we can be benefited by them only if they are run to their full capacity. Special attention should be paid towards this thing. Some incentive should be given to the technical people working in these public sector plants. There is also need to bring improvements in the administration.

So far as tourists are concerned they come to see here Indian culture and Indian way of living. We should serve them pure food and water. We can provide them good place to live. It is not as that they will not come if wine is not served to them.

So far Gandhi centenary is concerned we can take advantage of this opportunity and can do many good things in the country. We can undo the mistakes committed during the last 20 or 21 years. Peace can be established if problems like casteism and language are solved. It is not difficult to solve them if we have determination to solve them. Secondly if we appoint some judge to give his award on some problem, it may be Mysore-Maharashtra border then his award should be accepted. So far as Chandigarh is concerned some decision should be taken immediately. This matter should not be prolonged.

We should pay attention towards the poor backward and suppressed people.

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar): It is appreciated that India is making progress. We have a bumper crops this year. Our trade has also increased. But the integrity of the country is in danger. There have been boundary disputes, disputes of water etc. during the last year. There have been strained relations between the States and the Centre. Problems are not being solved properly.

There have not been Stable Governments in states due to defections. Governor is mostly responsible for dissolution of many State Governments. Government sends the report for

implementing President's rule in the States. The Governor's issue has been a very controversial issue. I have an objection with regard to the appointment of Governors. The procedure of appointment of Governors should be changed. So that people may not point out that a person defeated in elections has been appointed as Governor by the ruling party. I want to make a suggestion in this regard. Alike President's and Vice-President's elections, the election of the Governor should be done.

So far as the question of defections is concerned, forming a Committee is not enough. A Bill should be introduced in this regard and a provision should be made that the defector should have to seek re-election. He should be compelled to resign his seat.

There is no doubt the morale of our armed forces is very high. But their emoluments and the conditions of services are not proper. Their condition of services are bad as compared to Police, Homeguard, Border Security Force etc. Government should pay proper attention towards them. Our Forces cannot remain happy unless proper facilities are given to them.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प०
तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) राष्ट्रपति महोदय ने सरकार की सुदृढ़ विदेश नीति का उल्लेख किया है । देश के आन्तरिक मामले में होने वाले विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अभी भी भारत का 15,000 वर्ग मील क्षेत्र लाल चीन के कब्जे में है । हमें रोज सुनाई देता है कि सशस्त्र तथा प्रशिक्षित गुरैला नागालैंड और मिजो क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रहे हैं और सरकार अभी तक उनको रोकने में सफल नहीं रही है । देश से घुसपैठियों को निकालने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसके बावजूद भी भारत की विदेश नीति पर गर्व किया जाता है ।

1968-69 में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसके लिये बाढ़ और सूखे को दोष दिया गया है ।

देश के स्वतन्त्र होने के 22 वर्ष बाद भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है । इस उत्पादन के लिये यदि किसी की प्रशंसा की जा सकती है तो वह है किसान । किसानों ने अपने दायित्व को निभाया । उन्होंने नये वैज्ञानिक तकनीक अपना कर इतना उत्पादन किया है ।

यदि किसानों को पानी सप्लाई किया जाये तो वे आनाज की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं । राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों से सिंचाई सुविधाएं देने का प्रयास कर रही हैं । लेकिन केन्द्रीय सरकार से पानी के मामले में सहयोग प्राप्त न होने के कारण यह विवाद

बना हुआ है, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी के बारे में विवाद कई वर्षों से चल रहा है। समस्या को हल करने की बजाय इसमें राजनीति को लाया जाता है और कहा जाता है कि राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा उनका हिस्सा दिया जा रहा है।

राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आगामी योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जायेगी। यह दुख की बात है कि कृषि पर भी कर लगाया जा रहा है। सरकार किसी भी बात पर निर्णय लेने में असमर्थ रही है और वह मीठापुर प्लान्ट या उड़ीसा में तलचर समूह में यूरिया प्लान्ट लगाने में असफल रही है।

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां भी बहुत कम रही हैं। मूल्य बहुत ऊंचे बढ़ रहे हैं। कीमतों में जो स्थिरता आई थी वह अस्थायी थी। जब तक सरकार अपने मूल विचारों में परिवर्तन नहीं करेगी आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकता।

रुपये की क्रय-शक्ति घटती जा रही है। कम और नियत आय वाले लोगों के लिये गुजारा करना बहुत कठिन है। अमीर और अमीर हो रहे हैं जबकि करोड़ों भारतीय और गरीब होते जा रहे हैं। देश के निर्यात में कमी हुई है।

कोटे का लाइसेंस जारी करने, आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और निर्यात पर नियंत्रण लगाने से राष्ट्रीय उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिन लोगों को कोटे के लाइसेंस दिये गये हैं उन्हें बहुत लाभ हुआ है। वे लोग करोड़पति हो गये हैं। लड़ाई से पूर्व अनाज के व्यापारियों को बहुत कम लाभ होता था लेकिन आज उन्हें इसका एकाधिपत्य प्राप्त हो गया है। क्योंकि सरकार ने नियंत्रण जारी कर दिया है। जब तक सरकार इस नियंत्रण को समाप्त नहीं करेगी बनावटी अनाज की कमी जारी रहेगी। सरकार को सब कंट्रोल, लाइसेंस और परमिटों को समाप्त करना चाहिये।

देश में बचत में कमी हुई है। राष्ट्रीय आय में 18 प्रतिशत वृद्धि होने की बजाय 20 वर्ष से बचत में स्थिरता रही है और 1965-66 के बाद तो इसमें और कमी हुई है। सामान्य व्यक्ति के लिये अपने बच्चों को दूध तथा उनकी फीस की व्यवस्था करना कठिन हो गया है।

देश में नौकरी के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। इसी कारण देश में इंजीनियरों और तकनीकियों में बेरोजगारी में इतनी वृद्धि हुई है और उनमें से बहुत से इंजीनियर देश से बाहर जा रहे हैं।

आंतरिक ऋण और वैदेशिक ऋण का भार 5,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। घाटे की अर्थव्यवस्था से देश में वित्त की स्थिति और खराब हो गई है। सत्तारूढ़ी दल द्वारा गत 22 वर्ष से गलत नीतियों का पालन करने के कारण देश की आज यह दशा हुई है। इसके बावजूद भी नीतियों पर पुनः विचार करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

समाजवाद के नाम पर लोगों के मूलभूत अधिकारों में कमी की जा रही है। यदि सामाजवाद का अर्थ लोगों के स्तर को बढ़ाना, लोगों के लिये दो वक्त के खाने की व्यवस्था करना लोगों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करना, अधिक उत्पादन करना और प्रादेशिक असमानता को दूर करना है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन यदि सामाजवाद का काम राज्य नियंत्रण, लाइसेंस, परमिट, कोटा आदि देना, सत्ता में आना और मूलभूत अधिकारों को देने से इंकार करना है तो मैं ऐसे समाजवाद को अस्वीकार करता हूं।

सरकार द्वारा वर्गीकरण की भावनाएं उत्पन्न करने के कारण देश में असमानता उत्पन्न हुई है। हमने देश के लिये सब कुछ त्याग दिया। भाषा विवाद, जल विवाद, क्षेत्रीय दावे और उनके विरुद्ध दावे राज्य में आपसी मतभेद केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सुविधाओं में भेदभाव किया जाना, राज्यों के आन्तरिक विवादों के मामले में निर्णय न लिये जाने से देश में निराशा व्याप्त है। आज भू-स्वामी, किरायेदार, विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच विवाद का होना एक सामान्य सी बात हो गई है।

उड़ीसा में राज्य की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में बहुत अन्तर है। इसके लिये केन्द्र की गलत नीति दोषी है। यदि देश का विकास किया जाना है तो देश में सब एककों का समान रूप से विकास किया जाना चाहिये। पारादीप पत्तन पर खर्च किये गये 15 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सरकार ने क्षतिपूर्ति नहीं की है। तालचरान्द बिमलगढ़ के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने में जानबूझकर विलम्ब की जा रही है।

उड़ीसा सरकार ने 321 करोड़ रुपये की चौथी योजना तैयार की है। राज्य के लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। 35 प्रतिशत लोगों को 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कम आय है। प्रति व्यक्ति न्यूनतम 20 रुपये की आय और चौथी योजना के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 1220 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को पांच वर्षों में मंहगाई के रूप में 10 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार को वैसे ही परेशान किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण राज्य सरकार को क्यों परेशान किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार के 321 करोड़ रुपये की योजना का समर्थन करना चाहिये और इसमें उसे पूरी सहायता करनी चाहिये।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : It is observed that similar views about the conditions of Harijans have been expressed in the reports submitted by the commission for scheduled castes and scheduled tribes and Perumal Committee but Government is adopting different attitude towards them. It is strange that nothing has been mentioned in the President's Address though Harijans were given high hopes in the election meetings. Whatever has been done for the removal of untouchability is negligible. In fact we should eradicate untouchability so that Harijans may find equal opportunities in service and other walks of life and lead an honourable life. It is a matter of concern that Government's attention has not been drawn towards this

fact in the President's Address. I may also state that Shri Golwalker has wrongly been quoted that he is in support of caste system. On the contrary he is against such caste system.

Many a time question of communalism has been raised and discussed here. I want to draw attention of the House to the demand of creation of Mallapuram district in Kerala State. Certainly it is being constituted on communal basis which is dangerous for the national integration and from the security point of view. This is an old demand of Muslim League and Mr. Jinnah had advised the Muslims of South to demand Moplistan so that they may create circumstances to enact coastal areas with Pakistan. Communists are also supporting this move because Mr. Koya, a Minister in Kerala State has told them that if they would oppose the move, they would withdraw their support. I would request the Hon. Minister of Home Affairs to examine this matter. I may also point out that it is not proper to use undignified words against Mahatma Tulsi Dass.

It is understood that Governor of Bihar has sent a Bill of Rs. 14 lakhs in connection with the election campaign of Prime Minister which had been spent on many other items besides security. May I know as to how this expenditure would be met from the exchequer? It would be appreciated if the Prime Minister gives detailes of the money received by her and the manner in which it would be received.

The art-silk mills of Amritsar are facing closure because there is monoply of Birla on 70 per cent raw material required for the purpose. We had contacted Shri Dinesh Singh but no one could dare to talk with him.

It has been published in the newspapers that Shri Suresh Kumar son of Shri Jagjiwan Ram has been in receipt of Rs. 1250/- or Rs. 1247 per month from a firm in West Germany. Will the Hon. Minister clarify it.

We should consider the circumstances through which our country is passing.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur): There is shortage of Fertilizer Plants in our country. We should instal more such plants so that employment opportunities could be increased. If we supply water of Narmada to Madhya Pradesh then Madhya Pradesh will be able to supply foodgrains to other states also and moreover it would help us in achieving self-sufficiency.

I may also point that a lot of avoidable expenditure in Government Departments should be checked. We should reconsider the question of top-heavy administration.

In order to remove the menace of communalism we should inculcate the feelings of nationalism and secularism in masses. It has been stated in the "World Peace through Love" that Divine love will conquer hate and fear. We must realise the realities of the world and act accordingly otherwise it would be difficult for the Governments to stay in power.

It has rightly been suggested in the President's Address that we should discuss and argue the measures to be adopted for reconstruction of society but ultimately we should reconstruct India according to the dreams of Gandhiji. I may, however, point out that before passing any uncalled remarks against the Hon. Minister of Home Affairs Hon. Members should think about themselves in the first instance.

I would suggest that entire country should be divided into four zones. The people living in each zone should speak regional language of the area to which they belong. Every one should respect each other's language.

In the end I would suggest it is not proper to abolish the post of Governor because it would create difficulties in co-ordinating the work of different States.

श्री जी० कुचेलर (बेल्लौर) : राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण पहले हिन्दी में पढ़ा था जिसे हम समझने में असमर्थ थे । उन्हें हमारी कठिनाइयों का ध्यान रखना चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है । यदि यह बात ठीक है तो जीवन निर्वाह की लागत कैसे बढ़ती रही और वर्ष 1960 से जनवरी 1969 तक महंगाई भत्ता कैसे बढ़ाया जाता रहा है । मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वह कृषि उद्योग, जो हमारे देश का मूल उद्योग है, के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने में असफल रही है । सरकार उनके लिये न्यूनतम मजूरी भी निश्चित नहीं कर सकी है । उनके हितों की रक्षा करने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये । इस उद्योग के कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये तामिलनाडू में आकाशवाणी के कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रयोग के विरुद्ध आन्दोलन की ओर हम केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं । समाचार प्रकाशित करने वाले बुलेटिन का समय बदल कर हिन्दीं न जानने वालों की प्राथमिकता को कम कर दिया गया है । इससे हमारे राज्य में काफी गड़बड़ी हो गई है । मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाषा की समस्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है । हमारे सामने पहले ही काफी समस्याएं हैं, हमें समाचार बुलेटिनों का समय बदल कर एक और समस्या नहीं पैदा करनी चाहिये । अतः सरकार को फिर पहले वाले समय पर समाचार प्रसारित करने चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हरिजनों की परेशानियों का कोई उल्लेख नहीं है । उन पर अत्याचार किये जाते हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती । अब तक जातिवाद को समाप्त कर दिया जाना चाहिये था । हरिजनों के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

शिव सेना द्वारा पैदा की गई समस्या के साथ सरकार को दृढ़ता से निपटना चाहिये । गृह-कार्य मंत्री को इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकना चाहिये । उन्हें उन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये । बम्बई में किये गये अत्याचारों का मैं विरोध करता हूं आज देश में कुछ अनुशासन और सिद्धान्त स्थापित करने की आवश्यकता है । यदि सरकार ने अनुशासन और सिद्धान्तों के अनुसार कार्य-वाही नहीं की तो उनके सम्मान को धक्का पहुंचेगा । इस सरकार को राष्ट्र के सम्मान को कम नहीं करना चाहिये ।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : श्रीमान्, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर चकित रह गया था । उन्होंने 60 लाख टन के अधिक खाद्य उत्पादन पर सरकार की सराहना की है परन्तु

देश के निम्न वर्गों की कठिनाइयों का उल्लेख तक नहीं किया गया। देश के छोटे स्तर के किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्हें अभी भी प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है।

आज हमारे देश की राजनैतिक स्थिति में भी हलचल है। बम्बई से कोहिमा तक गड़बड़ फैली हुई है। जनजीवन में अशान्ति आ गयी है। देश में हजारों की संख्या में इंजीनियर बेकार फिर रहे हैं। अन्य वर्गों में रोजगार की स्थिति भी खराब होती जा रही है।

हम जानते थे कि विभिन्न राज्यों के बीच विवाद चलते थे परन्तु अब तो एक राज्य के बीच के लोगों में ही झगड़े-फिसाद आरंभ हो गये हैं। यह चीज हमें तेलंगाना में देखने को मिली है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में वास्तविक स्थिति का उल्लेख नहीं है।

अब मैं मध्यावधि चुनावों के परिणामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि देश की जनता ने जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों को चुना है और धनी लोगों का साथ नहीं दिया है। बीस वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी का एकधिकार चलता रहा। अब यह परिवर्तन हुआ। नई पीढ़ी के लिये इसका विशेष महत्व है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र को हम परीक्षण द्वारा सुदृढ़ बना सकते हैं।

हमारे देश में लोग बहुत निर्धन हैं। लोगों के पास रहने को स्थान और खाने को कुछ नहीं है। यदि समूचे देश में पुनः चुनाव कराये जायें तो लोग कांग्रेस को बिल्कुल कोई स्थान नहीं देंगे। और देश में नये गठबन्धनों की प्रक्रिया आरंभ होगी।

कांग्रेस दल एक प्रकार की खिचड़ी है। इसमें विभिन्न तत्व जमा हो गये हैं। चुनाव में जो परिवर्तन सामने आया है, इसके लिये देश के युवक जिम्मेदार हैं। मैं मांग करता हूं कि मत देने के लिये 21 वर्ष की आयु को कम करके 18 वर्ष नियत किया जाये। इस प्रकार अधिक लोग चुनावों में भाग ले सकेंगे। देश में इससे स्वस्थ परिवर्तन आयेंगे।

मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि प्रधान मंत्री के लिये 25 लाख रुपये की लागत से एक बंगला बनाये जाने का प्रस्ताव है। एक निर्धन देश, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं, वहां ऐसा करना कैसे उचित है ? इस गांधी शताब्दी वर्ष में तो प्रधान मंत्री को यह नहीं करना चाहिये। इतनी धनराशि से 50,000 नलकूप लगाये जा सकते हैं, हजारों स्कूलों की मरम्मत की जा सकती हैं। खेद की बात है कि देश के स्कूलों में बच्चों को बैठने को तो स्थान न मिले, परन्तु प्रधान मंत्री के बंगले पर 25 लाख रुपये व्यय किये जायें। राजधानी में पहले ही बहुत से भव्य भवन हैं। उनमें से किसी एक को प्रधान मंत्री के बंगले के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

गांधीजी की बात बहुत की जाती है। उनके बताये मार्ग का अनुसरण करने की सीख दी जाती है, परन्तु दुख की बात है यही लोग उससे विपरीत कार्य करते हैं। गांधीजी की जिस बिड़ला भवन में हत्या हुई थी, उसे यह स्मारक बनाने के लिये लेना नहीं चाहते। इसके लिये एक आन्दोलन आरंभ करना पड़ा था। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं।

यह दावा किया गया है कि उद्योगों ने प्रगति की है। मैं जानना चाहता हूं कि देश के युवकों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है। उन्हें छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं। बड़े-बड़े एकाधिपति ही देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किये हुए हैं। नये स्नातकों और तकनीकी शिक्षा वाले व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई है। यह स्थिति देश के स्वतन्त्र होने के बीस वर्ष बाद की है। आज भी देश में ब्रिटिश इतिहास के अध्ययन की व्यवस्था चल रही है।

देश में भष्टाचार बहुत फैला हुआ है। उड़ीसा में खन्ना आयोग के प्रतिवेदन के बावजूद श्री पटनायक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आगामी 22 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो जायेगी। इसलिये मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वह देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाये। लोगों को रोजगार दिलाने सम्बन्धी योजनाएं भी इसी प्रकार बनायी जानी चाहिये। नई-नई वैज्ञानिक वस्तुओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना चाहिये।

सरकार को छोटे किसानों और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। उनकी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिये। पूंजीपति देशों में देखा गया है कि मजदूरों को प्रसन्न करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। ऐसे उदाहरण हमें जापान तथा इजरायल में मिलते हैं।

Shri Randir Singh (Rohtak): Sir, I support the motion of thanks moved by Shrimati Sushila Rohatgi on the President's Address.

It is a sad commentary that Government is paying lip sympathy to the difficulties of farmers. I feel that the farmers are fed up with Congress Party. They are going away from this party. It is a very dangerous trend. I find this trend among the farmers of Haryana, Punjab, U. P., Bihar and West Bengal. These our friends are misleading the farmers.

This thing saddens me very much, but I am sure that our friends in opposition cannot make fool of farmers.

I want to make certain suggestions. We have put ceiling on the holdings. I request that a limit on the property in urban areas should be put. A limit should be put on the income of big industrialists. The money accruing from these sources should be spent on improving the condition of village folk.

The prices of the produce of farmers are falling down, but the prices of those items which are not produced by him like iron and cloth are going up. The point should be looked into and the farmers should be provided the essential goods at cheap rates.

The daughter should have no share in the property of her father after marriage.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुनझनु) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाओं आदि की भी बात की है। परन्तु एक अत्यावश्यक वस्तु नमक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

इसका गांधी जी से सम्बन्ध नहीं है। गांधी जी ने नमक पर कर लगाये जाने का कड़ा विरोध किया था। इससे हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नयी प्रगति मिली थी। नमक सम्बन्धी सत्याग्रह का हमारे स्वतन्त्रता के संघर्ष में एक विशेष स्थान है। उस समय की सरकार ने नमक पर से फिर भी कर समाप्त नहीं किया। हां, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्वतन्त्र भारत की पहली सरकार ने नमक पर से कर समाप्त कर दिया था। परन्तु खेद की बात है कि इसे पुनः लागू कर दिया गया था। यह अब भी लागू है। इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिये। नमक से सम्बंधित सरकारी विभाग ने इसके विकास हेतु कोई कार्य नहीं किया है। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने गत बीस वर्षों में नमक पर उपकर के रूप में 45 करोड़ रुपये एकत्र किये हैं। आरंभ में यह कहा गया था कि इस प्रकार मिली राशि नमक सम्बन्धी कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण पर यह व्यय की जायेगी। हमारा उत्पादन का वार्षिक उत्पादन लगभग 55 लाख टन है और इस पर लगभग 2 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त नमक विशेषज्ञ समिति ने भी यह मत व्यक्त किया था कि नमक उद्योग का वैज्ञानिक ढंग से विकास नहीं हुआ है। सरकार के नमक विभाग को नमक निर्माताओं की सभी प्रकार से सहायता करनी चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नमक पर से उपकर हटा दिया जाये। नहीं तो इससे प्राप्त होने वाली राशि को नमक उद्योग में लगे मजदूरों के कल्याण के लिये प्रयोग में लाया जाना चाहिये। मजदूरों की मजूरी में वृद्धि की जानी चाहिये। इस उद्योग में वर्ष में केवल छः महीने काम होता है। शेष छः महीनों के लिये भी मजदूरों को कुछ दिया जाना चाहिये। कुछ राशि नमक की किस्म के सुधारने पर व्यय की जानी चाहिये।

अब मैं कुछ देश की सेना के बारे में कहना चाहता हूं। चीन के आक्रमण के समय हमारे सैनिकों को आवश्यक उपकरणों के बिना ही लड़ना पड़ा और हमारे देश को बहुत हानि उठानी पड़ी। हमें चीन तथा पाकिस्तान के बारे में सतर्क रहना है। सेनाओं को अच्छी तरह तैयार रखना चाहिये। हमें सेनाओं के लिये वस्त्र तैयार करने के लिये ऊन का आयात करना चाहिये। भारत के ऊन उद्योग को 32 करोड़ रुपये के आयातित ऊन की आवश्यकता होती है।

सरकार को सभी प्रकार के नियन्त्रण हटा देने चाहिये। वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण से किसी देश के विकास में सहायता नहीं मिली है। जापान और जर्मनी ने युद्ध के बाद वहां पर नियन्त्रण न होने के कारण प्रगति की है। अतः हमें भी सभी प्रकार के नियन्त्रण समाप्त कर देने चाहिये।

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur): It has been said in the President's Address that a new turn has come in the agricultural production. But I think that the required turn has not yet come. In this connection I would like to say that unless proper irrigational facilities, electricity at cheaper rates, good seeds and manures are not made available to the agriculturists the required targets of production cannot be achieved. Though there are controls of every type in our country but there is no control over cow-slaughter.

As far as tractors are concerned every agriculturist cannot make use of them. Tractors can be used only by big farmers who are the owners of large areas of land. Moreover the tractor parts are not available everywhere.

In my constituency the sub-soil water is very much and therefore the rivers there are of no use. Therefore tube-well should be installed there.

Just as peacock is our national bird similarly cow should be declared as our national animal. Only then we would be able to save our country.

I fail to understand why family planning is being enforced on Hindus only and not on Muslims. They are allowed to have four wives whereas a Government servant is not allowed to have a second wife. In this way a day will come when Hindus will be in a minority and our country will be in the hands of others. We could not protect our country even at the time of partition when there were 45 crore Hindus at that time in India. Nine crore Muslims who were in minority succeeded in getting partition. So, in case we come in minority how we would be able to safe guard the country. Therefore my submission is that if at all there is a need for family planning it must be enforced on all and not on Hindus alone. Hindus are the backbone of the country and if they become weak the whole country will become weak and then slave. Gandhiji used to say that we will form a casteless society but I feel that casteism is rather developing.

As far as the population is concerned it has increased in the case of Muslims and Christians. In the year 1951 the population of Muslims was 3,54,14,248 which increased to 4,63,29,557 i. e. there was an increase of one crore 15 lakhs 26 thousands two hundred and seventy-three. Similary the population of Christians increased by twenty four lakhs and four thousand. Now, I will tell you what are the reasons for that. Firstly, to some extent family planning is responsible for it. Secondly, Muslims and Christians are creating more children as compared to Hindus, and thirdly many people are being thrust by Pakistan towards our side so that they may form a majority and leave us in minority. Therefore we must be very much cautious about it. It is a matter of great regret that we are still following the policy of appeasement in order to secure their votes.

Now I would like to say something about national integration. There is no doubt that the unity of Muslims has been obtained. Majlise-Muslim has been formed. But our country is going towards partition. Majlise-Muslim wants to see that Hindus and Muslims part with each other. But I would like to submit that Harijans are part and parcels of Hindus. In case Harijans are separated from Hindus then Hindus will finish. They should not be met with any sort of injustice. Harijans should be treated at par with Hindus. They should not be separated from Hindus at any cost. I would not like to say much about national integration but would certainly submit that all barring Hindu Sabha, which is said to be the representative body of Hindus, were called in the conference. I would like to add that upto the time Hindu Sabha was representing, the country could not be divided. The history is the witness to this fact. A round table conference was held in the year 1930. At that time the country could not be divided. At the time of partition of the country Hindu Sabha was not given a chance to represent because congress said that we are the representative of Hindus. We are facing the same atmosphere even now. Shrimati Indira Gandhi had recently gone to Gorakhpur where she said that though Hindu Sabha is an old body but what can they do. So, in this connection I would like to ask if we cannot do anything for Hindus then who else can do anything for them ? Therefore I would like to say to everybody that we should be cautious from such persons who are prepared to divide the country and who are following the policy of appeasement to grind their own axe. In this connection I would also like to add that secularism in our country had failed the day this country was divided on two nation theory.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk): Sir, before saying anything on the President's Address I would like to submit that while mentioning the food problem of the country he did not say anything about the milk production. Five hundred million people of our country are in need of milk. Therefore in order to solve the problem of milk it is necessary for us to protect the cows and in order to protect the cows a legal ban should be imposed on cow-slaughter. In this connection I would like to say that a huge demonstration was held on 7th November, 1966 in front of Parliament House. Then out of fear the Government had appointed a Cow Protection Committee and had given a word to the people that cow-slaughter would be banned within three months. But it is a matter of great regret that the report of that committee has not yet been submitted. At the same time I would like to submit that three important members of that committee had resigned and therefore people are not prepared to accept the decisions of that committee. So, I would like to challenge the Government that if cow-slaughter is not banned then again a very strong movement will take place in our country.

If Congress Government want to remain in power for a pretty long time then they should follow the advice given by Babar to his son Humayun at the time of caronation that the feelings of the majority of the people, namely that cow-slaughter should be banned, should be respected.

Though the President had made a mention of communalism in the Address yet he had not defined it. In this connection I would like to submit that preparations are being made in Kerala and U.P. to create another Pakistan. Similarly seven lakh Pakistanies have infiltrated into Assam. I would also like to add that 1000 Pakistanies are entering Assam every month and our Government is unable to check them. The position of Kashmir is also very serious. A Hindu girl was abducted there on 5-8-1967. The Pandits, made huge demonstrations there but of no avail. Kohli Commission was appointed to go into the communal policy of Sadiq Government but its report has not yet been submitted. When the report is submitted only then the facts will come to light.

When Government cannot interfere with Muslim religion then they have no right to interfere with Hindu religion also. Only one type of code of conduct should be formed for the country. Instead of Hindu Code Bill, Hindustani Code Bill should be brought.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): After the achievement of Independence our country has made a lot of progress. There has been development and expansion of education. There has been an increase in production and a large number of new roads have been constructed. But we should not be complacent with it. I may submit that we have not made the expected progress. The speed with which Japan, Germany, Russia and China have made progress in the field of education and agricultural production etc. is much more than the speed with which we have made progress in our country. I would like to submit that merely by making declarations we cannot achieve much. We will have to keep before us a specified programme. Only then we would be able to give a new life to the down trodden. There is still illiteracy and unemployment in our country.

Our late lamented Prime Minister had said that the country is in dire needs of engineers and technicians. But today when they are available in plenty we have not been able to provide jobs for them. That is why I say that we have not made progress as we ought to have made. I feel that our problems can better be tackled by young persons than by the old ones.

We are seeing that a lot of changes have come out after fourth general elections. The political instability come out,and I think that this political instability is the result of our policies. People are trying to become leaders by taking the shelters of communal riots etc. In this connection I would like to submit that we do not mind if illiteracy is not removed from the country and if poverty remains as it is but we want to see that our country remains integrated.

Long time ago a demand was made that a canal should be made in Rajasthan so that the food problem may be eased thereby, but it is a matter of great regret that Rajasthan canal has not been included in the Plan even now.

In case we want to bring the backward areas at par with the developed areas then we must provide them with more financial facilities. Rajasthan is not developing democratically because we have not provided it financial facilities.

Our constitution had accepted Hindi as our national language. It was also said that Hindi will be put into practice within fifteen years. I agree with a member of D.M.K. that we should not think over the language problem from the political point of view but I am sorry to say that they themselves have made language a political basis.

No mention has been made in the President's Address about the development of Hindi. I would like the Centre and the State Government officers to take steps for the development of it.

It is a matter of great regret that 80 per cent people who are either tiller or run petty shops are not represented here.

श्री राजा राम (सलेम) : विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा था कि छोटे दुकानदारों का यहां प्रतिनिधित्व नहीं होता है परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारे दल में जो प्रतिनिधि हैं वे साधारण व्यक्तियों में से आये हैं और छोटे दुकानदार आदि हैं।

जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है मैं इस बात से तो सहमत हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल सिद्ध हो रहे हैं तथा हमारे तमिल नाडु में लोगों को उसके लिये पुरस्कार मिल रहे हैं। परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण तमिल नाडु में हमारी जनसंख्या कम हो गई है जिसके परिणामस्वरूप इस सभा में हमारे तीन प्रतिनिधि कम हो गये हैं। पश्चिम बंगाल ने इन कार्यक्रमों का अनुसरण नहीं किया तथा अधिक स्थान ग्रहण कर लिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु के लोग भी समझदार हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसे लाभ हो सकता है।

वे भी अधिक बच्चे पैदा करेंगे और इस प्रकार सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम ठप्प हो जायेगा। अतएव मेरी प्रार्थना है कि मद्रास से सभा में एक सीमा तक प्रतिनिधियों को भेजा जाय।

इसके अलावा और भी पहलू हैं। दिल्ली में दक्षिण भारतीय समाज कल्याण की एक सभा में श्री गोविन्द मेनन ने कहा है कि कलकत्ता केवल बंगालियों का ही नहीं है अपितु यह राष्ट्रीय शहर है। इसी प्रकार बम्बई, मद्रास आदि सब राष्ट्रीय शहर हैं। जहां तक केन्द्रीय मंत्री

का सम्बन्ध है यह तर्क ठीक लगता है वास्तव में मद्रास में हमें जल की कमी हो रही है और जब हम दूसरे राज्यों के पास जल के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि यह नदी हमारी है और इसमें से जल मत लो।

इस सम्बन्ध में मेरा केन्द्रीय सरकार से एक अनुरोध है। सरकार को चाहिए कि वह कानून बनाकर सब नदियों को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दे और यह देखे कि देश के महत्वपूर्ण शहरों को जल की सप्लाई हो रही है या नहीं। शहरों में गांवों के लोग रोजगार के लिए आते हैं तथा वहां उद्योग आदि स्थापित हो रहे हैं। अगर उनको जल न सप्लाई किया गया तो स्थिति विकट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इन बड़े-बड़े नारों का क्या तात्पर्य है ? मेरा अनुरोध है कि सब नदियों को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी जाये। अगर आप सिंचाई के लिए जल नहीं देते हो तो कम से कम शहरों में पीने के लिए जल तो उपलब्ध होना चाहिए।

मेरे राज्य की एक समस्या और है। यह कोयम्बतूर में कपड़े की मिलों से सम्बन्धित है। कोयम्बतूर में लगभग 29 मिलें बन्द हैं तथा 30,000 व्यक्ति बेरोजगार हैं। एक केन्द्रीय संगठन, जिसका नाम राष्ट्रीय कपड़ा निगम है, कुछ मिलों को अपने हाथ में ले लेने के लिए बनाई हैं। उनके पास 1 करोड़ रुपया है परन्तु उनके लिए यह सम्भव नहीं है कि वे इससे मिलों की सहायता कर सकें। मद्रास के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सूत पर से उत्पादन शुल्क को समाप्त कर दिया जाये। इस रीति से वे कम से कम कुछ मिलों को खोलना चाहते हैं। कपड़ा-मिलों के बंद होने से राज्य के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह इन सब पर नियंत्रण करे क्योंकि समस्त सीमा शुल्क आदि केन्द्र को मिलता है। राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहस के दौरान सब सदस्यों ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कहा है। जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ने भी कहा है कि "केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर फिर से देखने की आवश्यकता है।" हमारे दल का विचार है कि केन्द्र अपने हाथ में अधिक से अधिक शक्ति एकत्रित कर रहा है और राज्यों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। यह देश के लिए ठीक नहीं है। केन्द्र की शक्ति राज्यों की शक्ति पर आधारित है और यह तभी सम्भव है जब केन्द्र राज्यों को अधिक अधिकार दें केन्द्र को अधिक ध्यान प्रतिरक्षा पर देना चाहिए। केन्द्र की शक्ति आक्रमण का सामना करने में ही हैं न कि राज्यों को कमजोर बनाने में।

यह द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम का ही दृष्टिकोण नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के समय कांग्रेस दल भी संघीय प्रणाली की वकालत किया करती थी। तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री अन्नादुराई ने कहा था कि "संविधान के निर्माण के साथ नए विचार आए और हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। शिक्षा राज्य का विषय है परन्तु केन्द्रीय शिक्षा मंत्री राज्य के इस मामले में हस्तक्षेप करता है। इसी प्रकार उद्योग राज्य का विषय है। परन्तु केन्द्र लाइसेंस देता है और राज्य के पास कोई अधिकार नहीं रहता है।"

हम चाहते हैं कि अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक परिषद बनाया जाये । राष्ट्रपति को भी ऐसी परिषद बनाने का अधिकार प्राप्त है । जब केन्द्र तथा राज्य के मध्य नीति का समन्वय नहीं रहता अथवा इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है तो केन्द्र और राज्य के मध्य सम्बन्ध बनाए रखने के लिए विकल्प की आवश्यकता होती है । इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि आज केन्द्र और राज्य के मध्य वे सम्बन्ध नहीं है जो कि होने चाहिए ।

तमिलनाडु में हम इस्पात का कारखाना चाहते थे । इसी प्रकार आंध्र प्रदेश भी चाहता था । केन्द्र ने इस्पात कारखाना देने के बदले उनको इस्पात मंत्री दिया जो कि मैसूर से सम्बन्धित है । इस प्रकार वे दक्षिण वालों को धोखे में रख रहे हैं ।

मेरा दल केन्द्र के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहता है । हमारे नए मंत्री श्री करुणानिधि ने भी कोयम्बतूर में यही कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है । केन्द्र को भी राज्यों की ओर उचित ध्यान देना चाहिए तथा उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिए ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The address of the President shows the policies which the Government are likely to adopt in the next year. But it is surprising that there is no reference of solution of disputed matters.

A dispute regarding the boundary between Mysore and Maharashtra has been going on for the last so many years. Inspite of the coming out the Mahajan Report, there seems to be no solution in near future. Secondly, there is a Krishna, Godavari water dispute and Narmada water dispute between Madhya Pradesh and Gujarat. Some years back some decisions were arrived at but with no result. What I intend to say that the Government like to take the political advantage of all these problems.

I will give an instance which shows that the Government always hesitate in taking decisions. Sometimes back it was said that Hyderabad House would be converted to a residential place of the Prime Minister. Sometimes it is said that Nehru Museum of Teen-Murti House will be shifted to Vijai Ghat and the House will be converted to Prime Minister's residence. And sometimes it is said that a new house will be constructed in the area of Rashtrapati Bhawan. Such state of indecision does not indicate that the Government is sound and strong.

The Government have compiled articles on Gandhiji in connection with Gandhi Centenary Year. In one of the articles Gandhiji was given more importance than Mohammad Sahib. Some people at Cacutta raised objection on this. Now the Government are again publishing that book after removing that article. Such indecision State of mind will not benefit the Government.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Nowadays relations between Central Government and the Non-Congress Government are going to be strained. It was the news that the Punjab Government have decided to reinstate all those employees against whom the Central Government are taking judicial action. It is high time that the Central Government should take strong decision in this matter so that the relations between Centre and State may remain cordial.

It is my firm opinion that the establishment of unitary form of Government is the sole answer to all these disputes. The fall of S. V. D. Government had created an impression that the Congress would fair well in the mid-term election but the poll result have belied all hopes of the Congress. The Congress could not get absolute majority in any State. The Congress used to make slogan of stable Government. But today the defectors of her party, are running Government in Orissa and Madhya Pradesh.

I want to say to my friends belonging to Congress Party that while taking decisions, the consideration of the country should be placed above. The Congress has brought unstability in their attempt to stick to the Chairs. What has happened in Haryana Assembly ? If the Congress party wants to remain in power then it will be a curse for the country.

I was much felt when I came to know about the situation of West Bengal. Shri Dharma Vir, the Governor, himself wants to return as he is tired of the pulls, and pressure. When the Prime Minister visited Shanti Niketan to attend the convocation, she was asked about Shri Dharma Vir. She replied that no one had written about it. It mean the Prime Minister herself invited the trouble. She should have spoken straight away that the question of withdrawing him did not arise. The Governor is a representative of the President. If the Central Government starts calling back the Governors on the advice of the State Governments then the post of the Governor will lose its dignity and respect. The Central Government should examine all the situations before calling back the Governor. Only the advice of the state Government is not sufficient.

We are celebrating Gandhi-Centenary year. At least the Government should take firm decision regarding Prohibition and Hindi. They should not hang the question for an indefinite period. It is a pity that all the bills introduced in the House are in English language. I do not understand the objection of the Government in introducing bills in English and Hindi Language.

Some people have objection in the changing of time in the broadcasting of Hindi news bulletin I do not know what it makes difference ? It is not good that this issue may be given political colour. The Degree Colleges of Uttar Pradesh are closed for a month. The examinations are coming near. A deputation of teachers also met with Dr. Rao. Dr. Rao gave them assurance that he would look into the matter and ask the Uttar Pradesh Government to act upon the recommendation of University Grants Commission. I also request the Hon. Education Minister to remove the grievances of teachers.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मुझे आशा है कि इस नये उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक चलाने के लिये सब लोग मेरी सहायता करेंगे ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कई सदस्यों ने शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहा है । इस सम्बन्ध में संशोधन भी प्रस्तुत किये गये हैं । अतएव यह मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं इसके बारे में कुछ कहूं हालांकि इस सम्बन्ध में मेरा नई नीति बनाने का कोई निश्चय नहीं हैं ।

शिक्षा मंत्रालय के नाम के साथ-साथ युवक सेवा जोड़ने से सभा ने जो संतोष प्रकट

किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। यह इसलिये किया गया है क्योंकि आज विद्यार्थी और नवयुवक असंतुष्ट हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए युवक सेवा का होना बहुत आवश्यक है। मैं अभी देश में नवयुवकों की भलाई के लिये कार्यक्रम बनाने व नीति निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इस सम्बन्ध में अपने विपक्षी सदस्यों से बातचीत करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, कालेजों के प्रिंसिपल, विद्यार्थी संगठन के प्रतिनिधियों से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की जाएगी। मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि इसके लिये आयोग अथवा समिति को नियुक्त किया जाये। हमें इसके लिये कारणों को नहीं ढूढ़ना हैं अपितु ऐसा कार्यक्रम बनाना है जिससे इस समस्या को हल किया जा सके।

मैं इस समस्या के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह नहीं भूलना चाहिये कि स्कूल तथा कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत है और हमें उनकी शारीरिक शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसके लिये पर्याप्त कमरे, खेल के मैदान आदि होने चाहिये स्कूल या कालेजों का वातावरण ऐसा होना चाहिये जिसमें विद्यार्थी घुटा हुआ महसूस न करें। आप देखेंगे कि यह समस्या उन संस्थाओं में नहीं हैं जहां विद्यार्थियों की भलाई की ओर उचित ध्यान दिया जाता है तथा उनके लिये खुला वातावरण, खेल के मैदान आदि उपलब्ध कराये जाते हैं, परन्त रोग का कारण ढूढ़ना आसान होता है और उसका निदान करना कठिन। क्योंकि इसके लिये साधन एकत्रित करना कठिन होता है। इसमें मेरी भी जिम्मेवारी है और उतनी जिम्मेवारी इस सभा की भी है। आप सब जानते हैं कि देश में कितने संसाधन उपलब्ध हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति क्या है। मेरे कई विपक्षी दलों के मित्र कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार के सदस्य होने के नाते इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूं परन्तु विपक्षी दलों को भी इस कार्य में भाग लेना है।

यह समस्या एक ही दिन में सुलझ नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि स्कूल व कालेजों का अध्ययन किया जाये और यह बात जनता के सामने लाया जाये। कई स्कूल और कालेज ऐसे हैं जहां खेल के मैदान, कैन्टीन और विद्यार्थियों तथा विद्वानों के लिये कोई सहूलियतें उपलब्ध नहीं हैं, मेरे विचार में ये सब बातें प्रकाश में लानी चाहिये। हम यह देखेंगे कि सरकारी सहायता और जनता के सहयोग से इस स्थिति पर कैसे काबू पाया जा सकता है।

आज कई संस्थाओं में अध्यापक तथा विद्यार्थी का अनुपात संतोषजनक नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको अपनी ही आर्थिक कठिनाइयों की ओर से ध्यान हटाने को समय नहीं मिलता। हम यह भी जानते हैं कि कई संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हैं। यह भी सर्वविदित है कि कई संस्थाओं में शिक्षा देने की सुविधा अपर्याप्त है। हमें इन सब बातों को जानना होगा और इनको दूर करने के लिए समाधान ढूढ़ना होगा।

मेरे विचार में एक दो ऐसी बातें हैं जिनके लिये हम कुछ कर सकते हैं। वित्त तथा संसाधन

की भी एक सीमा होती है परन्तु इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह क्षेत्र विद्यार्थियों के मन में शैक्षणिक प्रक्रिया में भाग लेने से है। इंगलैंड जैसे रुढ़िवादी देशों को भी यह भान हो रहा है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में विद्यार्थियों का भाग लेना अति आवश्यक है। हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है ऐसा समाधान निकल आयेगा जिससे विद्यार्थी यह नहीं सोचेगा कि उसको केवल कुछ करने के लिये कहा ही जाता है अपितु शैक्षणिक प्रक्रिया में उसका भी हाथ है। इस समस्या पर विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कई विश्वविद्यालय निकाय भी इस पर विचार कर रहे हैं। अगर विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया गया तो कई अन्य समस्याओं का समाधान ढूढ़ने में आसानी रहेगी।

यह सर्वविदित है कि हम अपने कार्य द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है। अतएव यह हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम उदाहरण सही रूप में प्रस्तुत करें तभी इस समस्या का समाधान होगा। मेरे विचार में कई संस्थाओं का विद्यार्थियों की अपनी शिकायतें होती हैं परन्तु उनको दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम सब इस पर सहमत हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिये अध्यापक-विद्यार्थी परिषद का होना अति आवश्यक है। मैं कह नहीं सकता कि कितने कालेजों में इस प्रकार की व्यवस्था है। इस मामले पर हमें विचार करना चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और कालेजों में ऐसे किसी पर यह उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए जो विद्यार्थियों में फैली असंतोष की भावना का पहले ही पता लगा ले ताकि ऐसा न हो कि यह उग्र रूप धारण कर ले और हमें बाद में पछताना पड़े। कई विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों के डीन को नियुक्त किया है। मैं नहीं जानता की कालेजों ने इस सम्बन्ध में क्या किया है।

विद्यार्थियों के झगड़ों और शिकायतों की जांच करने के लिये और इस बात का प्रयास करने के लिये कि इनको किस प्रकार हल किया जा सकता है, कोई व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे देश में नवयुवक आदर्श-वाद के पुजारी हैं। हमारे देश में समाज-कार्य के बहुत अवसर हैं। इन नवयुवकों के लिये यदि सही मार्ग-दर्शन किया जाय, उचित वातावरण तैयार किया जाय तो ये नवयुवक अपनी शक्ति और लगन से सामाजिक कार्यों में योगदान देकर हमें चकित कर सकते हैं और यही इनकी आकांक्षा और जोश का सदुपयोग होगा।

बिहार में अकाल के समय और कोयना में भूकम्प के अवसर पर इन विद्यार्थियों ने बहुत शानदार काम किया है। आवश्यकता पड़ने पर ये विद्यार्थी पीछे हटने वाले नहीं हैं, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उनके लिये उचित अवसर प्रदान किये जायं। मुझे पूरा विश्वास है कि सामाजिक चेतना पैदा करना सम्भव हो सकेगा। हम जो राष्ट्रीय सेवा योजना बनाने जा रहे

हैं और उसको कालेजों में लागू कर रहे हैं, उससे हमें इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो जायेगी। गांधी शताब्दी वर्ष में हमें कुछ आदर्शों को प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

युवक सेवाओं के बाद में कुछ ठोस कार्य-क्रम तैयार करने के बाद मैं सभा में यह वक्तव्य दूंगा कि युवक सेवा विभाग क्या-क्या करेगा। इस कार्यक्रम के लिये अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध किये जायें। केवल आदर्शों से काम चलने वाला नहीं है, उनकी क्रियान्विति भी होनी चाहिये। युवकों और विद्यार्थियों के असंतोष की समस्या इस समय देश के सम्मुख सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है।

मेरे माननीय मित्र श्री बनर्जी ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत 7,000 शिक्षकों के बारे में कुछ कहा। मैं उस योजना के ब्योरे में नहीं जाना चाहता। मैं उनसे कह चुका हूं और पुनः कहना चाहता हूं कि यदि वह जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें सारी जानकारी देने के लिये तैयार हूं। जहां तक इस योजना का संबंध है, विकेन्द्रीकृत योजना अभी तक लागू नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था और शिक्षकों से यह पूछा गया था कि क्या वे राज्य योजनाओं में जायेंगे।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : हम और अधिक दायित्व नहीं ले सकते। हमारे पास धन नहीं है। इसलिये केरल सरकार ने इन्कार कर दिया है।

डा० वी० के० आर० वी० राव० : स्थिति यह है कि लगभग 7,000 शिक्षक हैं। ये सब केन्द्रीय राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन थे। ये सब लोग राज्यों में काम कर रहे हैं। 1965 में कुंजरू समिति के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की एक समेकित पद्धति लागू करने का निर्णय किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना की जाय। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच राज्य सरकारों द्वारा इन 7,000 व्यक्तियों को लेने के बारे में विचार-विमर्श हुआ। राज्य केन्द्र द्वारा दी जाने वाली धन की सहायता से संतुष्ट नहीं है। शारीरिक शिक्षकों ने राज्य सरकारों के अधीन आने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की है और राज्य सरकारें भी उन्हें अपने अधीन लेने के लिये तैयार नहीं हुई हैं। सारी बात अभी तक एक अनिश्चित स्थिति में है, परन्तु किसी भी व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाला गया है। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस समस्या को हल करने के लिये पूरी कोशिश करूंगा।

दूसरा उल्लेख उत्तर प्रदेश के कालेज अध्यापकों की हड़ताल के बारे में किया गया है। उत्तर प्रदेश के कालेजों के अध्यापकों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना की क्रियान्विति के बारे में कुछ कठिनाई आई है। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के सुझावों को स्वीकार करने के लिये तैयार है। परन्तु इन अध्यापकों की मांग इस समिति की सिफारिशों के दायरे से बाहर है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय।

Shri Prakash Vir Shastri : The U. P. Government have not even spent that amount on the teachers which was allocated by the Central Government. You should see to it that this amount is utilised for the purpose for which it is given.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार कालेज के शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने के लिये जो भी धन देगी, वह इसी कार्य पर खर्च किया जायगा ।

श्री बलराज मधोक : उत्तर प्रदेश के कालेजों के शिक्षक यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के अनुसार वेतनमानों में वृद्धि की जो योजना अन्य राज्यों ने स्वीकार की है, वह उत्तर प्रदेश के लिये भी लागू होनी चाहिये ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : वे उससे अधिक चाहते हैं ।

श्री शिव नारायण : यह 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये तक किया जाना चाहिये अथवा यह 800 रुपये तक किया जाय ।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : The Kashi Vidyapeeth, Varanasi has not received the full amount of the grant by the Government for the last several years as a result of which the teachers had to resort to strike for three months. What is the difficulty in giving the grant to Kashi Vidyapeeth, Varanasi ?

Secondly why the facilities of dearness allowance, etc. given to Centrally administered Universties are not being promoted to the teachers of Kashi Vidyapeeth. May I know the difficulties in this regard and the steps proposed to be taken by you to remove these difficulties.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Ramavtar Shastri : A delegation of teachers of Vidyapeeth has come here to meet you.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं उससे मिलने के लिये तैयार हूं ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनक्रम किस तारीख से लागू किये जायेंगे ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता । मैं मालूम करूंगा कि ये वस्तुत: किस तारीख से लागू होगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know how long will it take to arrive at a decision about giving an advance increment to every teacher in accordance with the assurance given by the Minister of Education and whether increased amount of 15 lakhs of rupees would be given in full or only one lakh rupees would be given ?

There is one other problem also. Six thousand students will seek admission in colleges while the admission capacity is limited only to 2,500 students. Would the Hon. Minister give an assurance that according to University conditions, all the eligible students would get admission ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न दिल्ली के शिक्षकों के पारिश्रमिक से सम्बन्धित है। मुझे इस प्रश्न के बारे में इस समय कोई जानकारी नहीं है। मैं सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करूंगा तथा माननीय सदस्य को तदनुसार सूचित करूंगा। शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद दिल्ली के शिक्षकों के दो प्रतिनिधिमण्डल मुझसे मिले हैं। वे अपने साथ हार इत्यादि लाये थे तथा एक शिक्षक के शिक्षा मंत्री बनने पर बड़े खुश थे। मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है तथा मेरे से कोई ऐसा प्रश्न न पूछा जाये जो पैसे से सम्बन्धित हो। हमने काफी मामलों पर जिसमें शिक्षा के स्तर में सुधार करना, क्षात्रों के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना तथा कई अन्य बातें शामिल हैं, बातचीत की थी। इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में जो कुछ आश्वासन दिये गये हैं, मै उन्हें देखूंगा तथा जो कुछ भी सम्भव होगा करूंगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं श्री कंवर लाल गुप्त को बहुत दिनों से जानता हूं और उन्होंने कालेजों की संख्या बढ़वाने के लिए सराहनीय काम किया है। अधिक छात्रों को दाखिला दिलाने के लिए वे प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के उपकुल पति से मुलाकात करते रहे हैं। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने युवक पीढ़ी के हित के लिए सराहनीय काम किया है। वह मेरी बधाई के पात्र हैं। जहां तक इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं और अधिक कालेज खोलने को तैयार हूं, परन्तु इस सम्बन्ध में मुझे अपेक्षित जानकारी प्राप्त करनी है और और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तथा तत्पश्चात ही मैं कोई आश्वासन दे सकूंगा।

श्री बलराज मधोक : अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था के कार्यसंचालन की जांच करने के लिये श्री चिन्ना रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने सुझाव दिया है कि इस संस्था के कार्यसंचालन में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

जामिया मिलिया कालेज से तीन छात्रों को बिल्कुल मामूली कारणों पर निकाल दिया गया है। उन्होंने उच्च-न्यायालय में याचिकायें दाखिल की थीं तथा उच्च-न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को स्वीकार किया है। उन्हें केवल साम्प्रदायिक कारणों से कालेज से निकाला गया है। जामिया मिलिया एक केन्द्रीय संस्था है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली में ही इस प्रकार की घटनायें होती हैं तो अन्य संस्थाओं में क्या हाल होता होगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये गये तथा इस संस्था के आगामी वर्ष के आयव्ययक में भी कुछ धन की व्यवस्था की गई है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि माननीय सदस्य ने जिन सिफारिशों का उल्लेख किया है उनको अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्था के अधिकारियों से बातचीत किये बिना ही स्वीकार कर लिया गया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

मैं श्री बलराज मधोक का बहुत आदर करता हूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में हम दोनों साथ-साथ शिक्षक रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्होंने साम्प्रदायिकता सम्बन्धी जो प्रश्न पूछा है, यदि वह इस प्रश्न को लोक सभा में न पूछ कर निजी तौर पर पूछते तो अधिक अच्छा होता। साम्प्रदायिक मामले बहुत नाजुक होते हैं तथा उन्हें निजी तौर पर पूछा जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले की जांच करूंगा और उन्हें अपेक्षित जानकारी दूंगा।

अन्त में मैं एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। जब मैं योजना आयोग का सदस्य था, उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उसमें शिक्षा के लिये 1,210 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में इस राशि को घटा कर 809 करोड़ रुपये कर दिया गया है, हालांकि चौथी पंचवर्षीय योजना का कुल पूंजी परिव्यय लगभग उतना ही है जितना कि पहले थे। अतः शिक्षा के संसाधनों को सीमित कर दिया गया है। मैं इन सीमित संसाधनों से ही देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है कि यदि शिक्षा के लिये और अधिक धन की आवश्यकता होगी तो समूचा राष्ट्र मेरा साथ देगा।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) माननीय शिक्षा मंत्री ने अभी जो भाषण दिया है, वह एक प्रकार से दीक्षांत भाषण था। यद्यपि इस वर्ष गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तथापि उन्होंने अपने भाषण में बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी के विचारों का कोई उल्लेख नहीं किया है। काश्मीर में हुए राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन में पब्लिक स्कूल तथा मांटेसरी अथवा प्राथमिक पाठशालाओं के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था। वास्तव में राष्ट्रीय एकता शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर ही भंग की जाती है। हमारे स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही सामाजिक असमानता आरम्भ हो जाती है। अतः पब्लिक स्कूलों को समाप्त किया जाना चाहिए।

मुझे श्री शंकर राव देव का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने लिखा है कि स्वतन्त्रता के बाद भारतीय उद्योगों में ब्रिटिश पूंजी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने यह पत्र सब संसद सदस्यों को भेजा है तथा यह निवेदन किया है कि दलगत भेद भावों को भूल कर सब संसद सदस्यों को मिल कर इस विदेशी पूंजी को राष्ट्रीय पूंजी में परिवर्तित करना चाहिए। हमें स्वतन्त्र हुए 20 वर्ष हो गये हैं, परन्तु हमारी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी ओर पूंजिपतियों की पूंजी बढ़ रही है। हमारे देश में ब्रिटिश पूंजी बढ़ रही है तथा विदेशी पूंजी बढ़ रही है। यह खेद की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि समाजवादी समाज की स्थापना की जायेगी। चूंकि

हमारे मन्त्रिमण्डल में राजे-महाराजे विद्यमान हैं, इसलिए निजी थैलियों के प्रश्न को भी अछूता छोड़ दिया गया है, यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह स्वीकार किया था कि निजी थैलियों को समाप्त किया जाना चाहिए। इस सभा में भी कई बार कहा गया है कि भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया जायेगा, तथापि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या यही समाजवादी समाज है ? गत बीस वर्षों में गरीब व्यक्ति और गरीब हो गये हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। विदेशी पूंजी बढ़ रही है। राजाओं तथा महाराजाओं को निजी थैलियां मिल रही हैं और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इन सब बातों के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिये मैं उनके अभिभाषण का विरोध करता हूं।

इस सरकार के विरुद्ध हमारी कुछ शिकायतें हैं। कल मेरे माननीय मित्र श्री शिव नारायण ने पश्चिम बंगाल के राज्य के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं थी। माननीय राष्ट्रपति ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के साथ हमारे सम्बन्धों का उल्लेख करना बिल्कुल भूल गए हैं। बिटिश राष्ट्रमण्डल में हमारी स्थिति क्या है ? हमारी प्रधान मंत्री लंदन गई थीं तथा उन्होंने कई मामलों पर विचार-विमर्श किया था, परन्तु वह एक भी संकल्प प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रही है। रोडेशिया के मामले को ताक पर रख दिया गया है। रंग भेद की नीति के बारे में एक भी संकल्प नहीं लाया गया। राष्ट्रमण्डल में रहने का हमें क्या लाभ है ? राष्ट्रमण्डल में रहने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ है। यह हमारे लिये शर्म की बात है कि भारत आज भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। हमें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को छोड़ देना चाहिए और सरकार को इस बारे में नये सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए।

जहां तक विघटनकारी शक्तियों का सम्बन्ध है, यह सच है कि देश में विघटनकारी शक्तियां सिर उठा रही हैं। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी का कहना है कि यह देख कर उनका दिल जलता है कि दामोदर घाटी निगम एक केन्द्रीय परियोजना है और नागार्जुन सागर एक राज्यीय परियोजना है। श्री वी० पी० नायक महाराष्ट्र में गन्ना पेरने के अधिक कारखानें स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की बार-बार मांग करते रहे हैं। तमिलनाड सरकार तथा केरल सरकार भी इस प्रकार की मांग करती रही है। परन्तु यह सरकार इन मांगों को अस्वीकार करती रही है। यह सरकार उत्तर भारत के बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ में है। आसाम एक पिछड़ा हुआ राज्य है तथा इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कच्चा तेल, कोयला और अन्य खनिज धातुओं की भरमार है, परन्तु गत बीस वर्षों में आसाम के प्रति भारत सरकार ने उचित व्यवहार नहीं किया है। श्री हेम बरुआ ने यहां तक कहा है कि यदि आसाम के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया गया तो आसाम भारत को छोड़ देगा। ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। बम्बई में शिव सेना ने जो हिंसक घटनायें की हैं, उनको भी हमें इसी पृष्ठ भूमि में देखना है। हम सब संसद सदस्यों ने संविधान में निष्ठा की शपथ ली है तथा हमें ऐसी गैर-जिम्मेदार बातें नहीं कहनी चाहिए कि यदि आसाम के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, तो आसाम भारत को छोड़ देगा। यह केवल आसाम का प्रश्न नहीं है, अपितु सभी राज्यों का प्रश्न है। जब केरल केन्द्रीय सरकार से चावलों की

मांग कर रहा था, तथा केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया तो क्या केरल को भारत से अलग हो जाना चाहिए था ? जब बंगाल को उड़ीसा से चावल खरीदने की केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नही दी गई, तो क्या बंगाल को भारत से अलग हो जाना चाहिए था। ऐसी बातें करना घातक हैं। हमारा समाज प्रजातन्त्रात्मक है। हमें प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन करने चाहिए। सरकार से हमें लड़ना है, परन्तु प्रजातन्त्रात्मक आधार पर। सरकार से हमें अपने हक प्राप्त करने हैं और यदि सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है तो हमें इसे बदलना है। यह सरकार पूंजी- पतियों, जमींदारों, राजाओं तथा रानियों की सरकार है, हमें इसको बदलना है और इसके स्थान पर समाजवादी प्रजातन्त्र सरकार बनानी है।

Shri Shivpujan Shastri (Bikramganj) : Mr. Speaker, Sir, many Hon. Members have expressed their views on the President's Address, some of them have supported it, while others have opposed it. I would like to concentrate myself on three major problems i. e. poverty, planning and political situation.

So far as the history of poverty is concerned, Dada Bhai Naoroji was the first man who wrote a book entitled "Authority and British Rule in India" and tried to show how poor our country was. He had written in his book that the per capita income of an Indian was Rs. 4 per annum, which meant that the per capita income per day was less than 4 paise- Gandhiji also painted a very gloomy picture of poverty in India in his correspondence with Lord Irwin in 1931. He said that the per capita daily income in our country was only 6 paise. Recently our Finance Minister has said in reply to a question that our present per capita yearly income is Rs. 313, which proves that even today the per capita daily income of an Indian is less than one rupee. It is beyond imagination how a man can meet his two ends with this paltry amount. So it is our responsibility to eradicate poverty from our land.

Now the question arises as to who is responsible for this poverty. I do not agree that the fault lies with the Congress party alone. I think all the political parties are at fault in this regard. The main reason of our poverty is that in our society there are so many old traditions and superstitions. These old traditions and superstitions, are hampering our progress. We need a social revolution to eradicate them. If that is done, many of our problems will the solved. We have to create a feeling among our people that they are the masters of their destiny. If that is done, they will rise and make progress. I do not agree that it is the responsibility of Congress alone to bring about this social change, but we all should make a combined effort to achieve this goal.

Now I come to the next point. So far as our Plans are concerned, a basic mistake has been committed. This fact has been ignored that India is an agricultural country and eighty to eighty five per cent of our population depends on agriculture. Due priority has not been given to agriculture in our plans. During the First Five Year Plan some priority was given to agriculture, but it was completely ignored during the Second Five Year Plan. Though there was food crisis during Third Five Year Plan even then agriculture was ignored in our Third Five Year Plan. Now during Fourth Five Year Plan it is proposed to give top priority to agriculture. If the agriculturist is given proper facilities of irrigation, fertilizers, pesticides and better seeds he can raise his farm production many fold. But the difficulty is that there are no irrigation facilities. At present 32 crore acres of land is under plough in our country,

but irrigation facilities are available in 8 crore acres of land only. Keeping this in view our plans should be so formulated that top most priority should be given to agriculture, so that our farm production may be increased. We should be self sufficient in food. It is not difficult to raise necessary resources required for the development of agriculture. Sant Vinoba Bhave has shown us the easiest path of raising resources. If we follow his foot steps then in every village, how small that may be, we can easily get Rs. 2,000 to Rs. 3,000 and this capital can be invested for the development of agriculture. We should not be dependent on foreign assistance, but we should be self ralient. Shri Vinobo Bhave has shown us the necessary path and we should follow that.

Now so far as mid-term elections are concerned it has been seen that voters have been exploited. Their sentiments has been raised. A feeling of casteism was created among them. They were subjected to intimidation and what not. They were threatened and prevented from casting their votes. When such tactics were adopted, how it could be said that the elections were democratic. The fact is that the voters are losing their faith in democracy. Now they are of the view that no party is going to look after their interests. These elections are being constituted by the political parties for their self interest. This is a very dangerous trend of thinking for our democracy. So I would appeal to all Hon. Members that we should establish healthy conventions and create a proper atmosphere for our democracy.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
29वां प्रतिवेदन

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर) : मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रीय समस्याओं की ओर जिनमें कृषि तथा उद्योग मुख्य हैं हमारा ध्यान दिलाया है। कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है और हमारे उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

विगत काल में सूखे तथा बाढ़ों के कारण बहुत हानि हुई है। आसाम, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात में प्रत्यकारी बाढ़ें आईं तथा राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। इनके परिणामस्वरूप हमारा कृषि उत्पादन घटा है और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है। आसाम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। अत: मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र आयोग का तुरन्त गठन किया जाना चाहिये।

भारत के लोग प्राचीन काल से सिंचाई करते रहे हैं, परन्तु यह खेद की बात है कि 20वीं शताब्दी में भी देश में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। गत सत्र में पूछे गये प्रश्न के

उत्तर में दिये गये एक विवरण से पता चलता है कि आसाम राज्य में एक इंच लम्बी नहर भी नहीं है, जबकि अन्य राज्यों में नहरों की लम्बाई 2000 से 13000 मील तक है ।

कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उर्वरकों की बहुत आवश्यकता होती है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि चालू वर्ष में कुछ उर्वरक कारखाने चालू किये जायेंगे । परन्तु वास्तविकता यह है कि अभी तक हम उर्वरकों का विदेशों से आयात करते हैं और उस पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं । हमें उर्वरकों का आयात न करके मशीनों आदि का आयात करना चाहिये और देश में उर्वरक कारखानें स्थापित करने चाहिये ।

जहां तक कृषि सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न है, कृषि सम्बन्धी सुधार अभी तक केवल कागजों पर ही किये गये हैं । यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिये, अन्यथा नक्सलबाड़ी जैसी घटनायें होंगी ।

कृषि के साथ-साथ उद्योग का भी देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है । हमारे उद्योग कृषि-आधारित अथवा कृषि प्रधान होने चाहिये । हमारे देश में ऐसे उद्योगों की बहुत गुंजाइश है । ऐसा करने पर नगरीय अथवा देहाती अर्थ व्यवस्था का अन्तर भी कम हो जायेगा ।

हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुछ खामियां हैं । उन्हें दूर किया जाना चाहिये । आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 30,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है । इस पूंजी से हमें कम से कम 300 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष लाभ होना चाहिए परन्तु हमें प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । महाप्रबन्धकों तथा प्रबन्धक निदेशकों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जानी चाहिये, न कि किसी अन्य आधार पर ।

उद्योगों के सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ स्थानों पर उद्योगों के केन्द्रीय-करण से क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। हाल में तेलंगाना में तथा अन्य स्थानों पर जो उपद्रव हुए हैं, उनका कारण क्षेत्रीय असंतुलन ही है । क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होना चाहिये । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गत 21 वर्षों में गोहाटी तेल शोधक कारखाने और नामरूप उर्वरक कारखाने को छोड़कर आसाम में और कोई कारखाना स्थापित नहीं किया गया है । यदि क्षेत्रीय असंतुलन इसी प्रकार कायम रहा तो यह कोई असंभव बात नहीं है कि लोगों में असंतोष फैल जायगा और उपद्रव होंगे ।

इस संदर्भ में मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं । आसाम में तेल के मूल्य अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक हैं । आसाम में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 1 रुपया 10 पैसे है, जबकि कलकत्ता में केवल 1 रुपया । संसार में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि किसी वस्तु के मूल्य अन्य स्थानों की तुलना में उस स्थान में अधिक न हों, जहां वह पैदा की जाती है । इस अन्याय को दूर किया जाना चाहिये ।

निरपेक्षता की हमारी नीति सही है परन्तु मित्रों का न होना हमारे लिये घातक है। हमारे ऐसे मित्र होने चाहिये जिन पर हम विश्वास कर सकें। हम इतिहास की अवहेलना नहीं कर सकते। नाजी जर्मनी रूस का मित्र था, परन्तु उसने ही रूस पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चीन हमारा मित्र था, परन्तु उसने हम पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। हमें इतिहास की इन घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिये।

राष्ट्रीय एकता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमारा देश एक बहुभाषी तथा बहुजातीय देश है। परन्तु इस सब के होते हुए भी भारतीय राष्ट्रीयता की भावना हममें मौजूद है। प्राचीनकाल में जबकि एक गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे, एक तालुक के लोगों के लिये दूसरे तालुक के लोग अजनबी होते थे, जातीयता की खाईं बहुत चौड़ी थी, उस समय भी हमारे अन्दर प्रादेशिकता अथवा साम्प्रदायिकता इतनी नहीं थी, जितनी आज है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि कुछ राजनीतिक दल अपने हितों के लिये लोगों की धार्मिक और प्रादेशिक भावनाओं को उभारते हैं। इन कारणों को दूर किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में उन लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिये, जिनकी लोकप्रियता प्रादेशिक अथवा जातीय भावनाओं को भड़काने पर निर्भर है। ऐसा करने से इन तत्वों को बल मिलता है। इसलिये राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को एक भिन्न दृष्टि से देखने की जरूरत है। हमारी प्राचीन संस्कृति में राष्ट्रीय एकता का सही स्वरूप विद्यमान है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भारत एक है, भारत के लोग एक हैं और हमें मन, वचन तथा कर्म से इस एकता को कायम रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : केवल दो मिनट बाकी हैं। श्री कछवाय अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Speaker, Sir, the President has not made any reference in his address to atrocities being committed on Harijans.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, there is no quorum in the House.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 26 फरवरी, 1969/7 फाल्गुन, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 26, 1969/Phalguna 7, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow 31-5-69—600.